भारत की भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग

जुलाई 2022

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सूची

कार्यपालक सार 6

विषय

1. पृष्ठभूमि.....10
2. विगत(पिछला)अभ्यास 10
3. वर्तमान अभ्यास.....11
4. आंकड़ों के स्रोत.....11
5. बेंचमार्किंग के लिए चुने गए देश 13
6. श्रेंणी निर्धारण (रेटिंग) 13
7. मुख्य-मुख्य बातें और भविष्य की राह.....14
8. बेंचमार्किंग अभ्यास का सारांश.....18

परिशिष्ट: शब्दावली 31

अनुबंध : बेंचमार्किंग का मूल्यांकन.....35

क. विनियमन.....35

1. मौजूदा क़ानून और विनियमन की व्यापकता 35
2. भुगतान प्रणाली लागत का विनियमन 37

ख. नकदी.....39

3. प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा (सीआईसी)..... 39
4. सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा 41

ग. भुगतान प्रणाली लेन-देन 43

5. भुगतान प्रणाली लेन-देन की मात्रा (परिमाण) और संवृद्धि 43
6. संचलन में मुद्रा के मुकाबले भुगतान प्रणाली लेन-देन का मूल्य 44

घ . चेक 45

7. चेकों में गिरावट की दर 45
8. भुगतान प्रणाली में चेकों का हिस्सा 46
9. चेक लिखत की विशेषताएं 47

च . डेबिट और क्रेडिट कार्ड 48

10. निर्गत (जारी किए गए) डेबिट और क्रेडिट कार्ड की संख्या 48

11. भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए भुगतान का हिस्सा (मात्रा).....49

12. बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल का अभिनियोजन 50

13. प्रति बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल व्यक्तियों की संख्या.....51

14. डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए भुगतान.....52

छ. नकदी बनाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए भुगतान.....53

15. डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए भुगतान बनाम संचलन में मुद्रा 54

ज. नकदी और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम).....54

16. अभिनियोजित (लगाए गए) एटीएम..... 54

17. प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या 56

18. एटीएम से प्रति व्यक्ति नकदी आहरण 57

19.संचलन में मुद्रा बनाम एटीएम आहरण 58

झ. घरेलू कार्ड नेटवर्क 59

20. घरेलू कार्ड नेटवर्क की उपस्थिति और इसका हिस्सा 59

ट. क्रेडिट अंतरण 61

21. क्रेडिट अंतरण की मात्रा और संवृद्धि 61

22. भुगतान प्रणाली में क्रेडिट अंतरण का हिस्सा (मात्रा).....62

ठ. बड़ी राशि के भुगतान 63

23. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस)..... 63

ड. तेज भुगतान 66

24. तेज भुगतान की उपलब्धता वाले चैनल....66

ढ . प्रत्यक्ष नामे (डायरेक्ट डेबिट)....68

25. सीधे नामे की मात्रा और संवृद्धि....68

26.भुगतान प्रणाली में सीधे नामे का हिस्सा (मात्रा).... 69

त. इलेक्ट्रॉनिक मनी (ई-मुद्रा)....70

27. वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की उपलब्धता....70

28. इलेक्ट्रोनिक मनी (ई-मुद्रा) की मात्रा और संवृद्धि 72

29. भुगतान प्रणाली में इलेक्ट्रोनिक मनी का हिस्सा (मात्रा)....73

थ . डिजिटल यूटिलिटी (उपयोगिता) भुगतान 74

30. यूटिलिटी बिल्स का डिजिटल भुगतान 74

31. सार्वजनिक जन परिवहन....75

द. डिजिटल बुनियादी अवसंरचना....78

32. मोबाइल और ब्रॉडबैंड अभिदान (सब्सक्रिप्शन)....78

ध. सरकारी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-पेमेंट)....80

न. एग्रीगेटर्स (समूहक)....80

33. अन्य पक्षकार भुगतान सेवा प्रदाता/भुगतान गेट वे/भुगतान एग्रीगेटर्स....80

प. ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण 83

34. ग्राहक संरक्षा और अधिप्रमाणन मानक....83

35. लोकपाल 87

फ. प्रतिभूति निपटान और समाशोधन प्रणाली 89

36. केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी)....89

ब. अन्वेक्षा (ओवरसाइट).....91

37. भुगतान प्रणाली की अन्वेक्षा.....91

भ. सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण.....92

38. उपलब्धता 92

39. प्रवाह.....94

40. लागत 95

कार्यपालक सार

विश्व भर का भुगतान परिदृश्य, विभिन्न नवोन्मेष भुगतान प्रणालियों और लिखतों को थोड़े-थोड़े अंतराल पर प्रस्तुत किए जाने के साथ तेजी से विकसित हो रहा है। भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क करने के इस अभ्यास का उद्देश्य अन्य प्रमुख देशों के समक्ष भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की प्रगति का मूल्यांकन करना और साथ ही भारतीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की शक्तियों और कमियों का पता लगाना है। इस अभ्यास में अन्य अधिकारिताओं के सापेक्ष भुगतान प्रणालियों और लिखतों हेतु प्रयोक्ताओं के अधिमान की जांच करने का प्रयास भी किया गया है। इस अभ्यास से मिली सीख से आशा है कि भारत के भुगतान परिदृश्य में और अधिक सुधार संभव होगा ।

2. भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क करने के लिए प्रायोगिक अभ्यास वर्ष 2019 में किया गया था। यह अभ्यास 21 देशों (उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स देशों - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित), के लिए आयोजित किया गया था, जहां भुगतान प्रणालियों को मजबूत, विविध और कुशल माना गया था। वर्तमान अभ्यास पिछली रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद बेंचमार्क किए गए देशों की प्रगति और वर्तमान सापेक्ष स्थिति की जांच करने के लिए किया गया एक अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर विश्वास जताया और यह सुनिश्चित करने हेतु सभी उचित प्रयास किए कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है। तथापि, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, अभ्यास में शामिल अधिकारिताओं से संबंधित डेटा/सूचना में यदि कोई परिवर्तन है तो वह यहां परिलक्षित नहीं होता हैं।

4. प्रत्येक संकेतक के लिए, उन देशों को ध्यान में रखते हुए रेटिंग की गई है जिनके संबंध में डेटा उपलब्ध था और केवल भारत को श्रेणीबद्ध (रेट) किया गया है। रेटिंग हेतु श्रेणियां इस प्रकार हैं:

क) "लीडर": पहली या दूसरी या तीसरी रैंक;

ख) "मजबूत": लीडर्स के अलावा शीर्ष आधे हिस्से के देशों में;

ग) "सामान्य": निम्नतम 5 देशों के अलावा निचले आधे हिस्से के देशों में; तथा

घ) "कमजोर": निम्नतम 5.

5. बेंचमार्किंग, 20 क्षेत्रों में और 40 संकेतकों की सहायता से की गई जैसा कि नीचे दिया गया है। भारत की स्थिति का एक आशुचित्र (स्नैपशॉट), जिसका ब्योरा रिपोर्ट में है, इस प्रकार है:

वर्तमान रेटिंग	संकेतक संख्या	संकेतक	क्षेत्र	पिछली रेटिंग
लीडर (नेता)	2	भुगतान प्रणाली की लागत का विनियमन	विनियमन	लीडर
	3	प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा	नकदी	मजबूत
	9	चेक लिखत की विशेषताएं	चेक	लीडर
	10	जारी किए गए डेबिट कार्ड की संख्या	डेबिट और क्रेडिट कार्ड	लीडर
	12	अभिनियोजित बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल	डेबिट और क्रेडिट कार्ड	मजबूत
	16	अभिनियोजित एटीएम	नकदी व एटीएम	लीडर
	18	एटीएम से नकदी आहरण प्रति व्यक्ति	नकदी व एटीएम	लीडर
	19	एटीएम आहरण बनाम संचलन में मुद्रा (सीआईसी ^)	नकदी व एटीएम	कमजोर
	21	क्रेडिट अंतरण की मात्रा व संवृद्धि *	जमा(क्रेडिट)अंतरण	मजबूत
	22	भुगतान प्रणाली में जमा अंतरण का हिस्सा (मात्रा)	जमा(क्रेडिट)अंतरण	लीडर
	23	तत्काल सकल निपटान (आरटीजी एस)	बड़े मूल्य के भुगतान	मजबूत
	24	तेज भुगतान की उपलब्धता वाले चैनल	तेज (फास्ट) भुगतान	मजबूत
	27	वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की उपलब्धता	इलेक्ट्रॉनिक मनी (ई-मुद्रा)	लीडर
	36	केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी)	प्रतिभूति निपटान और समाशोधन प्रणाली	मजबूत
	37	भुगतान प्रणाली की अन्वेक्षा	अन्वेक्षा (निगरानी)	लीडर
	39	सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण – प्रवाह	सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण	लीडर
मजबूत	1	मौजूदा क़ानून और विनियमन की व्यापकता	विनियमन	मजबूत
	5	भुगतान प्रणाली लेन-देन की मात्रा और संवृद्धि*	भुगतान प्रणाली लेन-देन	सामान्य
	10	निर्गत (जारी किए गए) क्रेडिट कार्ड की संख्या	डेबिट और क्रेडिट कार्ड	सामान्य
	25	सीधे नामे (डायरेक्ट डेबिट)* की मात्रा और संवृद्धि	डायरेक्ट डेबिट	कमजोर
	28	इलेक्ट्रॉनिक मनी (ई-मुद्रा)* की मात्रा और संवृद्धि	ई –मनी	मजबूत
	29	भुगतान प्रणाली में ई-मुद्रा का हिस्सा (मात्रा)	ई-मुद्रा	लीडर
	33	अन्य पक्षकार भुगतान सेवा प्रदाता/ भुगतान गेट वे/भुगतान एग्रीगेटर्स	एग्रीगेटर्स	सामान्य

	34	ग्राहक संरक्षा और अधिप्रमाणन मानक	ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण	मजबूत
	35	लोकपाल	ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण	मजबूत
	40	सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण –लागत	सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण	सामान्य
सामान्य	7	चेकों में गिरावट की दर	चेक	कमजोर
	14	डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान	डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स	सामान्य
	20	घरेलू कार्ड नेटवर्क की उपस्थिति और इसका हिस्सा	घरेलू कार्ड नेटवर्क	सामान्य
	26	भुगतान प्रणाली में सीधे नामे का हिस्सा (मात्रा)	सीधे नामे	कमजोर
	30	उपयोगिता (यूटिलिटी) बिलों का डिजिटल भुगतान	डिजिटल यूटिलिटी भुगतान	कमजोर
	31	सार्वजनिक जन परिवहन	डिजिटल यूटिलिटी भुगतान	कमजोर
	38	सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण –उपलब्धता	सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण	कमजोर
कमजोर	4	सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा	नकदी	सामान्य
	6	संचलनगत मुद्रा में भुगतान प्रणाली लेन-देन का मूल्य	भुगतान प्रणाली लेन-देन	सामान्य
	8	भुगतान प्रणाली में चेकों का हिस्सा (मात्रा)	चेक	कमजोर
	11	भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान का हिस्सा (मात्रा)	डेबिट और क्रेडिट कार्ड	कमजोर
	13	प्रति बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल व्यक्तियों की संख्या	डेबिट और क्रेडिट कार्ड	कमजोर
	15	डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान बनाम संचलनगत मुद्रा	नकदी बनाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड	कमजोर
	17	प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या	नकदी और एटीएम	कमजोर
	32	मोबाइल और ब्रॉडबैंड अभिदान (सब्सक्रिप्शन)	डिजिटल बुनियादी अवसंरचना	मजबूत

**मात्रा के अनुसार रेटिंग*

^पिछले अभ्यास के दौरान संचलनगत मुद्रा की तुलना में नकदी आहरण कम था और एटीएम की उपलब्धता कम होने के कारण संकेतक में भारत की रैंकिंग कमजोर थी। तथापि, एक समीक्षा पर, यह पाया गया कि डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ने पर ध्यान देने के कारण, संचलन में मुद्रा (सीआईसी) के सापेक्ष नकदी आहरण का कम अनुपात वांछनीय है। तदनुसार रेटिंग के औचित्य को आशोधित किया गया है।

6. पिछले अभ्यास के सापेक्ष वर्तमान अभ्यास दौरान रेटिंग श्रेणियों के मामले में भारत के कार्य-निष्पादन की तुलना नीचे दी गई है:

रेटिंग श्रेणियों के मामले में भारत का कार्य-निष्पादन				
	लीडर	**मजबूत**	**सामान्य**	**कमजोर**
वर्तमान अभ्यास	16	9	7	8
पिछला अभ्यास	10	11	7	11

सभी श्रेणियों में भारत की रेटिंग में परिवर्तन					
		वर्तमान अभ्यास			
		लीडर	**मजबूत**	**सामान्य**	**कमजोर**
पिछला अभ्यास	**लीडर**	9	1	0	0
	मजबूत	6	4	0	1
	सामान्य	0	3	2	2
	कमजोर	1	1	5	5

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने, विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं - व्यक्तियों, फर्मों, कॉरपोरेट्स, सरकार और अन्य आर्थिक एजेंटों के लिए समान रूप से उपलब्ध बहुविध भुगतान प्रणालियों और प्लेटफार्मों, भुगतान उत्पादों और सेवाओं के साथ, तीव्र विकास किया है। खुदरा भुगतान संवर्ग में भुगतान की नई प्रणालियों के प्रारंभ और स्वीकृति के साथ भुगतान परिदृश्य का विस्तार हुआ है, जिसमें (क) भुगतान करने और प्राप्त करने हेतु एक चैनल के रूप में मोबाइल फोन (मोबाइल भुगतान) (ख) विभिन्न प्रकार के डिवाइस (उपकरणों) पर खरीदारी करने के लिए इंटरनेट (इंटरनेट भुगतान), (ग) एटीएम/पीओएस पर संपर्क रहित प्रौद्योगिकी के उपयोग वाले कार्ड सहित भुगतान कार्ड (कार्ड भुगतान और टोकनाइजेशन) और (घ) तत्काल भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हेतु विभिन्न प्रणालियां और प्लेटफार्म, शामिल हैं । पिछले कुछ वर्षों में, ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए व साथ ही भुगतान प्रणालियों में विश्वास बनाए रखने के लिए भुगतान प्रणाली की विशेषताओं जैसे उपलब्धता, बार-बार किए जाने वाले भुगतान, संपर्क रहित भुगतान, ऑफ़लाइन भुगतान, टोकनाइजेशन आदि में अपेक्षित संरक्षा, सुरक्षा और दक्षता के उपायों को सुनिश्चित करते हुए काफी उन्नति की गई है।

1.2 बेंचमार्किंग अभ्यास भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना अन्य अधिकारिताओं के साथ करता है ताकि भारत में भुगतान परिदृश्य की स्थिति का पता लगाया जा सके और यह जांच की जा सके कि अन्य देशों की तुलना में इसका कार्यनिष्पादन कैसा है। इस संदर्भ में, भारत की भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग 2019 में शुरू की गई थी और यह अनुवर्ती अभ्यास उस प्रारंभिक अभ्यास के बाद से हुई प्रगति को मापने और भारत तथा विश्व दोनों में भुगतान के क्षेत्र में हाल की प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए किया जा रहा है।

2. पिछला अभ्यास

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019 में "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अन्य प्रमुख देशों की सदृश भुगतान प्रणालियों और उपयोग की प्रवृत्ति के सापेक्ष भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना की गई। इस अभ्यास में सभी महाद्वीपों के 21 देशों को (उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स देशों सहित) शामिल किया गया, जहां की भुगतान प्रणाली को मजबूत, विविध और कुशल माना गया । यह तुलना वर्ष 2012 से 2017 तक की 5 वर्षों की अवधि के दौरान संबंधित संकेतकों में हुई कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के मद्देनजर वर्ष 2017 के लिए की गई थी।

2.2 विश्लेषण में विनियमन, अन्वेक्षा, व्यक्तिगत भुगतान प्रणाली श्रेणियां, भुगतान लिखत, भुगतान अवसंरचना, उपयोगिता (यूटिलिटी) भुगतान, सरकारी भुगतान, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण, प्रतिभूति निपटान और

समाशोधन प्रणाली और सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण जैसे संकेतकों सहित, 21 व्यापक क्षेत्रों के 41 संकेतक शामिल किए गए ।

2.3 इस अभ्यास ने अन्य देशों के सापेक्ष भारत की भुगतान करने और प्राप्त करने की प्रणालियों की स्थिति और उनके प्रयोक्ताओं अधिमान की जानकारी प्रदान की। यह भारत की भुगतान प्रणालियों की कुशलता स्तरों के सार्थक विश्लेषण के लिए एक प्रारंभ बिंदु भी था।

3. वर्तमान अभ्यास

3.1 यह एक अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास है और इसका उद्देश्य बीस अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति, और साथ ही पिछले अभ्यास के बाद से सभी भुगतान प्रणालियों और भुगतान लिखतों में हुई प्रगति को मापना है। यह अभ्यास प्रयोक्ता अधिमान के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और अन्य देशों में सदृश (तुलनीय) भुगतान प्रणालियों के सापेक्ष भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत और कमियों की पहचान करने का प्रयास करता है। अतः यह अभ्यास (क) भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए भारतीयों के अधिमान की समझ और अन्य देशों के साथ ये अधिमान (प्राथमिकताएं) किस प्रकार तुलनीय हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने (ख) भारत की भुगतान प्रणालियों की दक्षता का मूल्यांकन करने और (ग) पिछले अभ्यास के बाद से मापदंडों (पेरामीटर) में हुई प्रगति को मापने का प्रयास करता है ।

3.2 इस अभ्यास में प्रयुक्त आंकड़े (डेटा) पिछले बेंचमार्किंग अभ्यास के बाद से तीन साल अर्थात 2017 से 2020 की अवधि में प्रासंगिक संकेतकों में हुई कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 के लिए हैं, (हालांकि वर्ष 2021 का डेटा जो भारत के लिए उपलब्ध है, वह अन्य अधिकारिताओं हेतु सार्वजनिक डोमेन (अनुक्षेत्र) में उपलब्ध नहीं है)।

3.3 पिछले अभ्यास में शामिल कुछ पैरामीटर उन प्रकाशनों पर आधारित हैं जिनके अनुवर्ती संस्करण जारी नहीं किए गए है। पिछले अभ्यास में प्रयुक्त गए मापदंडों को, अन्य उपलब्ध डेटा बिंदुओं का प्रयोग करते हुए, यथावत बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया गया । हालांकि, ऐसे मामलों में जहां डेटा बिंदु उपलब्ध नहीं हैं, मापदंडों को वर्तमान बेंचमार्किंग अभ्यास से बाहर रखा गया है।

3.4 देश में भुगतानों के डिजिटलीकरण के विस्तार को भलीभांति जानने के लिए भारत ने एक डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। डीपीआई कई मापदंडों पर आधारित है और विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियों की व्याप्ति और गहनता को मापता है। जबकि, डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का उपयोग देश भर में डिजिटल भुगतानों की गहनता को मापने के लिए किया जाता है, बेंचमार्किंग अन्य अधिकारिताओं के साथ एक सार्थक तुलना सुगम बनाता है।

4. आंकड़ों के स्रोत

4.1 बेंचमार्किंग अभ्यास के लिए विचार किए गए आंकड़ा (डेटा) स्रोत इस प्रकार हैं:

(ए) 2017 और 2020 को समाप्त वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक[1] (बीआईएस) द्वारा संकलित बीआईएस रेड बुक 'कंट्री टेबल'

(बी) वर्ल्डपे ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022[2]

(सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े (डेटा)

(डी) विश्व बैंक फास्ट पेमेंट टूलकिट[3]

(ई) विश्व बैंक हेतु संचालित ग्लोबल फाइंडेक्स सर्वेक्षण, 2017[4]

(एफ) विश्व बैंक - विश्व विकास संकेतक[5]

(जी) डीमिस्टीफाइंग टिकेटिंग एण्ड पेमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गतिशील (एडवाँसिंग) सार्वजनिक परिवहन रिपोर्ट - नवंबर 2020[6]

(एच) सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने पर एफएसबी स्टेज (चरण) 1 रिपोर्ट[7]

(आई) सीमा-पार भुगतान की चार चुनौतियों का समाधान करने हेतु लक्ष्यित वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की परामर्शदात्री रिपोर्ट[8]

(जे) एसीआई विश्वव्यापी - प्राइम टाइम फॉर रीयल-टाइम ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022[9]

(के) अन्य बेंचमार्क देशों के केंद्रीय बैंकों, लोकपाल, आदि की वेबसाइटें[10]

(एल) विभिन्न देशों में इंटरचेंज शुल्क: डेवलपमेंट्स एण्ड डिटरमिनेन्ट्स (गतिविधियाँ और निर्धारक तत्व) (स्टुअर्ट ई वेनर और जूलियन राइट)[11]

---

[1] एचटीटीपीएस://स्टेट्स.बीआईएस.ओआरजी/स्टेटएक्स/टीओसी/सीपीएमआई.एचटीएमएल
[2] एचटीटीपीएस://वर्ल्डपे.ग्लोबलपेमेंट्सरिपोर्ट.कॉम/एन
[3] एचटीटीपीएस://फास्टपेमेंट्स.वर्ल्डबैंक.ओआरजी/
[4] एचटीटीपीएस://ग्लोबलफाइंडेक्स.वर्ल्डबैंक.ओआरजी/
[5] एचटीटीपीएस://डेटाबैंक.वर्ल्डबैंक.ओआरजी/सोर्स/वर्ल्ड-डेवेलपमेंट-इंडिकेटर्स
[6] एचटीटीपीएस://सीएमएस.यूआईटीपी.ओआरजी/डब्लूपी/डब्लूपी-कन्टेंट/अपलोड्स/2021/03/रिपोर्ट-टिकेटिंग_एनओवी2020_अपडेट.पीडीएफ
[7] एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.एफएसबी.ओआरजी/2020/04/एन्हांसिंग-क्रॉस-बॉर्डर-पेमेंट्स-स्टेज-1-रिपोर्ट-टू-दि-जी20/
[8] एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.एफएसबी.ओआरजी/2021/05/टारगेट्स-फॉर-एड्रेसिंग-दि-फोर-चैलेंजेज-ऑफ़-क्रॉस-बॉर्डर-पेमेंट्स-कंसल्टेटिव-डॉक्यूमेंट/
[9]एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.एसीआईवर्ल्डवाइड.कॉम/रियल-टाइम-पेमेंट्स-रिपोर्ट?यूटीएम_सोर्स=फिनटेकफाइनेंसएंडयूटीएम_मीडियम=डिस्प्लेएण्ड यूटीएम_कैंपेन=एफएम-2022-बैंक्स-ग्लोबल-प्राइम-टाइम-2022
[10]एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.एएफसीए.ओआरजी.एयू;एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.फाइनेंसियल-ओम्बड्समैन.ओआरजी.यूके;
एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.ओबीएसआई.सीए;एचटीटीपीएस://एसीपीआर.बंक-फ्रांस.एफआर/एन/पेज-सोम्मैरे/अबाउट-एसीपीआर;
एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.बफिन.डे/ईएन/होमपेज;एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.ओबीएसएसए.सीओ.ज़ीए; एचटीटीपीएस://फिनओम्बड्समैन.आरयू/;
एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.ओसीसी.ट्रास.गोव/टॉपिक्स/सुपरविजन-एण्ड-एग्जामिनेशन/डिस्प्यूट-रेसोलुशन/कोन्सुमर-कंप्लेंटस/इंडेक्स-कोंसुमर-कंप्लेंट.एचटीएमएल
[11]एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लू डब्लू.केंसाससिटीफेड.ओआरजी/डाक्यूमेंट्स/7408/पीएससीपी2005_वेइनेर-राइट.पीडीऍफ़

(एम) खुदरा भुगतान 2012 में नवोन्मेष पर कार्यदल की रिपोर्ट[12]

(एन) प्रवसन और विकास पर वैश्विक ज्ञान भागीदारी (केएनओएमएडी) – धन प्रेषण आंकड़े (डेटा)[13]

4.2 भारिबैंक ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित प्रयास किए हैं कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी सटीक है। इसके अलावा, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, अभ्यास में शामिल अधिकारिताओं से संबंधित डेटा/सूचना में कोई भी परिवर्तन यहां परिलक्षित नहीं है।

5. बेंचमार्किंग के लिए चुने गए देश

5.1 सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए इस अभ्यास में वही देश शामिल हैं जो वर्ष 2019 के अभ्यास के लिए चुने गए थे । पिछले अभ्यास की तरह, शामिल देशों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और सभी ब्रिक्स देशों का मिश्रण है यथा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) को "विनियमन" और "अन्वेक्षा" संकेतकों के लिए शामिल किया गया है। इन देशों को न केवल इसलिए चुना गया है क्योंकि वे सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं बल्कि इसलिए भी कि इन देशों में भुगतान प्रणाली को मजबूत, विविध और कुशल माना जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश देश विश्व बैंक के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के अनुसार आय विस्तार (स्पेक्ट्रम) के ऊपरी छोर पर हैं।

6. श्रेणी निर्धारण (रेटिंग)

6.1 भुगतान प्रणालियों के विनियमन से लेकर भुगतान लिखतों और बुनियादी अवसंरचना तक के संकेतकों के लिए बेंचमार्किंग की गई है। किसी विशेष संकेतक की रैंकिंग के लिए, केवल उन देशों पर विचार किया गया है जिनके लिए संबंधित संकेतक के लिए आंकड़े (डेटा) उपलब्ध हैं । प्रत्येक संकेतक के लिए रेटिंग हेतु औचित्य, लीडर देशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के साथ अनुबंध में प्रदान किया गया है। रेटिंग[14] श्रेणियां पिछले अभ्यास में की गई रेटिंग की तर्ज पर ही हैं:

---

[12] एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.बीआईएस.ओआरजी/सीपीएमआई/पीयूबीएल/डी102.पीडीएफ
[13] एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.केएनओएमएडी.ओआरजी/डेटा/रेमिटेंसेस
[14] पिछले अभ्यास में रेटिंग की पद्धति निम्नवत थी:
(क)"लीडर": रैंक प्रथम या द्वितीय या तृतीय;
(ख) "मजबूत" :लीडर्स को छोड़ कर शीर्ष पायदान के देश (4थे से 9वाँ रैंक)
(ग) "समान्य ": मध्य में श्रेणीबद्ध (10 से 15वाँ रैंक)
(घ)"कमजोर": निम्नतम पायदान पर (16 से 21वाँ रैंक)

क) "लीडर": पहली या दूसरी या तीसरी रैंक;

ख) "मजबूत": लीडर्स के अलावा शीर्ष आधे हिस्से के देशों में;

ग) "सामान्य": निम्नतम 5 देशों के अलावा निचले आधे हिस्से के देशों में; तथा

घ) "कमजोर": निम्नतम 5.

6.2 किसी संकेतक के लिए रेटिंग अन्य संकेतकों के साथ सहसंबंध, यदि कोई हो, को ध्यान में लिए बिना दी गई है। एक मापदंड (पैरामीटर)/संकेतक के लिए 'रेटिंग' निर्दिष्ट करने का उद्देश्य इस अभ्यास के तहत शामिल देशों के सापेक्ष भारत की स्थिति को समझने के लिए एक पैमाना प्रदान करने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, कुछ मापदंडों के लिए, सापेक्ष स्थिति और उनकी रेटिंग बेंचमार्क देशों में उपभोक्ताओं के अधिमान (विभिन्न भुगतान वर्गों का हिस्सा, एटीएम से नकदी आहरण, आदि) को इंगित करती है। मापदंड/क्षेत्र जिनके लिए कोई अधिकारिता अपनी सापेक्ष स्थिति में सुधार के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना चाहती है, वह उसके भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, उपभोक्ताओं के अधिमान, भू-राजनीतिक वास्तविकताओं आदि के संदर्भ में उसकी मजबूती और कमियों से प्रेरित होगी । इस प्रकार, एक विशेष मापदंड में अपेक्षाकृत कम रैंकिंग कार्रवाई शुरू करने के लिए अपने आप में एक कारण नहीं हो सकता है।

7. मुख्य-मुख्य बातें और भविष्य की राह

7.1 बेंचमार्किंग अभ्यास ने भारत के भुगतान परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं की तुलना अन्य देशों के साथ की और अन्य देशों के सापेक्ष भुगतान लिखतों/प्रणालियों के लिए उपभोक्ताओं के अधिमान पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। कुछ मापदंडों के संबंध में सभी अधिकारिताओं में आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण मापदंडों का चयन बाधित रहा क्योंकि कुछ पहल / उत्पाद / प्रणालियाँ एक अधिकारिता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सभी अधिकारिताओं में लागू नहीं की जा सकती हैं, उदाहरणार्थ त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड का उपयोग। वर्ष 2019 के बाद से यह अभ्यास कुछ विकास कार्यों का साक्षी रहा है और इसने उन क्षेत्रों को उजागर करने में मदद की जहां भारत मजबूत था और उन क्षेत्रों की पहचान की जहां आगे की पहल/विकास वांछनीय थे। अभ्यास के प्रमुख निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

- कोविड 19 जनित महामारी आरम्भ होने और सामाजिक दूरी की आवश्यकता के कारण भुगतान प्रणालियों के निर्बाध परिचालन के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता पड़ी। चुनौतियों के बावजूद, भारतमें भुगतान प्रणाली ने महामारी के दौरान मजबूत संवृद्धि दिखाई।
- भारत में कई सक्रिय ग्राहक केंद्रित पहल किए जाने के साथ-साथ विनियमन मजबूत बना रहा। भुगतान एग्रीगेटर्स को भी विनियामक दायरे में लाने के लिए वर्ष 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए ।
- भारत में, जबकि प्रति व्यक्ति संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) कम है, सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) का अनुपात काफी अधिक है। भुगतान की व्यापकता का आकलन करने के लिए संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) एक कमजोर (उप-इष्टतम) संकेतक है, मुद्रा के रूप में विशेष रूप से उच्च मूल्यवर्ग के नोटों

का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और कोविड महामारी जैसी आपात स्थिति की अनिश्चितता के समय मूल्य संचय के रूप में भी किया जाता है।

- भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां बड़े मूल्य हेतु तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
- भारत में भुगतान प्रणाली/लिखतों (कागज समाशोधन को छोड़कर, जहां चेकों को कम करने का प्रयास किया जाता है) ने सभी खंडों में मजबूत संवृद्धि का प्रदर्शन किया है। भुगतान प्रणाली लेन-देनों में हिस्से के संदर्भ में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) प्रबल प्रणाली है, जिसने मार्च 2022 में 5.4 बिलियन से अधिक लेनदेन के साथ भुगतान प्रणाली लेन-देन 68% का योगदान किया है।
- भारत में तत्काल धन-हस्तांतरण की सुविधा देने वाली दो तेज़ भुगतान प्रणालियाँ नामतः तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और यूपीआई हैं। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा परिचालित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली 24x7 उपलब्ध है और आधे घंटे के बैचों में निपटान सुनिश्चित करती है।
- वर्ष 2020 में कोविड महामारी संबंधी लॉकडाउन और सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंधों का खुदरा दुकानों में भुगतान लिखतों के उपयोग पर असर पड़ा है । संभव है कि यह, वर्ष 2020 में भारत में अन्य भुगतान वर्गों की तुलना में कार्ड भुगतान में कम वृद्धि के कारणों में से एक कारण रहा हो। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान डिजिटल लेन-देन में प्रारंभिक गिरावट[15] के बाद वृद्धि हुई क्योंकि फोकस "नहीं / कम" शारीरिक संपर्क पर था।
- इस अवधि के दौरान भारत में भुगतान स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना में महत्वपूर्ण विस्तार के बावजूद, प्रति बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल पर लोगों की उपस्थिति लगभग 300 व्यक्ति के उच्च स्तर पर बनी रही । जनवरी 2021 में भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) के संचालनगत होने से भुगतान स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना के अभिनियोजन (तैनाती) में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारत में 150 मिलियन से अधिक डिजिटल बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल (क्यूआर कोड) हैं जो कार्ड, ई-मनी (इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा) और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- आरबीआई ने भुगतान प्रणाली संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी ढांचे के साथ वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस)[16] के लिए अद्यतन अन्वेक्षा फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है। यह इसके आगे भारतीय रिज़र्व बैंक की अन्वेक्षा के उद्देश्यों और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के साथ-साथ वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे हेतु सिद्धांतों (पीएफएमआई) के तहत वित्तीय बाजार अवसंरचना और प्रणाली व्याप्ति के रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसडब्ल्यूआईपीएस) के मूल्यांकन की पद्धति का ब्यौरा भी देता है।

[15] एचटीटीपीएस ://आरबीआई.ओआरजी.इन/स्क्रिप्ट्स/ट्रेंड्सपीएसआई यूज़रव्यू.एएसपीएक्स?आईडी=3

[16] एचटीटीपीएस ://आरबीआई.ओआरजी.इन/स्क्रिप्ट्स/बीएस_व्यूकन्टेंट.एएसपीएक्स?आईडी=3864

- भुगतान लेन-देनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में विभिन्न उपाय किए गए हैं। पिछले बेंचमार्किंग अभ्यास के बाद से वृद्धिशील उपायों में कार्ड लेनदेन को आरंभ/बंद करने/कार्ड लेन-देन के लिए उपयोग की सीमा, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफ), चेक लेन-देन के लिए सकारात्मक भुगतान (पॉजिटिव पे), उच्च मूल्य के लेन-देन के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) को अनिवार्य करना आदि शामिल है।
- भारत के डिजिटल भुगतान की दिशा में अग्रसर होने के साथ-साथ यह परिवर्तन भी आया है कि डिजिटल मोड से उपयोगिता (यूटिलिटी) बिलों का भुगतान होने लगा है। यह भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) द्वारा सुगम बनाया गया है, जिसने मार्च 2022 के अंत तक 20,000 से अधिक बिल बनाने वालों (बिलर्स) को जोड़ा है।
- जन परिवहन प्रणाली (मास ट्रांजिट सिस्टम) में टिकट खरीदने के लिए भुगतान तेजी से डिजिटल मोड के माध्यम से किए जा रहे हैं जिसमें संपर्क रहित कार्ड और क्यूआर आधारित भुगतान, पसंदीदा तरीके हैं।
- भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क –रुपे, कार्ड निर्गमन के मामले में डेबिट कार्ड सेगमेंट में प्रबल रहा है। हालांकि, वह क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में पिछड़ रहा है और कुल निर्गत क्रेडिट कार्डों में इनकी हिस्सेदारी 3% से कम है।
- हालांकि भारत में अभिनियोजित एटीएम की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, फिर भी बड़ी आबादी के कारण भारत का प्रदर्शन प्रति एटीएम सेवा प्रदत्त व्यक्तियों के मामले में खराब रहा है। हालाँकि, यह चिंता का विषय नहीं है क्योंकि भारत में नकदी आहरण की सुविधा अन्य चैनलों जैसे कि बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों और माइक्रो-एटीएम के माध्यम से आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ए-ईपीएस) का उपयोग करके भी प्राप्त की जाती है।
- भारत ने सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीमा-पार लेनदेन की सुविधा के लिए तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) की 24x7 उपलब्धता का लाभ उठाया जा सकता है।
- सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत की तीव्र भुगतान प्रणाली अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का अन्य अधिकारिताओं की सदृश प्रणालियों से अंतर-सहबद्धताओं का पता लगाया जा रहा है। वर्तमान में यूपीआई-पे नाउ इंटरफ़ेस सिंगापुर के साथ चल रहा है। इस तरह की पहल से धन-प्रेषण सहित सीमा-पार भुगतान के लिए एक त्वरित और कम लागत वाला विकल्प उपलब्ध होने की आशा है।
- डिजिटल भुगतान की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत में कई अन्य पहल की जा रही हैं। टोल-फ्री नंबर, वेबसाइट, चैटबॉट सुविधा आदि के माध्यम से डिजिटल भुगतान पर प्रश्नकर्ता प्रयोक्ताओं की सहायता के लिए एक उद्योग-व्यापी केंद्रीकृत 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना की गई । खराब या कमजोर इंटरनेट या कमजोर दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को किसी भी चैनल या लिखतों जैसे कार्ड, वॉलेट, मोबाइल

डिवाइस आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को समर्थ करने की अनुमति दी गई थी। देश भर में 400 मिलियन फीचर फोन प्रयोक्ताओं की डिजिटल समर्थता सुनिश्चित करने के लिए, यूपीआई सिस्टम का लाभ उठाते हुए डिजिटल भुगतान शुरू करने के लिए चार अलग-अलग विकल्पों उदाहरणार्थ (ए) इंटरएक्टिव वॉयस रिकॉर्डिंग, (बी) मिस्ड कॉल, (सी) ऐप-आधारित कार्यात्मकता, और (डी) निकटता ध्वनि-आधारित भुगतान के साथ यूपीआई123पे आरंभ किया गया । इसके अलावा, भुगतान स्पर्श बिंदुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग (भू-अंकन) के लिए हाल ही में निर्धारित फ्रेमवर्क वर्तमान भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की सटीक अवस्थिति बताएगा और देश भर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना को बढ़ाने के लिए लक्षित साक्षरता कार्यक्रमों और मध्यक्षेप कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। इन पहलों से डिजिटल भुगतान की और अभिस्वीकृत और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

भविष्य की राह

7.2 भारत में एक कुशल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे चौबीसों घंटे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) जिसमें तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) निहित हैं, के परिचालन से मजबूत किया गया है। 24x7 तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) ने बाजार के घंटों के विस्तार की नींव रखी है, जिससे भारतीय बाजारों की दक्षता बढ़ेगी और भुगतान लेन-देन में वृद्धि होगी। इसके अलावा, प्रमुख व्यापारिक मुद्राओं जैसे यूएसडी, यूरो, पाउंड, आदि में लेन-देन के निपटान हेतु आरटीजीएस के दायरे में विस्तार पता लगाया जा सकता है ताकि विदेशी मुद्रा लेन-देन के प्रसंस्करण की सुविधा मिले और भारत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो सके।

7.3 वैश्विक ध्यान सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने पर केंद्रित होने के साथ भारत के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में आगे की कार्रवाई का समन्वेषण करे, जिससे उसकी सापेक्ष स्थिति आगे बढ़ेगी और ऐसे लेन-देन में होने वाले टकराव दूर होंगे। इन उपायों में, यूपीआई-पे नाउ इंटरफेस का निर्माण करना और यूपीआई को अन्य अधिकारिताओं की तेज भुगतान प्रणालियों के साथ अंतर-सहबद्ध करने के रास्ते तलाशना, ग्राहक सुविधा में सुधार के लिए मुदा अंतरण सेवा योजना (मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम) के उपयोग द्वारा आवक धन-प्रेषण की निर्धारित सीमा को बढ़ाना/ की समीक्षा करना, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) फ्रेमवर्क में प्रदान की गई जोखिम-आधारित व्यवस्था के अनुरूप विदेशी आवक धन-प्रेषण के लिए विभेदक स्क्रीनिंग अपेक्षाएं अपनाना, आदि शामिल हैं। जबकि सीमा-पार लेन-देन को बढ़ाना एक फोकस क्षेत्र है, ऐसे लेन-देन की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। । भारत में ऑनलाइन कार्ड लेनदेन के लिए

अनिवार्य अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन (एएफए) ने भुगतान धोखाधड़ी को कम किया है और कार्ड लेन-देन में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाया है। प्रौद्योगिकी के विकास और सीमा-पार भुगतान में वृद्धि के साथ, भारत में जारी कार्ड का उपयोग करके किए गए सीमा-पार कार्ड लेनदेन के लिए अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन (एएफए) की अपेक्षा को लागू करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

7.4 घरेलू परिप्रेक्ष्य से, सुदृढ़ भुगतान अवसंरचना ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय संवृद्धि को सुगम बनाया है। इन सीखों का लाभ वैश्विक स्तर पर उठाने के लिए यह समय उपयुक्त है। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण से विदेशी व्यापार और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ तादात्म्य बनाए रखने में अधिक सुविधा होगी। अन्य वैश्विक लोकसंपर्क (आउटरीच) उपायों के साथ, यह धन-प्रेषण सहित सीमा पार लेन-देन की लागत को कम करने में सहायक होगा और भारतीय रुपये की तीव्र स्वीकृति में मदद करेगा। सतत सहसंबंधित निपटान (कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट) में भारतीय रुपये को मुद्रा के रूप में शामिल करना इस दिशा में एक कदम हो सकता है। भारतीय रुपये में व्यापारिक बीजक बन (ट्रेड इनवॉइस) बनाने और निपटान करने की सुविधा के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के सदस्य देशों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अन्य केंद्रीय बैंकों में चालू खाते खोलना, तीव्र निपटान की सुविधा के लिए विचारार्थ एक और पहलू हो सकता है।

8. बेंचमार्किंग अभ्यास का सारांश

क्षेत्र	संकेतक संख्या	संकेतक	अंतर्दृष्टि	पिछली रैंकिंग	वर्तमान रैंकिंग
(क) विनियमन	1	मौजूदा क़ानून और विनियमन की व्यापकता	भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन का दायरा संपूर्ण भुगतान प्रणालियों और लिखतों के साथ-साथ बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक विस्तृत है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास भुगतान प्रणाली पर एक निर्दिष्ट कानून है। भुगतान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, कुछ अन्य अधिकारिताओं के विपरीत, भारत में प्रचालको के प्रवेश और निकास को विनियमित किया जाता है।	**मजबूत**	**मजबूत**

	2	भुगतान प्रणाली की लागत का विनियमन	भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों अर्थात आरटीजीएस और अर्थात एनईएफटी लेनदेन पर प्रसंस्करण प्रभार माफ कर दिया गया है । इसके अलावा, 1 जनवरी, 2020 से बैंकों को निदेश दिया गया कि वे अपने बचत बैंक खाताधारकों द्वारा ऑनलाइन किए गए एनईएफटी निधि अंतरण पर कोई प्रभार न लगाएं। इसके अलावा, 1 जनवरी, 2020 से, सरकार ने निदेश दिया है कि एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और रु पे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) एकत्र नहीं किया जाएगा।	**लीडर**	**लीडर**
(ख) नकदी	3	प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा	भारत में प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा 2017 में 218 अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 288 अमरीकी डॉलर हो गई । हालाँकि, भारत में प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न होती है।	**मजबूत**	**लीडर**
	4	सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा	बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल देशों में से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा (सीआईसी) के संबंध में भारत का प्रतिशत तीसरा सबसे बड़ा है। वर्ष 2017 में भारत में संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10.7 प्रतिशत थी वह 2020 में बढ़कर 14.4% हो गई यह सभी अधिकारिताओं पाई गई प्रवृत्ति के अनुरूप ही है। कोविड 19 जनित महामारी के प्रारंभ से ही सभी अधिकारिताओं नकदी की कमी हो गई। भारत में गहन लॉकडाउन था, जिसके	**सामान्य**	**कमजोर**

			परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई और अन्य देशों के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट (डिनोमिनेटर) ने वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।		
(ग) भुगतान प्रणाली लेन-देन	5	भुगतान प्रणाली लेन-देन की मात्रा और संवृद्धि	वर्ष 2017 और 2020 के बीच भारत में भुगतान प्रणाली लेन-देन की मात्रा में 21% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से जोरदार वृद्धि हुई, जो गैर-नकद भुगतान मोड को तेजी से अपनाने का संकेत देती है। बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल देशों में भारत कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) केवल सऊदी अरब (26%) के बाद दूसरे स्थान पर थी ।	**सामान्य**	मात्रा : **मजबूत** सीएजीआर **लीडर**
	6	संचलनगत मुद्रा में भुगतान प्रणाली लेन-देन का मूल्य	बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल अन्य देशों की तुलना में वर्ष 2020 में संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में भुगतान प्रणाली लेनदेन का मूल्य का अनुपात भारत में सबसे कम (44.9) था। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2017 से 2020 के दौरान अनुपात में वृद्धि देखी है।	**सामान्य**	**कमजोर**
(घ) चेक	7	चेक में कमी की दर	भारत में, अन्य देशों की तुलना में वर्ष 2020 में चेक भुगतान (708 मिलियन)की मात्रा अधिक थी। भारत में चेक-आधारित भुगतान लेन-देन में वर्ष 2017 से 2020 तक 15.4 प्रतिशत की सीएजीआर से गिरावट आई है।	**कमजोर**	**सामान्य**
	8	भुगतान प्रणाली में चेकों का हिस्सा (मात्रा)	भारत में कुल भुगतान प्रणाली लेन-देन में चेक भुगतान की हिस्सेदारी जो वर्ष 2017 में 7.5% थी, वर्ष 2020 में घटकर 1.7% रह गई ।	**कमजोर**	**कमजोर**

	9	चेक लिखत की विशेषताएं	वर्ष 2021 में, भारत ने सभी बैंक शाखाओं को छवि (इमेज) - आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) समाशोधन तंत्र के तहत लाकर देश भर में सभी लिखतों के लिए टी+1 निपटान सुनिश्चित किया। इसके अलावा, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सभी उच्च मूल्य के चेक, अर्थात ₹ 50,000 से अधिक के लिए सकारात्मक भुगतान (पॉजिटिव पे) का एक तंत्र उपलब्ध कराया।	**लीडर**	**लीडर**
(च) डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स	10	निर्गत डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की संख्या	वर्ष 2020 के अंत में भारत 886 मिलियन डेबिट कार्ड के साथ, निर्गत डेबिट कार्ड्स की संख्या के मामले में केवल चीन (8178 मिलियन) से पीछे था। निर्गत क्रेडिट कार्डों की संख्या के मामले में, भारत, 60.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, कनाडा, कोरिया और तुर्की से पीछे था।	*डेबिट कार्ड्स:* **लीडर;** *क्रेडिट कार्ड्स:* **सामान्य**	*डेबिट कार्ड्स:* **लीडर;** *क्रेडिट कार्ड्स:* **मजबूत;**
	11	भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान का हिस्सा (मात्रा)	वर्ष 2020 में, भारत में कुल भुगतान प्रणाली लेन-देन में कार्ड भुगतान का हिस्सा दूसरा सबसे कम (14.7%) था, केवल इंडोनेशिया में इससे कम हिस्सेदारी (7.2%) देखी गई। इसके अलावा वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में इंडोनेशिया, कोरिया, स्वीडन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम के साथ कार्ड भुगतान के हिस्से में गिरावट के साक्षी कुछ देशों में भारत भी एक था।	**कमजोर**	**कमजोर**
	12	अभिनियोजित बिक्री केंद्र (पॉइंट ऑफ़ सेल) टर्मिनल्स	वर्ष 2020 के अंत तक भारत में उपलब्ध बिक्री केंद्रों (पॉइंट ऑफ़ सेल) टर्मिनलों की संख्या (4.6 मिलियन) थी जो ब्राजील (13.4 मिलियन) और चीन (38.3 मिलियन) को छोड़कर बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल अन्य देशों की तुलना में अधिक थी।	**मजबूत**	**लीडर**

	13	प्रति बिक्री केंद्र (पॉइंट ऑफ़ सेल) टर्मिनल्स व्यक्तियों की संख्या	भारत ने वर्ष 2020 के अंत तक अभिनियोजित पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनलों की समग्र संख्या के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, प्रति बिक्री केंद्र (पॉइंट ऑफ़ सेल) टर्मिनल्स व्यक्तियों की संख्या के मामले में, जो कि वर्ष 2020 के अंत तक 296 व्यक्तियों के लिए एक पीओएस टर्मिनल थी, में सुधार की गुंजाइश है।	**कमजोर**	**कमजोर**
	14	डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान	वर्ष 2017 से 2020 के दौरान भारत में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान क्रमशः 7.3% और 8.5% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ सम्मानजनक रूप से बढ़े हैं। हालांकि, समग्र रूप से, भारत में वर्ष 2020 में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की मात्रा अन्य देशों की तुलना में काफी कम थी।	**सामान्य**	**सामान्य**
(छ) नकदी बनाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड	15	संचलन में मुद्रा बनाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान	भारत में संचलनगत मुद्रा के सापेक्ष कार्ड भुगतान का मूल्य, 0.4 था जो बेंचमार्क देशों में सबसे कम था, यह डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के प्रति कम वरीयता का संकेत देता है।	**कमजोर**	**कमजोर**
(ज) नकदी और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	16	अभिनियोजित एटीएम	वर्ष 2020 के अंत तक, अभिनियोजित एटीएम की संख्या के मामले में भारत केवल चीन और रूस के बाद था। तथापि, वर्ष 2017 से 2020 के दौरान भारत में अभिनियोजित एटीएम की संख्या में रूस की 17% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की तुलना में 2% की सीएजीआर से वृद्धि हुई।	**लीडर**	**लीडर**
	17	प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या	बेंचमार्क देशों के बीच भारत में समग्र रूप से एटीएम की तीसरी सबसे बड़ी संख्या अभिनियोजित है। तथापि, जब हम एटीएम की पहुंच मापते हैं तो वर्ष 2020 के अंत तक 5800 से अधिक लोगों के लिए	**कमजोर**	**कमजोर**

			एक एटीएम के साथ यह प्रदर्शन कमजोर लगता है।		
	18	एटीएम से प्रति व्यक्ति नकदी आहरण	वर्ष 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति नकदी आहरण 5 था जो बेंचमार्क देशों में सबसे कम था । यह वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति नकदी आहरण 7 से गिर कर कम हुआ था। हालांकि यह अनुपात सामान्य रूप से कम नकदी निर्भरता को इंगित करता है, परन्तु यह कम अनुपात बड़ी जनसंख्या (डिनोमिनेटर) का एटीएम की कम संख्या (न्युमेरेटर) के कारण पहुंच कम होना हो सकता है। इसके अलावा, बिना किसी प्रभार के एटीएम से नकदी आहरण की सीमा है, जो कई बार एक निवारक के रूप में कार्य करती है।	**लीडर**	**लीडर**
	19	संचलन में मुद्रा बनाम एटीएम से आहरण	भारत में एटीएम से नकदी आहरण का संचलन में मुद्रा (सीआईसी) से अनुपात सबसे कम अनुपातों में से एक है। यह प्रति व्यक्ति एटीएम लेन-देन की कम संख्या के साथ-साथ कम एटीएम की सघनता कारण भी हो सकता है।	**कमजोर**[17]	**लीडर**
(झ) घरेलू कार्ड नेटवर्क	20	घरेलू कार्ड नेटवर्क की उपस्थिति और उसका हिस्सा	भारत में, घरेलू कार्ड नेटवर्क, रु पे को वर्ष 2012 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रारंभ किया गया था। जनवरी 2022 के अंत तक 651 मिलियन से अधिक रुपे डेबिट कार्ड निर्गत हो चुके थे जिनकी कुल कुल निर्गत कार्डों के 65% से अधिक हिस्सेदारी के कारण बाजार में उनकी प्रबल उपस्थिति थी। हालाँकि, रु पे कार्ड्स की भारत में क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में 3% से कम हिस्सेदारी है।	**सामान्य**	**सामान्य**

17 *पिछले अभ्यास में संचलन में मुद्रा (सीआईसी) के सापेक्ष नकद आहरण अनुपात कम था और एटीएम की कम उपलब्धता को देखते हुए भारत को इस संकेतक में कमजोर का दर्जा दिया गया था। हालांकि, एक समीक्षा पर यह पाया गया कि डिजिटल भुगतान की ओर अग्रसित होने पर ध्यान केंद्रित करने से, संचलन गत मुद्रा (सीआईसी) के सापेक्ष नकदी आहरण का कम अनुपात वांछनीय है। तदनुसार रेटिंग के औचित्य को संशोधित किया गया।*

क्षेत्र	संकेतक संख्या	संकेतक	अंतर्दृष्टि	पिछली रैंकिंग	वर्तमान रैंकिंग
(ट) जमा अंतरण	21	जमा अंतरण की मात्रा और संवृद्धि	वर्ष 2020 में जमा अंतरण लेन-देन की संख्या और वर्ष 2017 से 2020 के बीच 3 साल की अवधि में कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दोनों मामलों में भारत प्रबल है। इसका श्रेय चौबीसों घंटे प्रचुरता से उपलब्ध जमा अंतरण प्रणाली (क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम) को दिया जा सकता है, जिससे तत्काल निधि अन्तरण की सुविधा मिलती है।	**मजबूत**	**लीडर**
	22	भुगतान प्रणाली में जमा अंतरण का हिस्सा (मात्रा)	समग्र भुगतान प्रणाली लेन-देन में जमा अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर) की हिस्सेदारी वर्ष 2017 में 37.5% से बढ़ कर वर्ष 2020 में 68.8% हो गई और अब यह बेंचमार्क देशों में सबसे अधिक है।	**लीडर**	**लीडर**
(ठ) बड़े मूल्य के भुगतान	23	तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस)	भारत में, आरबीआई के स्वामित्व में और उसके द्वारा परिचालित आरटीजीएस प्रणाली को 2004 में आरंभ किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई बदलाव हुए हैं। यह प्रणाली 14 दिसंबर, 2020 से चौबीसों घंटे चल रही है; इसने भारत को विश्व के उन कुछ देशों में से एक बना दिया है, जहां बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली चौबीसों घंटे परिचालित होती हैं।	**मजबूत**	**लीडर**
(ड) तेज भुगतान	24	तेज भुगतान की सुविधा वाले चैनल	भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिसके पास दो तेज़ भुगतान प्रणालियां अर्थात आईएमपीएस और यूपीआई उपलब्ध हैं। भारत में तत्काल भुगतान को अपनाना उल्लेखनीय रहा है, इससे अन्य देशों की तुलना में भारत में तेज भुगतान प्रणाली का उपयोग करके किए गए लेन-देन की संख्या काफी प्रबल रही, जिसके लिए डेटा भी उपलब्ध है।	**मजबूत**	**लीडर**

			इसके अलावा, भारत में आरबीआई द्वारा परिचालित एक अन्य खुदरा भुगतान प्रणाली भी है, अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), जो यद्यपि एक तेज़ भुगतान प्रणाली नहीं है (क्योंकि इसमें निपटान आधे घंटे के बैचों में होता है), परन्तु यह बिना निपटान जोखिम के (लाभार्थी को भुगतान निपटान के बाद किए जाने के कारण) 24X7 चलती है।		
(ढ) सीधे नामे (डायरेक्ट डेबिट)	25	सीधे नामे की और संवृद्धि	वर्ष 2017 और 2020 के बीच 38.6% की सीएजीआर से भारत ने प्रत्यक्ष(सीधे) नामे (डायरेक्ट डेबिट) के मामले में बेंचमार्क देशों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, मात्रा के मामले में, भारत में डायरेक्ट डेबिट संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में कम है।	**कमजोर**	मात्रा : **मजबूत** कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर: **लीडर**
	26	भुगतान प्रणाली में सीधे नामे का हिस्सा (मात्रा)	भुगतान प्रणालियों में सीधे नामे लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में 2.5% थी। भुगतान प्रणालियों में सीधे नामे द्वारा भुगतान के हिस्से में बदलाव अधिकांश बेंचमार्क देशों के मामले में नगण्य है।	**लीडर**	**लीडर**
(त) ई-मुद्रा	27	वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की उपलब्धता	वर्ल्डपे ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में ऑनलाइन लेन-देन का 45% डिजिटल/ मोबाइल वॉलेट (ई-मनी) का उपयोग कर किए जाते हैं। भारत में, भुगतान का वैकल्पिक रूप, जो यूपीआई, अन्य-पक्ष एप्लिकेशन द्वारा सुगम किया गया है, का उपयोग मुख्य रूप से ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के लिए किया जाता है।	**लीडर**	**लीडर**

	28	ई-मुद्रा की मात्रा और संवृद्धि	भारत ने वर्ष 2020 में 4950 मिलियन से अधिक ई-मुद्रा लेन-देन के साथ ई-मनी लेनदेन की मात्रा के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये लेन-देन पूर्वदत्त भुगतान लिखतों का उपयोग करते हुए अनुमोदित बैंकों के साथ-साथ प्राधिकृत गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा निर्गत कार्ड या वॉलेट के रूप में किए जाते हैं।	**मजबूत**	मात्रा : **मजबूत;** सीएजीआर: **सामान्य**
	29	भुगतान प्रणाली में ई-मुद्रा का हिस्सा (मात्रा)	भारत में ई-मनी भुगतान लेन-देन की हिस्सेदारी जो वर्ष 2017 में 22.1% थी, वर्ष 2020 में घटकर 12.2% हो गई और यह हिस्सेदारी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है, उदाहरणार्थ जापान (78.8%), सिंगापुर (60.1%) और इंडोनेशिया (36.5%)।हिस्सेदारी में इस गिरावट को अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई में बढ़ोतरी के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।	**लीडर**	**मजबूत**
(थ) डिजिटल रूप में यूटिलिटी भुगतान	30	उपयोगिता (यूटिलिटी) बिलों का डिजिटल भुगतान	भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था ताकि ग्राहकों को बहुविधि मोड का उपयोग और भुगतान की तत्काल पुष्टि के लिए अंतर परिचालनीय (इंटरऑपरेबल) और सुलभ बिल भुगतान सेवाएं प्रदान की जा सकें। बिल बनाने वाले (बिलर्स) और प्रसंस्कृत लेन-देन के मामले में इस प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।	**कमजोर**	**सामान्य**
	31	सार्वजनिक जन यातायात	भारत के अधिकांश महानगरीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग किया जाता है। देश भर में चलने वाली मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड का उपयोग करती है जो संपर्क रहित नकदी मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।	**कमजोर**	**सामान्य**
(द) डिजिटल बुनियादी	32	मोबाइल और ब्रॉडबैंड	भारत में प्रति 100 व्यक्तियों पर मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन (अभिदान) की संख्या	**मजबूत**	**कमजोर**

अव-संरचना		(अभिदान) सब्सक्रिप्शन	वर्ष 2020 में सबसे कम क्रमशः 83.6 और 1.6 थी। इसके अलावा, वर्ष 2017 से 2020 की अवधि में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन 6.3% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़े जबकि इस अवधि के दौरान मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 1.4% की वार्षिकीकृत दर से कमी आई।		
(ध) एग्रीगेटर्स	33	अन्य पक्षकार भुगतान सेवा प्रदाता/ भुगतान गेट वे/भुगतान एग्रीगेटर्स	भारत ने हाल ही में भुगतान एग्रीगेटर्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश लाए हैं और सभी विद्यमान भुगतान एग्रीगेटर्स को 30 सितंबर, 2021 तक प्राधिकार हासिल करने हेतु आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। भारत में, भुगतान गेटवे की गतिविधियों को विनियमित नहीं किया जाता है क्योंकि वे निधियों का रख-रखाव नहीं करते हैं और विनियामक उनकी गतिविधियों के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी पर केवल अनुशंसात्मक दिशा-निर्देश जारी करता है। इसके अलावा, गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए एक फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है ।	**सामान्य**	**मजबूत**
(न) ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण	34	ग्राहक संरक्षा और अधिप्रमाणन मानक	भारत में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की देयता सीमित करने हेतु एक फ्रेमवर्क है। इसके अतिरिक्त, विनियामक ने ग्राहक लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पिछले अभ्यास के बाद से, विभिन्न उपायों की शुरुआत की है, उदाहरणार्थ (ए) कार्ड लेनदेन को प्रारंभ / बंद करने की सुविधा, (बी) कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकनाइजेशन, (सी) केंद्रीय भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) को अनिवार्य करना, (डी) उच्च मूल्य के	**मजबूत**	**मजबूत**

			चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली लागू करना ।		
	35	लोकपाल	भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2021 में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए एकीकृत लोकपाल योजना आरंभ की। एकीकृत लोकपाल योजना (आईओएस) ने निम्नलिखित तीन योजनाओं को संयुक्त किया है (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 इसके अलावा, एक तेज, प्रभावी और कुशल शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, 2019 में बड़े गैर-बैंक पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) के लिए एक आंतरिक लोकपाल योजना शुरू की गई थी।	**मजबूत**	**मजबूत**
(प) प्रतिभूति निपटान और समा-शोधन प्रणाली	36	केंद्रीय प्रतिपक्षकार (काउंटर पार्टी) (सीसीपी)	भारतीय समाशोधन निगम लि. (क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में काम करता है और मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और डेरिवेटिव (व्युत्पन्नी) बाजार में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान की सुविधा प्रदान करता है। बहुराष्ट्रीय (क्रॉस-कंट्री) तुलना में भारतीय समाशोधन निगम लि. संगठन के प्रबंधन हेतु विद्यमान शासन व्यवस्था और सदस्य के व्यतिक्रम (चूक) और अन्य गैर-व्यतिक्रम (नॉन डिफ़ॉल्ट) से हानि के प्रबंध हेतु लागू जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के संबंध में मजबूत कार्य करता है	**मजबूत**	**लीडर**
(फ) अन्वेक्षा (निगरानी)	37	**भुगतान प्रणाली की अन्वेक्षा (निगरानी)**	भारत में, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के आधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को देश के भीतर भुगतान प्रणाली को विनियमित और	**लीडर**	**लीडर**

			पर्यवेक्षित करने हेतु नामोद्दिष्ट और प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 2020 में भारिबैं ने वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणाली (आरपीएस) के लिए एक अन्वेक्षा(निगरानी) फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जो आरबीआई के निरीक्षण उद्देश्यों और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के साथ-साथ वित्तीय बाजार की अवसंरचना हेतु सिद्धांत (पीएफएमआई) के तहत वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और प्रणाली व्याप्ति के रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसडब्ल्यूआईपीएस) के मूल्यांकन की पद्धति का ब्यौरा भी देता है।		
(ब) सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण	38	**उपलब्धता**	भारत में, सीमा-पार प्रेषण का बड़ा हिस्सा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। गैर-बैंक प्रतिभागियों को केवल आवक प्रेषण की सुविधा की अनुमति है।	**कमजोर**	**सामान्य**
	39	**प्रवाह**	वैश्विक धन-प्रेषण के 11.85% हिस्से के साथ वैयक्तिक धन-प्रेषण अंतर्वाह के मामले में भारत लीडर (अग्रणी) है। भारत को वर्ष 2020 में 83 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि का धन-प्रेषण प्राप्त हुआ।	**लीडर**	**लीडर**
	40	**लागत**	भारत को धन-प्रेषण भेजने की लागत अन्य बेंचमार्क देशों की तुलना में कम थी। हालांकि, भारत से धन -प्रेषण भेजने की लागत रूस और सिंगापुर की तुलना में अधिक थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बेंचमार्किंग अभ्यास में चुने गए सभी देशों में धन-प्रेषण की तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि धन-प्रेषण मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उद्भव होते हैं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लाभार्थियों को निर्देशित होते हैं।	**सामान्य**	**मजबूत**

परिशिष्ट

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	परिभाषा
1	वैकल्पिक भुगतान	वैकल्पिक भुगतान (अल्टरनेट पेमेंट्स) वे भुगतान हैं जो नकदी या कार्ड ब्रांड नेटवर्क से जुड़े भौतिक कार्ड के अलावा अन्य तरीकों का उपयोग कर किए जाते हैं।
2	एटीएम	ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) ऐसे टर्मिनल हैं जो अधिकृत प्रयोक्ताओं को, आमतौर पर कार्ड का उपयोग करके, नकदी आहरण, शेष राशि की जानकारी, निधि अंतरण और/या जमा राशि की स्वीकृति जैसी सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराते हैं।
3	बिग टेक	बिगटेक शब्द उन कंपनियों के प्रयोग किया जाता है जो अपने संबंधित क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां है। उनके उत्पादों और सेवाओं का विश्व स्तर पर प्रयोग किया जाता है और व्यवसायों और व्यक्तियों की उन पर समान रूप से बहुत अधिक निर्भरता हो गई है।
4	बीएनपीएल	अभी खरीदें बाद में भुगतान करें (बाई नाउ पे लेटर) एक प्रकार का अल्पावधि वित्तपोषण है जो उपभोक्ताओं को खरीदारी करने और भविष्य की तारीख में उनके लिए, अक्सर ब्याज मुक्त, भुगतान करने की अनुमति देता है।
5	सीएजीआर	कंपाउंड (चक्रवृद्धि) वार्षिक वृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) वह औसत दर है जिस पर एक संकेतक का मूल्य एक समयावधि के दौरान एक मूल्य से दूसरे मूल्य पर जाता है।
6	कार्ड्स	कार्ड एक विशिष्ट संख्या आधारित भुगतान लिखत हैं जिसका उपयोग भुगतान करने, नकदी आहरण या नकदी जमा, जिसे कार्ड योजना पर/का उपयोग कर संसाधित किया जाता है या - एटीएम पर आहरण और जमा करने के लिए – कार्ड जारीकर्ता द्वारा संचालित नेटवर्क के भीतर, किया जाता है । इस अभ्यास के लिए, कार्ड का अर्थ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए
7	सीआईसी	संचलन में मुद्रा (सीआईसी) एक देश के अंदर नकदी की वह राशि है जो भौतिक रूप से उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच लेन-देन करने के लिए उपयोग की जाती है न कि किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या केंद्रीय बैंक में संग्रहीत की जाती है। इसमें संचलन में नोट और सिक्के शामिल हैं
8	चेक	चेक एक भुगतान लिखत है जो एक पक्ष (आहरणकर्ता, चेक काटने वाला) से दूसरे पक्ष (अदाकर्ता, आमतौर पर एक बैंक का खाता धारक) के लिखित आदेशों पर आधारित होता है और जिसमें अदाकर्ता से यह अपेक्षित होता है कि वह मांग किये जाने पर आहरणकर्ता को या उसके द्वारा निर्दिष्ट तीसरे पक्ष को एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करे ।
9	क्रेडिट ट्रान्सफर	जमा अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर) भुगतान आदेश या संभवतः आनुक्रमिक भुगतान आदेशों पर आधारित हैं, जो आदाता (पाने वाला) के निपटान में निधियां रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। निधियां, भुगतानकर्ता की संस्था से आदाता की संस्था में संभवतः मध्यस्थ के रूप में कई अन्य संस्थाओं और/या एक या अधिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से होती हुई अंतरित होती हैं। भारत में, इन प्रणालियों में

क्रम संख्या	शब्द	परिभाषा
		तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) क्रेडिट, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसी एच) क्रेडिट, त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) सम्मिलित हैं।
10	डिजिटल भुगतान	यह भुगतान का एक साधन है जो डिजिटल मोड में किया जाता है। डिजिटल भुगतान में, भुगतानकर्ता और आदाता (प्राप्तकर्ता) दोनों क्रमशः पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है। डिजिटल भुगतान में कोई नकद राशि (हार्ड कैश) शामिल नहीं होती
11	डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी) सीधे उनके खाते में अंतरित करना है।
12	डायरेक्ट डेबिट	प्रत्यक्ष नामे (डायरेक्ट डेबिट) आदाता द्वारा भुगतानकर्ता के खाते से पूर्व-अधिकृत संभवतः आवर्ती नामे (डेबिट) होते हैं। भारत में, इनमें ईसीएस डेबिट[18] और एनएसीएच डेबिट शामिल हैं।
13	डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क	कार्ड नेटवर्क, अधिग्राहक (प्राप्तकर्ता) बैंकों और जारीकर्ता बैंकों (या कार्ड निर्गमकर्ता) के बीच जानकारी साझा करके कार्ड भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। घरेलू (डोमेस्टिक) कार्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी विशिष्ट देश के बैंकों के लिए स्थापित सेटअप किया जाता है। भारत में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के रुपे कार्ड घरेलू कार्ड नेटवर्क के रूप में परिचालनगत हैं।
14	ई-मनी	इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा (ई-मनी) इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचयित पूर्वदत्त (प्रीपेड) मूल्य है, जो ई-मनी जारीकर्ता (एक बैंक, एक ई-मनी संस्थान या स्थानीय अधिकारिता (क्षेत्राधिकार) में ई-मनी जारी करने के लिए प्राधिकृत या अनुमत कोई अन्य संस्था) की देयता का प्रतिनिधित्व करता है और जो एक प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा समर्थित मुद्रा (करेंसी) में मूल्यवर्गित होती है । भारत में, वॉलेट और कार्ड के रूप में जारी पूर्वदत्त (प्रीपेड) भुगतान लिखत ई-मनी में आते हैं।
15	फास्ट पेमेंट	तेज भुगतान (फास्ट पेमेंट) ऐसे भुगतान हैं जिनमें भुगतान संदेश का प्रसारण और आदाता (प्राप्तकर्ता) को "अंतिम" निधि (धन) की उपलब्धता तत्काल या निकट-तत्काल समय होती है और यथासंभव रात दिन और सात-दिन (24x7) या सन्निकट आधार पर होती है। भारत में, आईएमपीएस और यूपीआई को फास्ट पेमेंट सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
16	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

18 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) जनवरी 2020 को उसके सभी लेन-देन राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) को स्थानांतरित करने के साथ, बंद कर दी गई।

क्रम संख्या	शब्द	परिभाषा
17	इंटरचेंज फी	परस्पर परिवर्तनीयता (इंटरचेंज) शुल्क एक लेन-देन शुल्क है जो एक व्यापारी को भुगतान करना होता जब भी कोई ग्राहक उसके अपने स्टोर से खरीदारी करने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग करता है। इस शुल्क का भुगतान कार्ड निर्गमकर्ता बैंक को रख रखाव (हैंडलिंग) लागत, धोखाधड़ी और अशोध्य ऋण लागत और भुगतान की स्वीकृति में निहित जोखिम को कवर (रक्षित) करने के लिए किया जाता है।
18	एमडीआर	व्यापारी मितीकाता दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) डेबिट / क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए एक व्यापारी से लिया जाने वाला प्रभार है।
19	माइक्रो एटीएम	माइक्रो-एटीएम एक सुवाह्य डिवाइस है जिसका उपयोग व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा अपने बैंक से संपर्क करने, ग्राहकों को अधिप्रमाणित करने और नकदी जमा, आहरण और निधि अंतरण जैसे लेन-देन करने के लिए किया जाता है।
20	एनएफसी	नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) वह तकनीक है जो दो उपकरणों (डिवाइसेस), जैसे फोन और भुगतान टर्मिनल को एक-दूसरे के करीब होने पर एक-दूसरे से संपर्क करने की अनुमति देती है। एनएफसी वह तकनीक है जो संपर्क रहित भुगतान को संभव बनाती है।
21	पेमेंट एग्रीगेटर्स	भुगतान (पेमेंट) एग्रीगेटर ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों को खुद की एक अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाए बिना ग्राहकों को उनके भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए विभिन्न भुगतान लिखतों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
22	पेमेंट गेट वे	भुगतान गेटवे ऐसी संस्थाएं हैं जो निधियों को संभाले बिना ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के लिए राह और प्रसंस्करण की सुविधा देंने हेतु प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करती हैं।
23	पीएसओ	भुगतान प्रणाली परिचालक (पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर) एक कानूनी इकाई है जो भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए उत्तरदायी होती है।
24	पेमेंट सिस्टम ट्रांसेक्शन	भुगतान प्रणाली लेन-देन (पेमेंट सिस्टम ट्रांसेक्शन) में देश की सभी भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किए गए कुल लेन-देन आते हैं। भारत में, इसमें शामिल हैं, (ए) कागजी समाशोधन (चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस), चुम्बकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर), गैर-माईकर); (बी) बड़े मूल्य (तत्काल सकल निपटान); (सी) खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस), राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी); (डी) तेज भुगतान (त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई); (एफ) कार्ड भुगतान (क्रेडिट और डेबिट कार्ड) और (जी) ई-मनी (इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा), (पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) कार्ड और वॉलेट)।
25	पर केपिटा	पर केपिटा (प्रति व्यक्ति) एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद 'सिर से' होता है और मूल रूप से इसका अर्थ है 'औसत प्रति व्यक्ति'।
26	पॉइंट ऑफ़ सेल	बिक्री केंद्र (पॉइंट ऑफ़ सेल) टर्मिनल ऐसे डिवाइसेस (उपकरण) होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर खुदरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से और - कुछ मामलों में - पेपर वाउचर पर भुगतान जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

क्रम संख्या	शब्द	परिभाषा
27	पीपीआई	पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) ऐसे भुगतान लिखत हैं जो उनमें संचयित मूल्य के समक्ष वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं।
28	रिटेल पेमेंट्स	खुदरा (फुटकर) भुगतान निजी व्यक्तियों, कंपनियों, सरकारी एजेंसियों के बीच "रोजमर्रा" के-अपेक्षाकृत कम मूल्य के-भुगतान हैं। उदाहणार्थ खुदरा भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं या उपयोगिता (यूटिलिटी) या दूरसंचार (सेवा) प्रदाताओं को किया जाता है। व्यवसायों द्वारा किए गए वेतन भुगतान, कर भुगतान और सामाजिक योगदान संबंधी भुगतान भी इसी श्रेणी में आते हैं।
29	आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) एक निधि अंतरण प्रणाली है जहां पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में 'रियल-टाइम (वास्तविक समय)' में और ग्रॉस आधार पर अंतरित किया जाता है। आरटीजीएस भारत की बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली (एलवीपीएस) है जो आम तौर पर बड़े मूल्य और उच्च प्राथमिकता वाले भुगतानों को संभालती है।
30	क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड एक दो-आयामी बार कोड का प्रकार है जिसमें एक सफेद पृष्ठभूमि पर एक वर्ग ग्रिड में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। इन कोड को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए स्मार्टफोन कैमरों जैसे इमेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए ऐप-आधारित भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

अनुबंध

बेंचमार्किंग मूल्यांकन

क. विनियमन

1. मौजूदा क़ानून और विनियमन का दायरा

1.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन का दायरा भुगतान प्रणालियों और उपकरणों (डिवाइसेस) के पूरे विस्तार के साथ-साथ बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक व्यापक है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास भुगतान प्रणाली पर एक निर्दिष्ट कानून है। भुगतान प्रणालियों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, कुछ अन्य अधिकारिताओं से अलग, भारत में परिचालकों के प्रवेश और निकास को विनियमित किया जाता है।

1.2 बेंचमार्क रेटिंग : मजबूत

1.3 विश्लेषण : एक सुदृढ़ और उपयुक्त कानूनी ढांचे को सामान्यतया एक प्रभावशाली भुगतान प्रणाली का आधार माना जाता है। भारत में, भुगतान प्रणालियों के विकास और व्यवस्थित कार्यपद्धति हेतु विनियमन का महत्व स्वीकार करते हुए, वर्ष 2007 में भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम बनाया गया। भुगतान प्रणालियों के विनियमन का कानूनी आधार भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 से निकलता है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी होगा । इसके विनियमन के सामान्य अधीक्षण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति उत्तरदायी है, जो इस कार्य (टास्क) को दिए गए महत्व को दर्शाता है।

संरक्षा और ग्राहक केंद्रित पहल के साथ सक्रिय विनियमन, खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास की उत्कृष्टता की पहचान रहा है। वर्तमान भुगतान एग्रीगेटर्स को सितंबर 2021 तक प्राधिकार हेतु आवेदन करना अपेक्षित कर देने के साथ ही भुगतान एग्रीगेटर्स द्वारा की गई गतिविधियों को भी विनियामक दायरे में ले लिया गया है । भुगतान गेटवे जो प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करते हैं और जो निधियों को संभाले बिना ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करते हैं, उनके लिए बेसलाइन टेक्नोलॉजी की संस्तुति की गई हैं और उन्हें विनियामक से प्राधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है।

हाल के वर्षों में, लाइसेंस संबंधी अनिश्चितताओं को कम करने और भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा दीर्घावधि कार्यनीतिक योजना को सुकर बनाने के लिए, आरबीआई कुछ शर्तों के अधीन स्थायी आधार पर संस्थाओं को अधिकृत कर रहा है। इसके अलावा, अनुशासन पैदा करने और केवल गंभीर प्रतिभागियों द्वारा आवेदन जमा करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विराम अवधि (कूलिंग पीरियड) की अवधारणा लाई गई जिसके अनुसार कोई इकाई आवेदन के

प्रतिसंहरण (रिवोकेशन)/ गैर-नवीकरण/ स्वैच्छिक आत्मसमर्पण को स्वीकार किए जाने / आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।

तालिका 1: विनियमन का दायरा और कानूनी आधार

देश	दायरा				कानूनी आधार		
	खुदरा भुगतान प्रणाली	खुदरा भुगतान लिखत	बैंकों द्वारा प्रदत्त खुदरा भुगतान सेवाएं	गैर-बैंकों द्वारा प्रदत्त खुदरा भुगतान सेवाएं	केंद्रीय बैंक के क़ानून	भुगतान प्रणाली के क़ानून	अन्य क़ानून
आस्ट्रेलिया	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ब्राजील	Y	Y	Y			Y	Y
कनाडा					Y	Y	
चीन	Y	Y	Y	Y	Y		Y
यूरोपीय केंद्रीय बैंक	Y	Y	Y	Y	Y		
फ्रांस	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
जर्मनी	Y	Y	Y	Y	Y		
हांगकांग एसएआर	Y	Y	Y	Y		Y	
भारत	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
इटली	Y	Y	Y	Y			Y
जापान	Y				Y		
मेक्सिको	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
रूस*	–	–	–	–		Y	
सऊदी अरब	Y	Y	Y	Y	Y		Y
सिंगापुर	Y	Y	Y	Y		Y	
दक्षिणी अफ्रीका	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
दक्षिणी कोरिया	Y	Y	Y	Y	Y		Y
स्वीडन	Y				Y		Y
तुर्की	Y				Y		Y
संयुक्त राज्य अमरीका	Y	Y	Y		Y	Y	Y

स्रोत: खुदरा भुगतान में केन्द्रीय बैंक की भागीदारी पर कार्यकारी समूह द्वारा किया गया सर्वेक्षण, 2012 (सीपीएसएस, बीआईएस)
** आंकड़े उपलब्ध नहीं*

2. भुगतान प्रणाली के विनियमन की लागत

2.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों अर्थात आरटीजीएस और एनईएफटी पर प्रसंस्करण प्रभार माफ कर दिया है। इसके अलावा, 1 जनवरी, 2020 से बैंकों को निदेशित किया गया है कि वे अपने बचत बैंक खाताधारकों द्वारा ऑनलाइन शुरू किए गए एनईएफटी निधि अंतरण पर कोई प्रभार न लगाए । इसके अलावा, 1 जनवरी, 2020 से, सरकार ने निदेश दिया है कि यूपीआई और रु पे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए व्यापारी मितिकाटा दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) न लिया जाए। वर्तमान में, ₹2 मिलियन या उससे अधिक के वार्षिक व्यापारावर्त वाले व्यवसायों के लिए, डेबिट कार्ड (रु पे के अलावा) पर एमडीआर लेन-देन मूल्य के 0.9% या ₹1,000, जो भी कम हो, तक सीमित रखी गई है।

2.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

2.3 विश्लेषण: जबकि उपभोक्ताओं द्वारा नकदी को 'मुफ्त' माना जाता है, इसकी महत्वपूर्ण समाज-सर्जित लागत होती हैं और साथ ही मुद्रा की छपाई, वितरण और रख-रखाव की लागत भी होती है, जो आरबीआई द्वारा वहन की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक, अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कम लागत पर ई-भुगतान की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भुगतान प्रणाली की लागत को विनियमित कर रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों के लिए लेन-देन की लागत में कमी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त व्यापारियों को जोड़ने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी।

भुगतान प्रणालियों की लागतों के विनियमन के लिए ठीक संतुलन की आवश्यकता होती है। उच्च लागत उपभोक्ताओं/व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की ओर जाने से हतोत्साहित करेगी, जबकि कम लागत लाभप्रद नहीं होने से निवेश को हतोत्साहित करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रयास अविरत उपस्थिति और निरंतरता हेतु भुगतान क्षेत्र को बड़ी मात्रा वाला, कम-औसत-मूल्य और कम लागत वाला मामला बनाना है।

तालिका 2: परस्पर परिवर्तनीयता शुल्क

		केन्द्रीय बैंक[1]			प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी /केन्द्रीय बैंक संवाद
क्षेत्र	देश	एजेंसी	कार्रवाई /नियम		
			कार्रवाई /नियम की गई	कार्रवाई /नियम बकाया	
1	2	3	4	5	6
एशिया पेसिफिक	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलियाई रिज़र्व बैंक का भुगतान प्रणाली बोर्ड (संसद द्वारा	1. एमसी, वीसा, एमेक्स और डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड अधिभार-नहीं नियम समाप्त किए गए (01/03) 2. बैंक कार्ड ,एमसी, और वीसा ने परस्पर परिवर्तनीयता शुल्क	1. बिक्री केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी पीओएस) पिन डेबिट इंटरचेंज शुल्क कम करने का प्रस्ताव (02/05)।	"ऑस्ट्रेलिया में डेबिट और क्रेडिट कार्ड योजनाएं, इंटरचेंज फीस और एक्सेस का एक अध्ययन," अक्टूबर

क्षेत्र	देश	केन्द्रीय बैंक[1] एजेंसी	कार्रवाई /नियम		प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी /केन्द्रीय बैंक संवाद
			कार्रवाई /नियम की गई	कार्रवाई /नियम बकाया	
		जुलाई 1998 में स्थापित)	(इंटरचेंज फीस)कम की और इसके स्तरों को प्रकाशित करना आरंभ किया ।(10/03) 3. एमेक्स और डाइनर्स क्लब और उनके बैंक भागीदारों के बीच भुगतान को विनियमित नहीं किया जाएगा; हालांकि, एमेक्स और डाइनर्स क्लब उनके मर्चेंट समझौतों के खण्ड का पुनः शब्दांकन करेंगे और औसत व्यापारी सेवा शुल्क प्रकाशित करेंगे। (02/05)	2. वीज़ा सिग्नेचर डेबिट इंटरचेंज शुल्क कम करने का प्रस्ताव (02/05)। 3. वीज़ा क्रेडिट कार्ड-हस्ताक्षर डेबिट कार्ड एचएसी नियम को समाप्त करने का प्रस्ताव (02/05) 4. बैंक वर्ष 2007 में क्रेडिट कार्ड योजनाओं के मानकों की समीक्षा करेगा। (02/05)	2000 संयुक्त अध्ययन आयोजित किया गया।
उत्तरी अमरीका	कनाडा	बैंक ऑफ़ कनाडा			सीमित संपर्क
	मेक्सिको	बैंको डि मेक्सिको		1. बैंको डी मेक्सिको और मेक्सिकन बैंकर्स एसोसिएशन के बीच एक ठोस प्रयास के कारण इंटरचेंज फीस कम कर दी गई। 2. बैंको डी मेक्सिको ने एचएसी नियम को और अधिक लचीला बना दिया है: व्यापारियों को केवल डेबिट, क्रेडिट या दोनों कार्ड स्वीकार करने की अनुमति है। 3.कोई अधिभार नहीं (नो-सरचार्ज) नियम को बरकरार रखा गया था क्योंकि छूट की अनुमति पहले से ही दी गई है	सीमित संपर्क
	संयुक्त राज्य अमरीका	फ़ेडरल रिज़र्व			सीमित संपर्क
यूरोप	यूरोपीय संघ-सीमा पार	यूरोपीय केंद्रीय बैंक			थोड़ा संपर्क ; ईसीबी सलाहकार की भूमिका निभा सकता है।
	स्वीडन	रिक्स बैंक			सीमित संपर्क
	यूनाइटेड किंगडम	बैंक ऑफ़ इंग्लैंड			सीमित संपर्क ; बैंक ऑफ इंग्लैंड संयुक्त ओएफटी/उद्योग कार्य बल (टास्क फोर्स) में एक पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहता है।

स्रोत: विभिन्न देशों में परस्पर परिवर्तनीयता शुल्क: विकास और निर्धारक (स्टुअर्ट ई. वेनर और जूलियन राइट)

ख. नकदी

3. प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा

3.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा जो वर्ष 2017 में 218 अमरीकी डॉलर थी वह वर्ष 2020 में बढ़कर 288 अमरीकी डॉलर हो गई । तथापि, भारत में प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा में महत्वपूर्ण रूप से अंतर होता है।

3.2 बेंचमार्क रेटिंग: लीडर

भारत की स्थिति : 3/18

तालिका 3: प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा

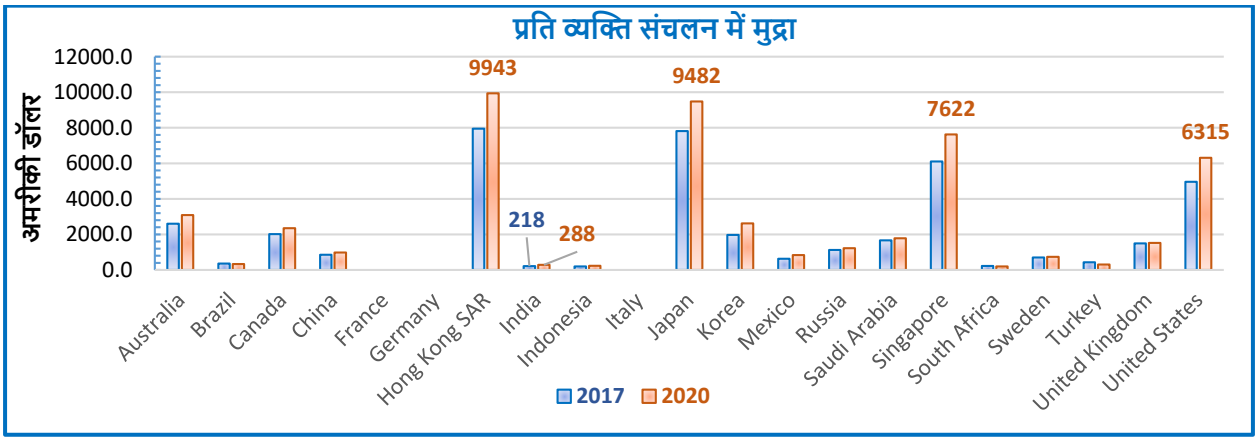

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

3.3 विश्लेषण: प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा नकदी के उपयोग की और संकेत करती है और इसलिए प्रति व्यक्ति संचलनगत मुद्रा के निम्न स्तर का मतलब भुगतान के डिजिटल मोड को अधिक अपनाना है । हालांकि, प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा किसी देश में प्रति व्यक्ति आय के स्तर को भी दर्शाता है, जो कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर से प्रदर्शित होता है।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में अधिकांश देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और तुर्की को छोड़कर) में प्रति व्यक्ति संचलनगत मुद्रा वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति संचलनगत मुद्रा में वृद्धि को कोविड जनित

महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अनुभव की जा रही अनिश्चितताओं के कारण व्यक्तियों द्वारा नकदी रखने की अधिमानता के रूप में देखा जा सकता है।

प्रति व्यक्ति संचलन में मुद्रा का उच्च स्तर आवश्यक रूप से भुगतान लेनदेन के लिए नकदी के उपयोग की ओर इंगित नहीं करता है और यह मूल्य संचयन के रूप में मुद्रा के उपयोग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, यह सभी अधिकारिताओं में मुद्रा के उच्च मूल्यवर्ग के लिए देखी गई मजबूत मांग से प्रदर्शित होता है।

तालिका 4: मूल्यवर्ग के अनुसार संचलन में मुद्रा

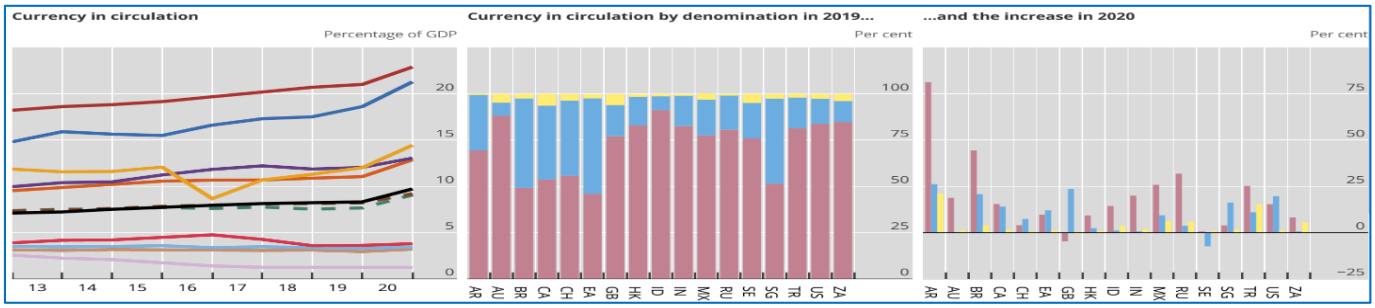

(करेंसी इन सर्कुलेशन=संचलन में मुद्रा; परसेंटेज ऑफ़ जीडीपी =सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत ; करेंसी इन सर्कुलेशन बाई डीनोमीनेशन इन 2019=वर्ष 2019 में मूल्यवर्गवार संचलन में मुद्रा; एंड द इनक्रीस इन 2020 =और 2020 में वृद्धि; परसेंट = प्रतिशत
टू लार्जेस्ट नोट्स = दो बड़े (मूल्य वर्ग वाले) नोट, रिमेनिंग नोट्स=शेष नोट ; कॉइनस =सिक्के
[1]ईए:100यूरो नोट भी शामिल किए गए, क्योंकि 500 यूरो नोट अब जारी नहीं किए जाते; इन: दूसरे बड़े मूल्य वर्ग के नोटों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे स्मारक बैंक नोट हैं)

स्रोत : बीआईएस रिपोर्ट: कोविड ने भुगतान के डिजिटलीकरण को तेज किया है।
नोट : बेंचमार्क देशों के लिए मूल्यवर्गवार करेंसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

4. सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा

4.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल देशों में से भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा तीसरी सबसे अधिक है। वर्ष 2017 में भारत में संचलन में मुद्रा जीडीपी के 10.7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2020 बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 14.4% हो गई, जो सभी अधिकारिताओं में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। वर्ष 2017 की तुलना में 2020 में केवल चीन और तुर्की में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीआईसी में गिरावट देखी गई।

4.2 बेंचमार्क रेटिंग: कमजोर

भारत की स्थिति : 16/18

तालिका 5: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा

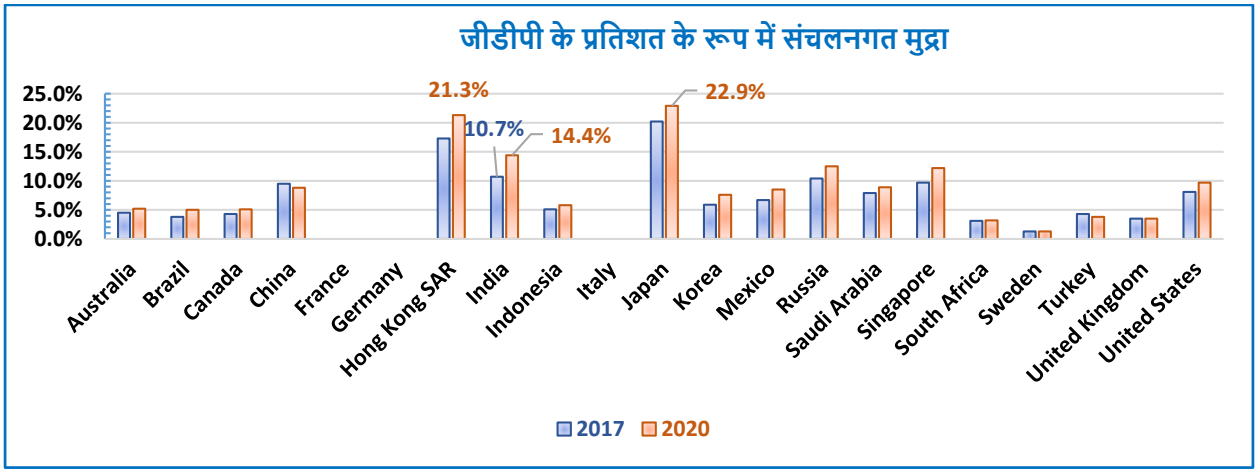

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

4.3 विश्लेषण: मुद्रा की मांग देश की आर्थिक संवृद्धि, ब्याज दर का स्तर और जनसांख्यिकीय रूपरेखा (प्रोफाइल) सहित कई समष्टि-आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संचलनगत मुद्रा का अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में नकदी की निर्भरता का संकेतक है। हालाँकि, नकदी का उपयोग भुगतान के साधन और मूल्य के संचय दोनों के रूप में किया जाता है। कोविड जनित महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मूल्य संचय के रूप में मुद्रा के उपयोग को और अधिक महत्व मिला।

कोविड जनित महामारी की शुरुआत के साथ, सभी अधिकारिताओं में नकदी की कमी हो गई थी। भारत में तालाबंदी गंभीर थी, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई और अन्य देशों के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट (भाजक के रूप में) ने वर्ष 2020 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संचलनगत मुद्रा की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बेंचमार्क देशों में, केवल हांगकांग (21.3%) और जापान (22.9%) में भारत की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलनगत मुद्रा का उच्च अनुपात था। कम अपराध दर, वर्षों से अति-निम्न ब्याज दरों और एटीएम के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क ने जापान में नकदी को आकर्षक बना दिया है, जिससे लोगों को यह अवसर मिला कि वे भुगतान के अन्य तरीकों को अपनाएं।

ग. भुगतान प्रणाली लेन–देन

5. भुगतान प्रणाली लेन–देन मात्रा और संवृद्धि

5.1 मुख्य अंतर्दृष्टि:

5.2 बेंचमार्क रेटिंग : मात्रा – मजबूत; कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)- लीडर

भारत की स्थिति: मात्रा – 5/20; सीएजीआर – 2/20; वर्षानुवर्ष वृद्धि – 2/20

तालिका 6: भुगतान प्रणाली लेन–देन मात्रा

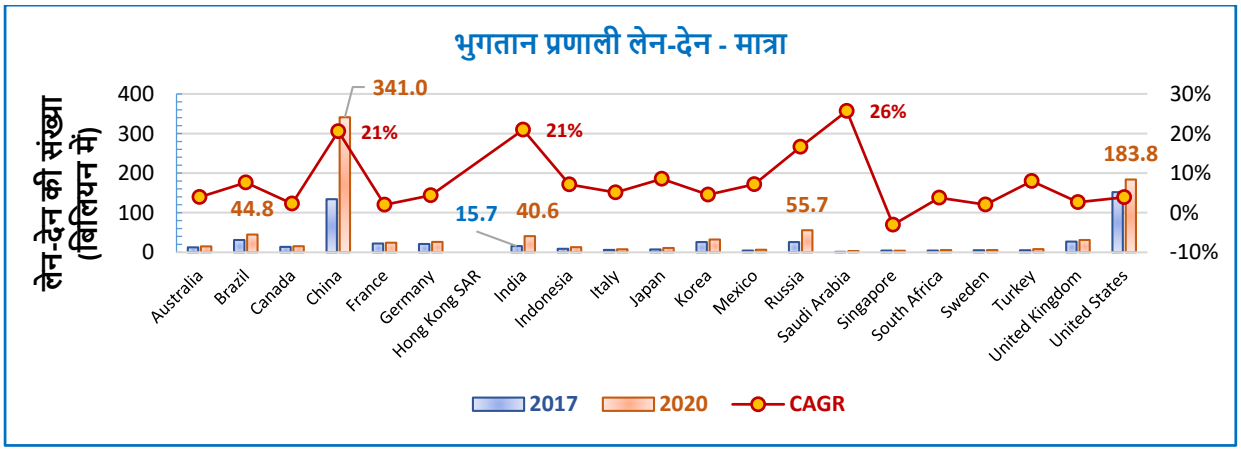

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

सीएजीआर= कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर

तालिका 7: भुगतान प्रणाली लेन–देन मात्रा में वर्षानुवर्ष वृद्धि

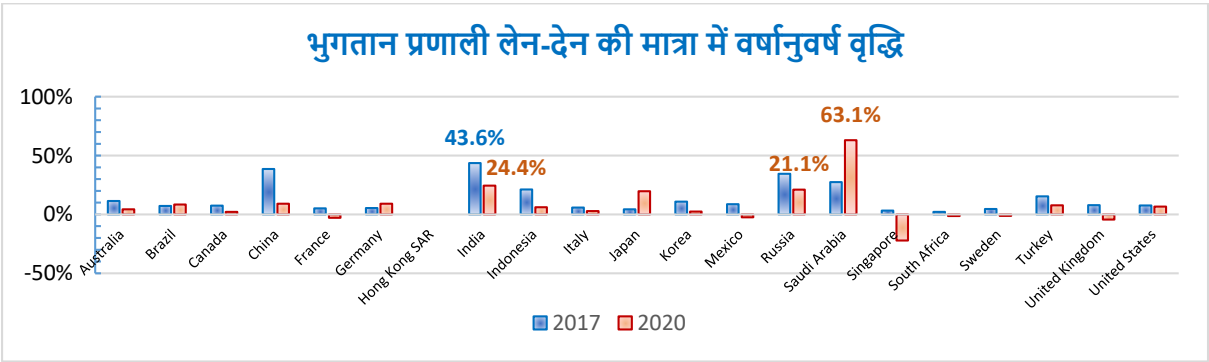

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

5.3 विश्लेषण : भुगतान प्रणाली लेन-देन की मात्रा नकदीतर (गैर-नकद) भुगतान को अपनाने और नकदी से दूर होने का संकेत देती है। इसके अलावा, वर्षानुवर्ष वृद्धि नकदीतर भुगतान प्रणाली लेन-देन की ओर बढ़ने की गति का संकेतक है।

डिजिटल भारत के अपने विजन की ओर अग्रसर होते हुए भारत ने भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों के साथ मिलकर 'ऐम्पावरिंग(सशक्तिकरण) एक्सेप्शनल(असाधारण) (ई) पेमेंट एक्सपीरियंस (ई-भुगतान अनुभव)' की दिशा में जोरदार प्रयास किया है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाया गया और उनमें गहनता आई की है। वर्ष 2017 और 2020 के बीच 21% की सीएजीआर के साथ, वर्ष 2020 में नकदीतर भुगतानों की संख्या तेजी से बढ़कर 40 बिलियन से अधिक हो गई है। भारत में भुगतान प्रणाली लेन-देन में पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में 24.4% की वृद्धि हुई है। बेंचमार्क देशों में, केवल सऊदी अरब ने वर्ष 2020 में 63% की उच्च वर्षानुवर्ष वृद्धि का प्रदर्शन किया। नकद भुगतान से भुगतान के अन्य तरीकों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में जब जनसंख्या महत्वपूर्ण हिस्सा भुगतान प्रणाली लेन-देन को अपना लेता है तो भुगतान लेन-देन की वर्षानुवर्ष वृद्धि सभी अधिकारिताओं में साधारण होती है।

भुगतान प्रणाली लेन-देन की संख्या के संदर्भ में, ब्राजील (45 बिलियन), चीन (341 बिलियन), रूस (56 बिलियन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (184 बिलियन) ने वर्ष 2020 में भारत की तुलना में अधिक लेन-देन किया है । हाल के वर्षों में नकदी इतर भुगतान में चीन की प्रगति अलीबाबा के अलीपे और टेंसेंट के वी चैट पे द्वारा प्रेरित है।

6. संचलनगत मुद्रा में भुगतान प्रणाली लेन-देन का मूल्य

6.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : बेंचमार्किंग अभ्यास में सम्मिलित अन्य देशों की तुलना में वर्ष 2020 में संचलनगत मुद्रा के सापेक्ष भुगतान प्रणाली लेनदेन का मूल्य भारत में सबसे कम (44.9) था। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2017 से 2020 के दौरान इस अनुपात में वृद्धि देखी है।

6.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति: 14/16

तालिका 8: संचलनगत मुद्रा में भुगतान प्रणाली लेन-देन का मूल्य

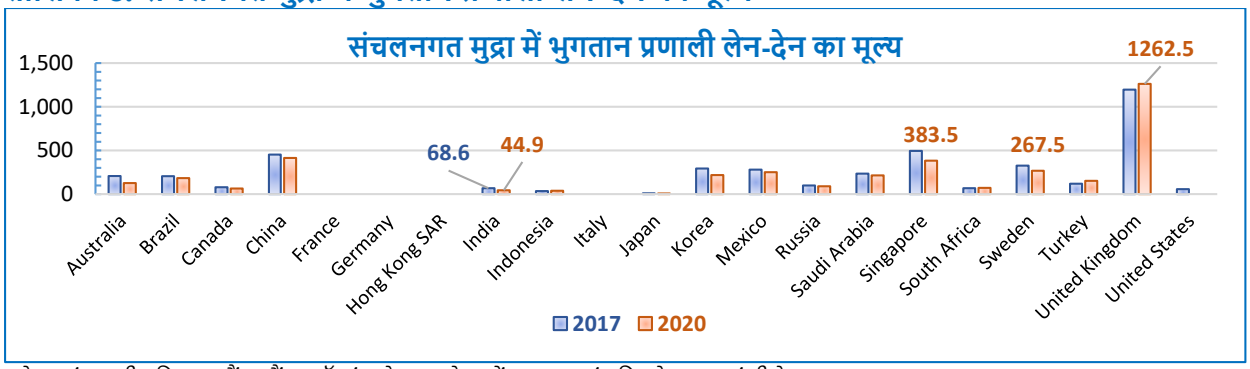

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

6.3 विश्लेषण : संचलन में मुद्रा के सापेक्ष भुगतान प्रणाली द्वारा संसाधित लेन-देन के मूल्य का उच्च अनुपात नकदी के उपयोग से भुगतान प्रणालियों की ओर अर्थव्यवस्था के प्रवसन को इंगित करता है।

भारत बेंचमार्क देशों में 14वें स्थान पर है, वर्ष 2020 में संचलन में मुद्रा के सापेक्ष भुगतान प्रणाली लेनदेन के कुल मूल्य का अनुपात 44.9 था । वर्ष 2020 में यूनाइटेड किंगडम 1262.5 के अनुपात के साथ लीडर (अग्रणी) है, इसके बाद चीन और सिंगापुर का अनुपात क्रमशः 414.7 और 383.5 है ।

भारत में, खुदरा भुगतान प्रणाली भुगतान लेन-देन की मात्रा को संचालित करती है और मूल्य के मामले में बड़े मूल्य की प्रणाली अर्थात तत्काल सकल निपटान प्रमुख हिस्सा लेती है। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) उन ग्राहकों के लेन-देन की सुविधा भी देता है जिनका व्यक्तिगत लेन-देन मूल्य अन्य खुदरा भुगतान प्रणालियों के बराबर है; इसलिए, इन लेन-देनों को खुदरा भुगतान के रूप में माना गया है। भारत के लिए यह अनुपात कम है क्योंकि खुदरा भुगतान में मुख्य रूप से बड़ी मात्रा और कम मूल्य के लेन-देन शामिल हैं।

(घ). चेक

7. चेकों में कमी की दर

7.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : वर्ष 2020 में भारत में अन्य देशों की तुलना में चेक भुगतान की मात्रा (708 मिलियन) अधिक थी। भारत में चेक-आधारित भुगतान लेन-देन में वर्ष 2017 से 2020 के दौरान 15.4 प्रतिशत की सीएजीआर से गिरावट हुई।

7.2 बेंचमार्क रेटिंग : सामान्य

भारत की स्थिति: मात्रा – 16/18; कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) – 12/18

तालिका 9: चेक लेन-देन की मात्रा

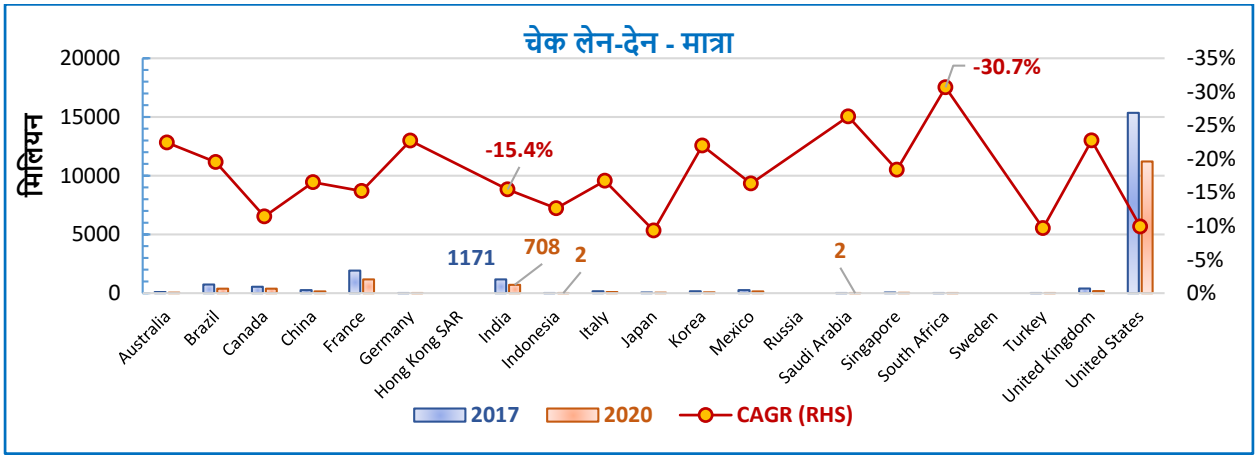

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)
सीएजीआर (आरएचएस)= कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (दायें हाथ की तरफ)

7.3 विश्लेषण: डिजिटल भुगतान की ओर प्रवसन के साथ, सभी अधिकारिताओं में कागज आधारित लेन-देन की मात्रा घट रही है। अधिकांश बेंचमार्क देश चेक के उपयोग को समाप्त करने के नजदीक हैं; जबकि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम चेक के उपयोग को कम करने में सबसे सफल हैं। वर्ष 2020 में, भारत में चेक भुगतान की मात्रा 708 मिलियन थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, भले ही चेक भुगतान की मात्रा कम हो, चेक से जुड़े लेन-देन का मूल्य काफी अधिक है। इन देशों में सरकारी भुगतान सहित उच्च मूल्य के लेन-देन के लिए ज्यादातर चेक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में, सामान्य रूप से लोगों की कागजी लिखतों के प्रति एक मजबूत अधिमानता है, विशेष रूप से उच्च मूल्य के भुगतान के लिए और इसलिए चेक का उपयोग अभी भी व्यापक है।

8. भुगतान प्रणाली में चेकों का हिस्सा (मात्रा)

8.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत में कुल भुगतान प्रणाली लेन-देन में चेक भुगतान की हिस्सेदारी जो वर्ष 2017 में 7.5% थी वर्ष 2020 में घटकर 1.7% रह गई,

8.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति :11/15

तालिका 10: भुगतान प्रणाली में चेकों का हिस्सा (मात्रा)

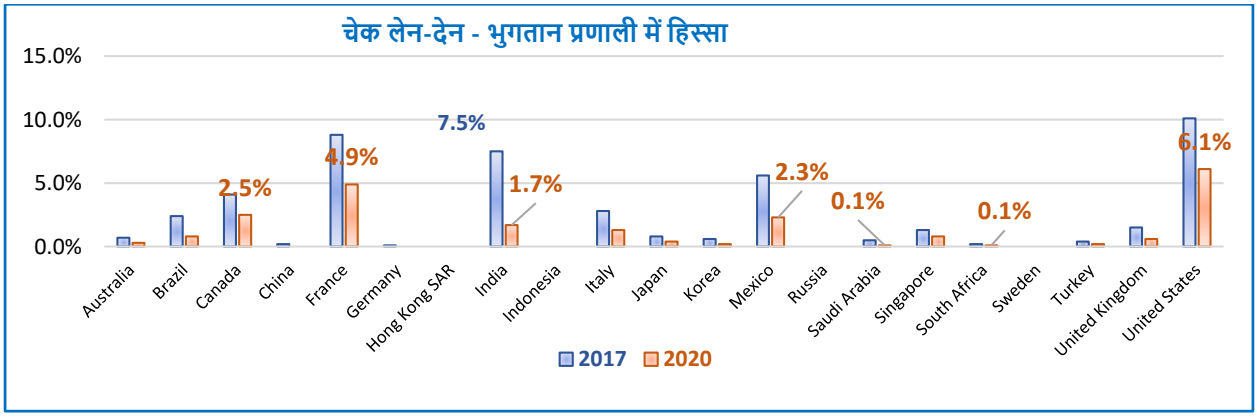

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

8.3 विश्लेषण: समग्र भुगतान लेन-देन में चेक लेन-देन की घटती हिस्सेदारी डिजिटल भुगतानों को अपनाने और कागज से भुगतान के डिजिटल रूप में प्रवसन को इंगित करती है। यद्यपि भारत में चेक भुगतानों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी देखी गई और वर्ष 2020 में कुल भुगतान लेन-देन में चेकों का हिस्सा केवल 1.7% था परन्तु

बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल अन्य देशों की तुलना में, कनाडा (2.5%)), फ्रांस (4.9%), मेक्सिको (2.3%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (6.1%) को छोड़कर, चेकों की हिस्सेदारी अधिक पाई गई ।

जर्मनी, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका ऐसे कुछ देश हैं जो चेक को भुगतान के एक तरीके के रूप में समाप्त करने के करीब हैं।

9. चेक लिखत की विशेषताएं

9.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: वर्ष 2021 में, भारत में सभी बैंक शाखाओं को छवि-आधारित सीटीएस (चेक ट्रंकेशन प्रणाली) समाशोधन तंत्र के अंतर्गत लाया गया है, जो पूरे देश में सभी लिखतों के लिए टी + 1 निपटान सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर ने के लिए, सभी उच्च मूल्य के चेक, अर्थात ₹50,000 से अधिक के लिए सकारात्मक भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ।

9.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

9.3 अंतर्दृष्टि : वैश्विक स्तर पर, अधिकांश देशों में एक चेक समाशोधन गृह हैं जिसमें समाशोधन गृह प्रचालक के रूप में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। इसके अलावा, अधिकांश अधिकारिताओं में स्वचालित चेक प्रसंस्करण सुविधा के साथ चेकों को मानकीकृत किया गया हैं।

भारत में, "सीटीएस-2010" चेक मानक कुछ अनिवार्य विशेषताएं निर्धारित करता है जैसे कागज की गुणवत्ता, वॉटरमार्क, अदृश्य स्याही में बैंक का लोगो, शून्य पेंटोग्राफ, आदि, और चेक पर फील्ड प्लेसमेंट का मानकीकरण। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा उनकी आवश्यकता और जोखिम बोध के आधार पर कार्यान्वयन के लिए कुछ वांछनीय विशेषताओं का भी सुझाव दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर सीटीएस के कार्यान्वयन ने कागज-आधारित समाशोधन के परिचालन की दक्षता में वृद्धि की है और चेकों के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया को तेज किया है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ग्राहक सेवा हुई है।

दुनिया भर के देशों में चेक प्रसंस्करण के लिए जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। हालांकि, विभिन्न अधिकारिताओं में उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए चेक का उपयोग अभी भी प्रचलित है। उच्च मूल्य के चेक भुगतानों में ग्राहक संरक्षा को और बढ़ाने और चेक के पन्नों से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए, भारत ने 2021 में सकारात्मक भुगतान की संकल्पना आरम्भ की, जिसमें बड़े मूल्य के चेक के प्रमुख विवरणों की पुन: पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है । सकारात्मक भुगतान तंत्र के तहत, चेक जारीकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, आदि के माध्यम से) चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (तिथि, लाभार्थी / आदाता (पाने वाले) का नाम, राशि, आदि) अदाकर्ता बैंक को जमा करने की आवश्यकता होती है जो सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ प्रति-जाँच (क्रॉस-चेक) किए जाते हैं।

च. डेबिट और क्रेडिट कार्ड

10. निर्गमित डेबिट और क्रेडिट कार्ड की संख्या

10.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत, वर्ष 2020 के अंत तक निर्गत 886 मिलियन डेबिट कार्ड के साथ, निर्गमित डेबिट कार्डों की संख्या के मामले में केवल चीन (8178 मिलियन डेबिट कार्ड्स) से पीछे था। निर्गमित क्रेडिट कार्डों की संख्या के मामले में, भारत, 60.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड के साथ, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोरिया, तुर्की और यूएसए से पीछे था।

10.2 बेंचमार्क रेटिंग: निर्गमित डेबिट कार्ड – लीडर; निर्गमित क्रेडिट कार्ड्स- मजबूत

भारत की स्थिति: **डेबिट कार्ड्स-2/19: कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर): 15/19**
क्रेडिट कार्ड्स -7/19: कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर): 5/19

तालिका 11: डेबिट कार्ड निर्गमित

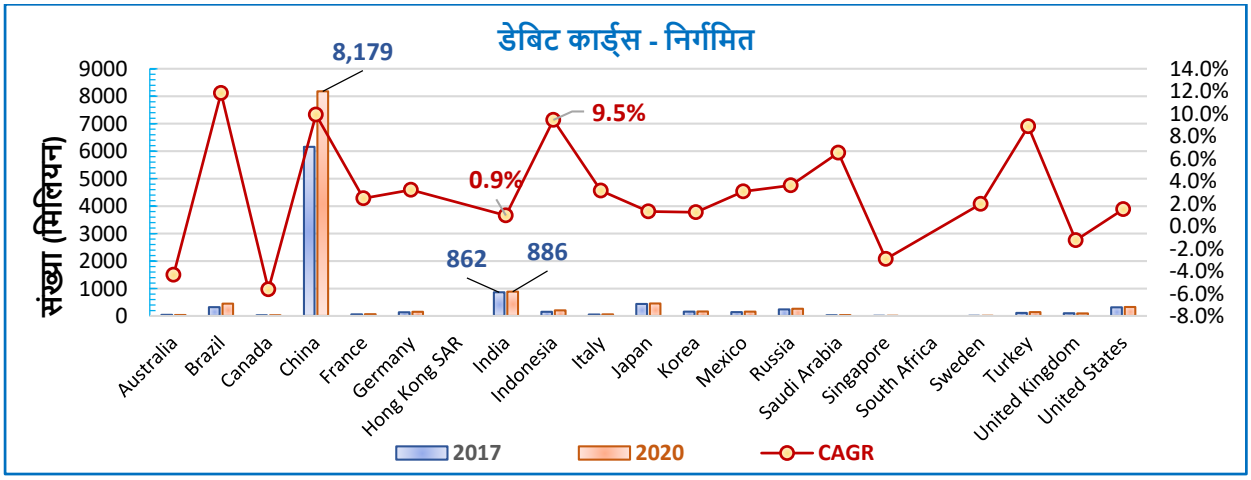

तालिका 12 –क्रेडिट कार्ड- निर्गमित

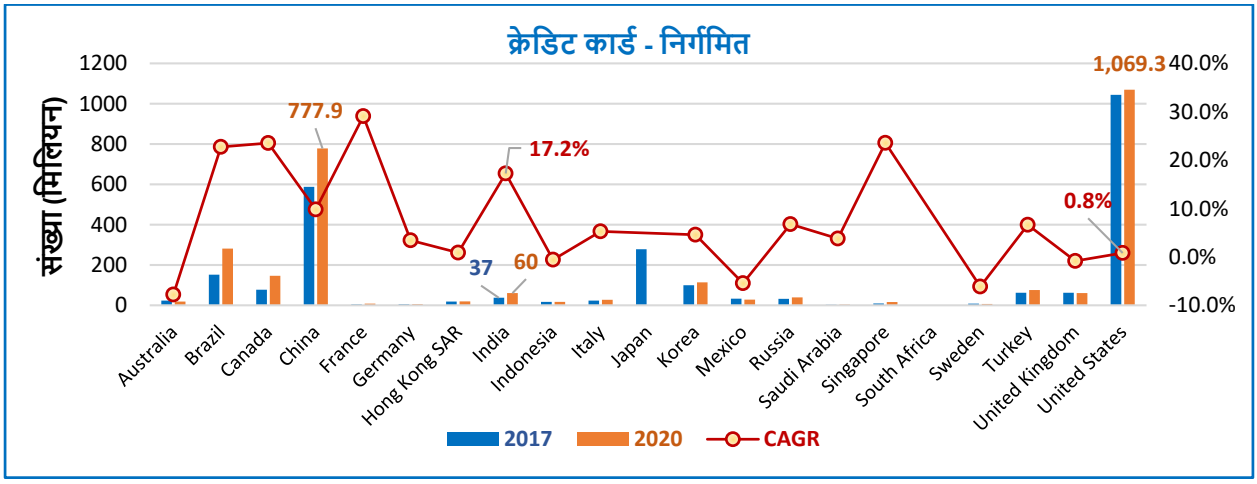

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)
सीएजीआर=कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर

10.3 विश्लेषण: किसी अधिकारिता में जारी किए गए क्रेडिट और डेबिट कार्डों की संख्या कार्ड के माध्यम से भुगतान को अपनाने का संकेत देती है। डेबिट कार्ड निर्गमन में चीन अग्रणी (लीडर) है, जिसके बाद भारत का स्थान है वर्ष 2020 के अंत तक दोनों देशों में क्रमशः 8.1 बिलियन और 0.88 बिलियन डेबिट कार्ड जारी किए गए । भारत में मार्च 2022 के अंत में निर्गमित किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्रमशः 0.92 बिलियन और 73.6 मिलियन तक बढ़ गए।

वर्ष 2019 में मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से ईवीएम चिप और पिन आधारित कार्ड में नियोजित माइग्रेशन के कारण 150 मिलियन डेबिट कार्ड बाजार से बाहर हो जाने के बावजूद, भारत ने वर्ष 2017 और 2020 के बीच डेबिट कार्ड के निर्गमन में 1% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की ।

क्रेडिट कार्ड निर्गमन के मामले में, भारत ने वर्ष 2017 और 2020 के बीच 17.2% की मजबूत कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की। क्रेडिट कार्ड में इस वृद्धि का श्रेय नवोन्मेष उत्पादों, सह-ब्रांडेड साझेदारी (जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) / फिनटेक कंपनियों की बैंकों के साथ), ई-कॉमर्स, कैश-बैक कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी को दिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि भी पारिस्थितिकी तंत्र में खुदरा उधारकर्ताओं की संख्या में विस्तार का एक संकेत है। तथापि, समग्र रूप से दिसंबर 2020 के अंत तक, चीन (778 मिलियन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (1069 मिलियन) की तुलना में भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या काफी कम है।

11. भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान का हिस्सा (मात्रा)

11.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : वर्ष 2020 में, कुल भुगतान प्रणाली लेन-देन में कार्ड भुगतान का हिस्सा भारत में दूसरा सबसे कम (14.7%) था, केवल इंडोनेशिया में इससे कम हिस्सेदारी (7.2%) देखी गई। इसके अलावा, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में कार्ड भुगतान के हिस्से में गिरावट देखने वाले कुछ देशों जैसे इंडोनेशिया, कोरिया, स्वीडन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत भी एक था।

11.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति : 16/17

तालिका 13: भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान का हिस्सा (मात्रा)

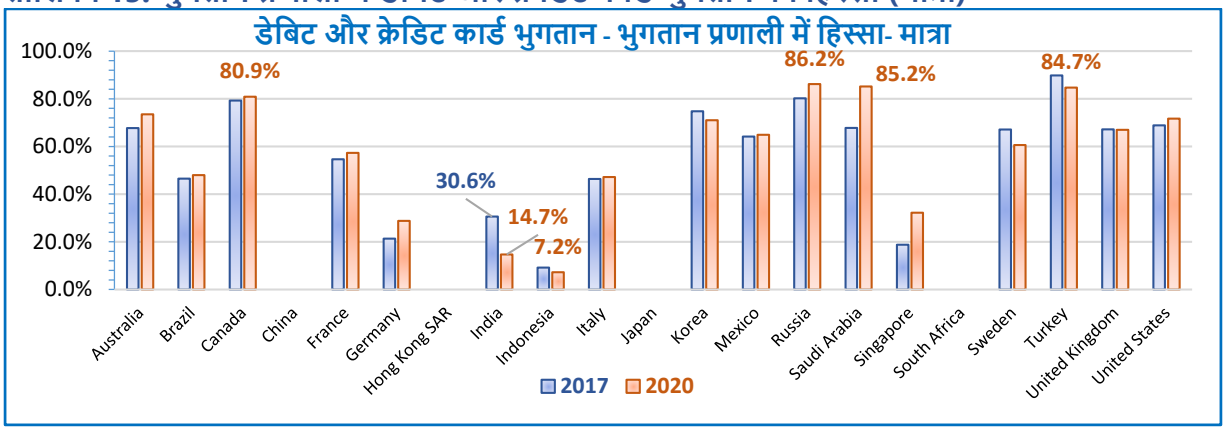

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

11.3 विश्लेषण : कार्ड भुगतान का एक उच्च हिस्सा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को भुगतान के अधिमानित (पसंदीदा) तरीके के रूप में अपनाए जाने का संकेत देता है। बेंचमार्क किए गए देशों में से कनाडा, रूस, सऊदी अरब और तुर्की में वर्ष 2020 में भुगतान प्रणाली लेन-देन में कार्ड भुगतान मात्रा के संदर्भ में प्रबल रहा ।

भारत में समग्र भुगतान प्रणाली लेन-देन में कार्ड लेन-देन की हिस्सेदारी वर्ष 2017 में 30.6% से घटकर वर्ष 2020 में 14.7% हो गई। वर्ष 2020 में कार्ड लेन-देन की हिस्सेदारी में गिरावट के लिए (ए) सर्वव्यापी, तत्काल भुगतान की सुविधा देने वाली अंतर-प्रचालनीय (इंटर ऑपरेबल) प्रणाली जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) की उपस्थिति और (बी) कोविड जनित महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर कार्ड के कम उपयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

12. अभिनियोजित बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल

12.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : वर्ष 2020 के अंत तक भारत में उपलब्ध बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या (4.6 मिलियन) थी जो बेंचमार्किंग अभ्यास में शामिल देशों, ब्राजील (13.4 मिलियन) और चीन (38.3 मिलियन) को छोड़कर, की तुलना में अधिक थी।

12.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति: 3/17

तालिका 14 : अभिनियोजित बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल

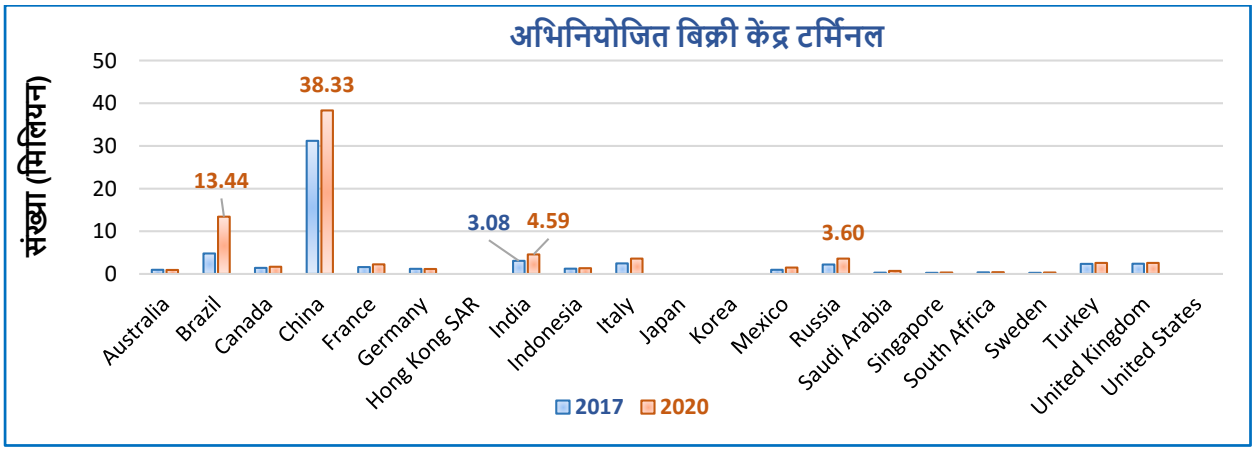

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

12.3 विश्लेषण: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पूर्वदत्त (प्रीपेड) कार्ड का उपयोग करके डिजिटल भुगतान में प्रवसन (माइग्रेशन) के लिए भुगतान स्वीकृति की अवसंरचना जैसे बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल की उपलब्धता आवश्यक है।

भारत में बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या वर्ष 2017 में 3.08 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2020 में 4.59 मिलियन हो गई और वह 14% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है। भारत में, मानकीकृत भारत क्यूआर कोड, जिसका उपयोग व्यापारी भुगतान की सुविधा के लिए किया जाता है, के क्रम-विकास के साथ, कार्ड सेगमेंट ने

भी भौतिक बिक्री केंद्र (पीओएस) से वर्चुअल/डिजिटल बिक्री केंद्र (पीओएस) में परिवर्तनीयता देखी है। ग्राहक, कार्ड से भुगतान हेतु व्यापारी द्वारा अभिनियोजित (लगाए गए) भारत क्यूआर कोड को सीधे स्कैन कर भुगतान सकते हैं।

13. प्रति बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल व्यक्तियों की संख्या

13.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत ने वर्ष 2020 के अंत तक अभिनियोजित बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों की निरपेक्ष संख्या के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, अभिनियोजित प्रति बिक्री केंद्र टर्मिनल व्यक्तियों की संख्या के मामले में, जो वर्ष 2020 के अंत में 296 व्यक्तियों के लिए एक बिक्री केंद्र टर्मिनल थी, में सुधार की गुंजाइश है।

13.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति: 17/17

तालिका 15: प्रति बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल व्यक्तियों की संख्या

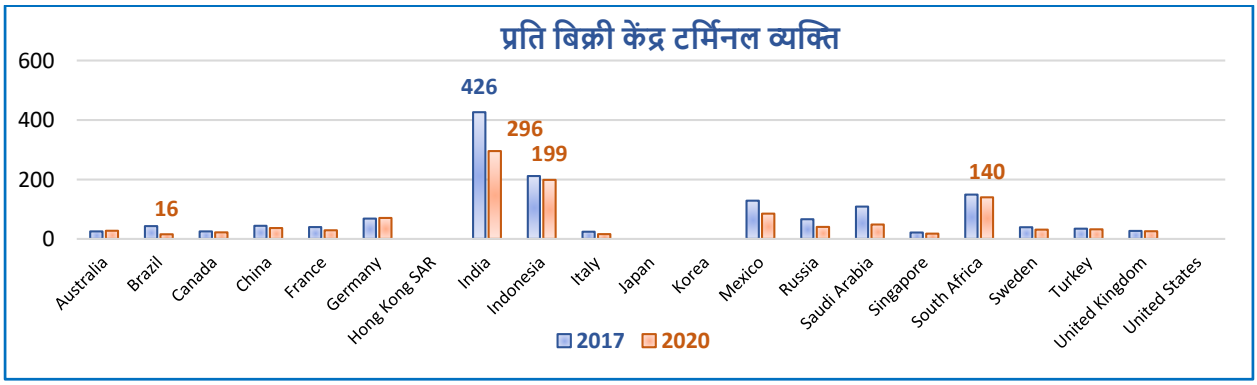

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

13.3 विश्लेषण : देश भर में भुगतान स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता को प्रति बिक्री केंद्र टर्मिनल द्वारा सेवा किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या के आधार पर मापा जा सकता है। डिजिटल भुगतानों को गहनता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश भर में स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना के घनत्व को बढ़ाया जाय।

बिक्री केंद्र टर्मिनल द्वारा सेवा किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2017 में प्रति बिक्री केंद्र टर्मिनल पर 426 व्यक्तियों के बजाए वर्ष 2020 में प्रति बिक्री केंद्र टर्मिनल पर 296 व्यक्ति हो गई। हालांकि, बेंचमार्क देशों के बीच यह आंकड़ा अभी भी सबसे अधिक है। स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना की आपूर्ति संबंधी समस्याओं को हल करने और देश में बिक्री केंद्र टर्मिनलों के अभिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना के विस्तार पर जोर देते हुए भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का परिचालन आरंभ किया। मार्च 2022 के अंत तक, इस योजना के तहत क्रमशः 9.1 मिलियन और 0.39 मिलियन डिजिटल और भौतिक भुगतान स्वीकृति डिवाइसेस अभिनियोजित किए गए।

ब्राजील उन विकासशील देशों में से एक है जहां प्रति बिक्री केंद्र टर्मिनल (16) पर कम व्यक्ति हैं। ब्राजील में, उच्च मोबाइल व्याप्ति और बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योगों (एसएमई) और व्यष्टि व्यवसायों की उपस्थिति ने देश भर में गतिशील बिक्री केंद्र / स्मार्ट बिक्री केंद्र (मोबाइल /स्मार्ट पीओएस) के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।

14. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भुगतान

14.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक क्रमशः 7.3% और 8.5% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) की सम्मानजनक दर से बढ़े हैं। तथापि, निरपेक्ष रूप से भारत में वर्ष 2020 में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की मात्रा अन्य देशों की तुलना में काफी कम थी।

14.2 बेंचमार्क रेटिंग: सामान्य

भारत की स्थिति : मात्रा-11/18, कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर – 11/18

तालिका 16: कार्ड भुगतान मात्रा और संवृद्धि

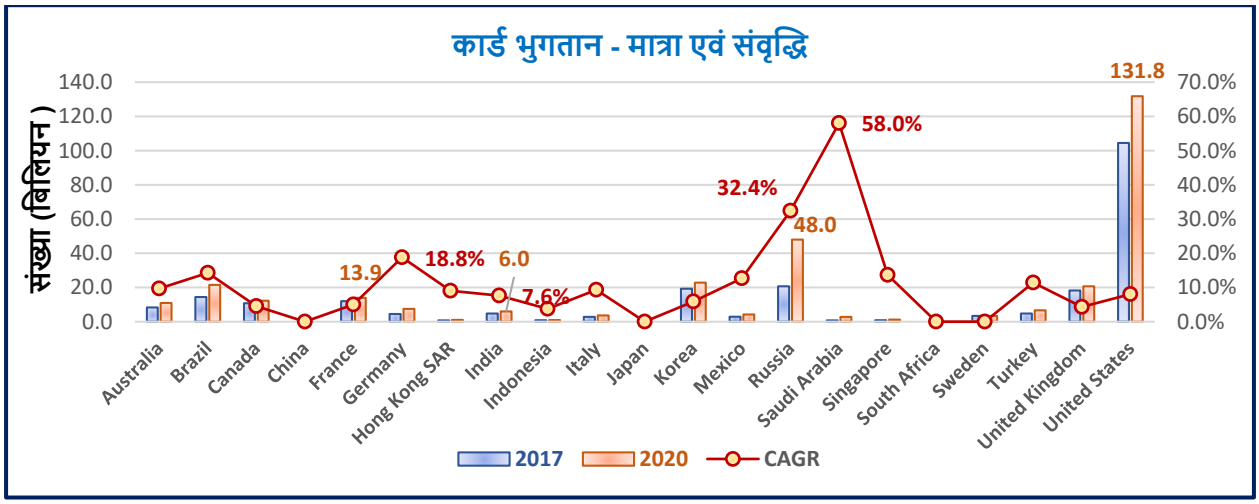

सीएजीआर=कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

14.3 विश्लेषण : कार्ड से भुगतान की उच्च मात्रा भुगतान करने के अधिमानित साधन के रूप में कार्डों को अपनाए जाने का संकेत देती है। भारत में कार्ड भुगतान की मात्रा जो वर्ष 2017 में 4.8 बिलियन लेन-देन थी वह 7.6% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर वर्ष 2020 में 5.98 बिलियन लेन-देन हो गई। हालांकि, समग्र रूप से, भारत में कार्ड भुगतान लेन-देन ब्राजील, कोरिया, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।

सऊदी अरब और रूस ने वर्ष 2017 से 2020 की अवधि के दौरान कार्ड भुगतान में क्रमशः 58% और 32% की उच्चतम वृद्धि देखी है। सऊदी अरब में कार्ड भुगतान प्रमुखतः निम्नलिखित से प्रेरित रहा; शरीयत अनुरूप इस्लामी कार्ड के निर्गमन और ई-कॉमर्स उद्योग में वृद्धि के साथ-साथ आय का बढ़ता स्तर और शहरीकरण में वृद्धि, जिससे उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में बदलाव और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई। रूस में, सरकारी पहल जैसे कि नकद भुगतान की सीमा तय करने संबंधी नियम और राष्ट्रीय भुगतान कार्ड प्रणाली (एनपीसीएस) का आरंभ ने कार्ड भुगतान की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह बढ़ोत्तरी बैंक सुविधा से संपन्न आबादी में वृद्धि, कार्ड के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता और स्वीकृति की बेहतर बुनियादी अवसंरचना पर आधारित है। दूसरी ओर, धोखाधड़ी का डर, कार्ड स्वीकार करते समय छोटे प्रतिष्ठानों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क /प्रभार कुछ ऐसे कारण हैं जो कुछ अधिकारिताओं में कार्ड भुगतान की संवृद्धि को रोकते हैं।

छ. नकदी बनाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड

15. डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान बनाम संचलन में मुद्रा

15.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में संचलनगत मुद्रा में कार्ड भुगतान का मूल्य बेंचमार्क देशों में सबसे कम, 0.4 रहा जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने हेतु कम वरीयता को दर्शाता है।

15.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति: 17/17

तालिका 17: कार्ड भुगतान मूल्य बनाम संचलनगत मुद्रा

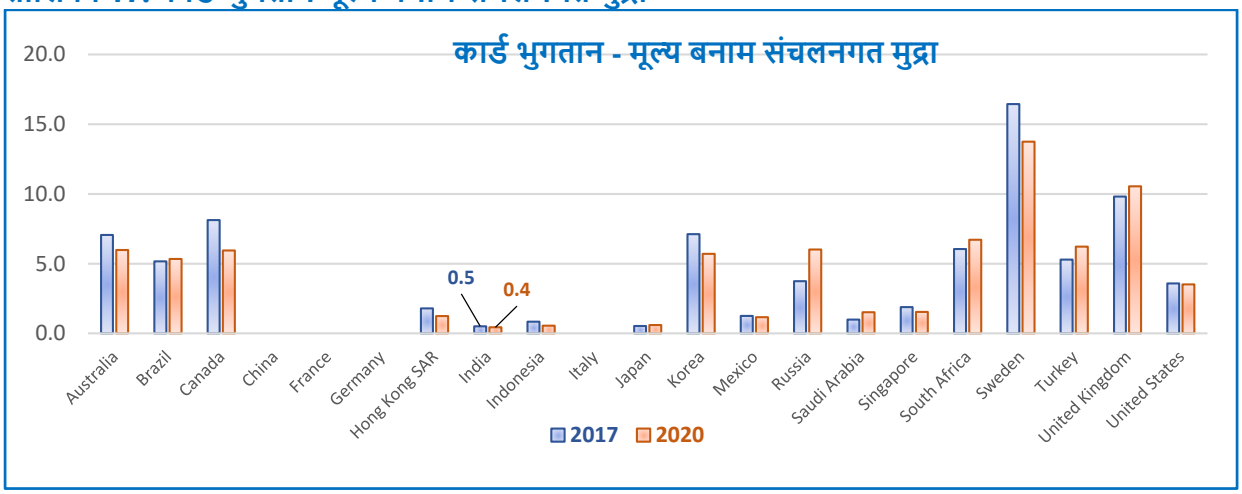

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

15.3 विश्लेषण : भारत, इंडोनेशिया और जापान ऐसे देश हैं जहां संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) से कार्ड भुगतान का अनुपात 1 से कम देखा गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत और इंडोनेशिया में कार्ड भुगतान की मात्रा काफी कम देखी गई जो भुगतान लेनदेन में कार्ड के प्रति निम्न वरीयता को दर्शाता है फलस्वरूप कार्ड भुगतान का

मूल्य कम होने की संभावना रहती है। जापान में, हालांकि वैकल्पिक भुगतान प्रणालियाँ उपलब्ध हैं, परंतु नकदी का प्रयोग अधिक है।

भारतीय भुगतान प्रणालियों की प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि भारतवासी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तुलना में भुगतान के वैकल्पिक साधनों को अधिक पसंद करते हैं।

ज. नकदी और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

16. अभिनियोजित एटीएम

16.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : , अभिनियोजित एटीएम की संख्या के मामले में वर्ष 2020 के अंत तक भारत केवल चीन और रूस के बाद था। तथापि, वर्ष 2017 से 2020 की अवधि में, भारत में अभिनियोजित एटीएम रूस में 17% की तुलना में 2% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़े।

16.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति : 3/19

तालिका 18: अभिनियोजित एटीएम

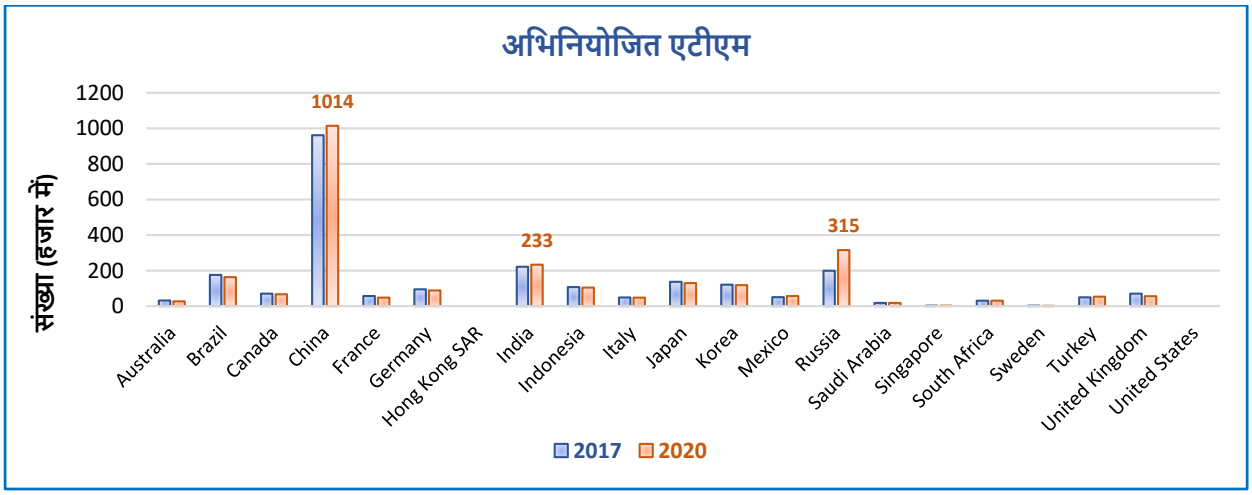

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

16.3 विश्लेषण: एटीएम मुख्य रूप से नकदी अवसंरचना का एक हिस्सा हैं। हालांकि, उनका उपयोग बढ़ते स्तर पर अन्य गतिविधियों जैसे कार्ड से कार्ड अंतरण, बिल भुगतान आदि के संचालन के लिए भी किया जा रहा है, जिससे बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस तरह ये 'डिजिटल लेनदेन' करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं परंतु सीमित स्तर पर । देश भर में एटीएम की बुनियादी अवसंरचना के प्रसार का समर्थन करने के लिए भारत में प्राधिकृत बैंकेतर संस्थाओं को भी एटीएम लगाने की अनुमति है, जिन्हें व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में जाना जाता है ।

वर्ष 2017 और 2020 के बीच लगभग 11 हजार नए एटीएम अभिनियोजित किए जाने के साथ वर्ष 2020 के अंत तक, पूरे भारत में 233 हजार एटीएम अभिनियोजित किए गए थे । यह उसी अवधि में चीन और रूस द्वारा अभिनियोजित किए गए क्रमशः 53 हजार और 116 हजार नए एटीएम की तुलना में काफी कम है।

भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में खाताधारक अक्सर कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) और अपने पड़ोस के व्यापारियों के बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों से नकदी निकालते हैं, जो "माइक्रो-एटीएम" के रूप में कार्य करते हैं । ये कारोबार प्रतिनिधि आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का उपयोग करते हैं, जो आधार आधारित अधिप्रमाणन का उपयोग कर माइक्रो-एटीएम पर ऑनलाइन अंतर-परिचालनीय (इंटरऑपरेबल) लेन-देन की अनुमति देता है। दिसंबर 2020 के अंत तक, भारत में करीब 356 हजार माइक्रो-एटीएम अभिनियोजित थे।

चीन में, एटीएम में वृद्धि की मुख्य प्रचालक ग्राहकों की मांग थी और सरकार एटीएम के अभियोजन को प्रोत्साहित करती है क्योंकि वे नए कार्डधारकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा, चीन ने परस्पर सक्रिय (इंटरएक्टिव) टेलर मशीन (आईटीएम) भी लगाए हैं जिसमें वीडियो की सहायता से स्क्रीन पर टेलर के साथ प्रयोक्ता संपर्क में होता है। आईटीएम ग्राहकों को ब्रांच में होने (इन-ब्रांच) जैसा अनुभव कराने की सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से।

17. प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या

17.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: बेंचमार्क देशों में भारत में एटीएम की निरपेक्ष रूप से तीसरी सबसे बड़ी संख्या अभिनियोजित है। हालांकि, जब हम एटीएम तक पहुंच के आधार पर इसको मापते हैं तो यह प्रदर्शन खराब लगता है क्योंकि वर्ष 2020 के अंत तक 5800 से अधिक लोगों की सेवा में एक ही एटीएम था।

17.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति : 19 /19

तालिका 19: प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या

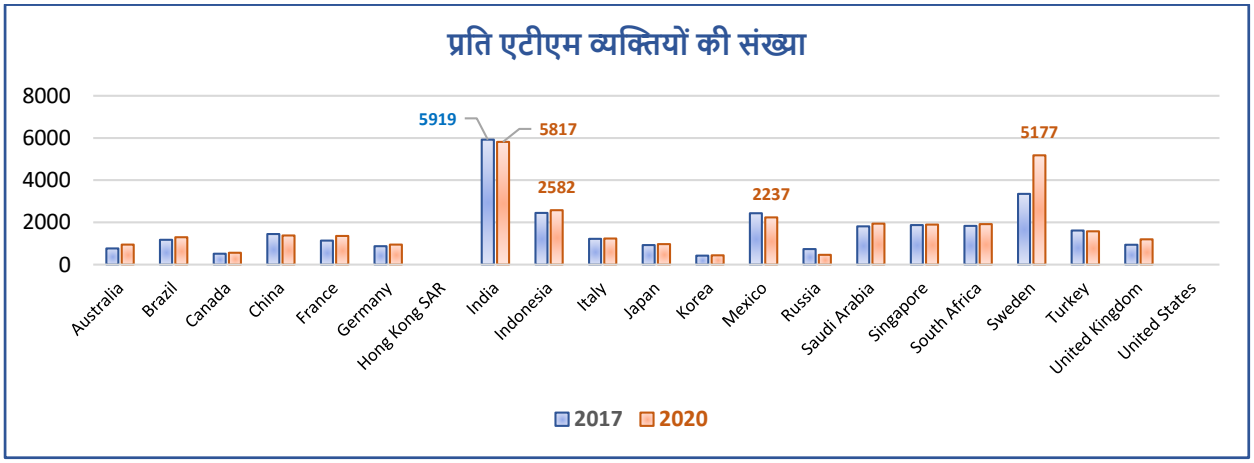

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

17.3 विश्लेषण: एटीएम घनत्व, अर्थात प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या, देश भर में एटीएम की उपलब्धता बताने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रति एटीएम व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या यह बताती है कि एटीएम की मौजूदा बुनियादी अवसंरचना जनसंख्या की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

भारत में एटीएम घनत्व वर्ष 2017 में 5919 से थोड़ा सा घट कर वर्ष 2020 में 5817 हो गया है और भारत अन्य बेंचमार्क देशों की तुलना में सबसे नीचे है। एटीएम की बुनियादी अवसंरचना को माइक्रो-एटीएम, जो प्राथमिक रूप से ग्रामीण/बैंक-रहित आबादी के लिए उपलब्ध हैं और भारत में वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, द्वारा अनुपूरित किया जाता है ।

स्वीडन में, पिछले दशक के अधिकांश समय के दौरान भुगतान प्रणालीगत गतिविधियों से एक अग्रणी संकेत यह मिला कि नकदी की मांग में गिरावट आई है। उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अपना रहे हैं और व्यापारी कागजी मुद्रा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। पिछले कुछ वर्षों में अभिनियोजित एटीएम की संख्या में गिरावट आई है। अतः प्रति एटीएम व्यक्तियों की संख्या अधिक होना हमेशा चिंता का कारण नहीं होता।

18. एटीएम से प्रति व्यक्ति नकदी आहरण

18.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: वर्ष 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति नकदी आहरण 5 था जो बेंचमार्क देशों में सबसे कम था । यह वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति 7 नकदी आहरण से कम हुआ है। हालांकि, सामान्यतः यह अनुपात नकदी पर कम निर्भरता को इंगित करता है, परंतु ज्यादातर कम अनुपात का कारण बड़ी जनसंख्या (भाजक) की एटीएम (अंश) की कम संख्या के कारण, कम पहुंच होता है। .

इसके अलावा, बिना किसी शुल्क के एटीएम से कितनी बार नकदी आहरण किया जा सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है, जो कई बार एक निवारक के रूप में कार्य करती है।

18.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति : 1/16

तालिका 20 : एटीएम से प्रति व्यक्ति नकदी आहरण

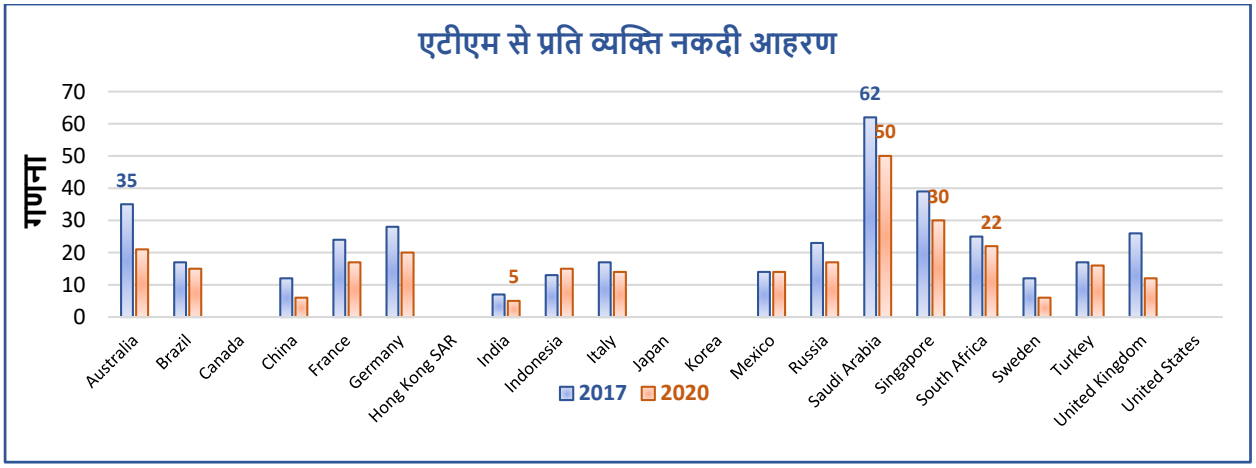

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)
नोट: जहां देश के भीतर नकदी आहरण उपलब्ध नहीं है, कुल नकदी आहरण (देश के भीतर और बाहर) को गणना में लिया गया।

18.3 विश्लेषण: एटीएम से प्रति व्यक्ति नकदी आहरण की अधिक संख्या नकदी पर अधिक निर्भरता को दर्शाती है। हालांकि, नकदी आहरण एटीएम घनत्व पर भी निर्भर करता है, और एटीएम की सीमित उपलब्धता भी आहरण की संख्या को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, कोविड जनित महामारी के कारण आए व्यवधान और सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध ने अधिकांश अधिकारिताओं (इंडोनेशिया को छोड़कर) में नकदी आहरण को कम किया है।

भारत में एटीएम घनत्व कम होने के अलावा, एक बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करने के लिए एटीएम की सीमित उपलब्धता के कारण प्रति माह मुफ्त एटीएम लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय) की संख्या पर प्रतिबंध है। इसके परिणामस्वरूप एटीएम से प्रति व्यक्ति नकदी आहरण कम होने की संभावना है।

कुछ अधिकारिताओं में, अभी भी नकदी को भुगतान के साधन के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति नकदी आहरण अधिक होगा। सिंगापुर और स्वीडन ने एटीएम के माध्यम से आहरण को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूरोप में नकदी का उपयोग मुख्य रूप से कम मूल्य के भुगतान के लिए, जबकि कार्ड का उपयोग बड़े मूल्य के भुगतान के लिए किया जाता है।

19. एटीएम से आहरण बनाम संचलनगत मुद्रा[19]

19.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में एटीएम से नकदी आहरण का संचलनगत मुद्रा से अनुपात सबसे कम है। यह एटीएम का घनत्व का कम होने के साथ प्रति व्यक्ति एटीएम लेनदेन की संख्या कम होने का परिणाम हो सकता है।

19.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति : 2/13

तालिका 21: एटीएम से आहरण बनाम संचलनगत मुद्रा

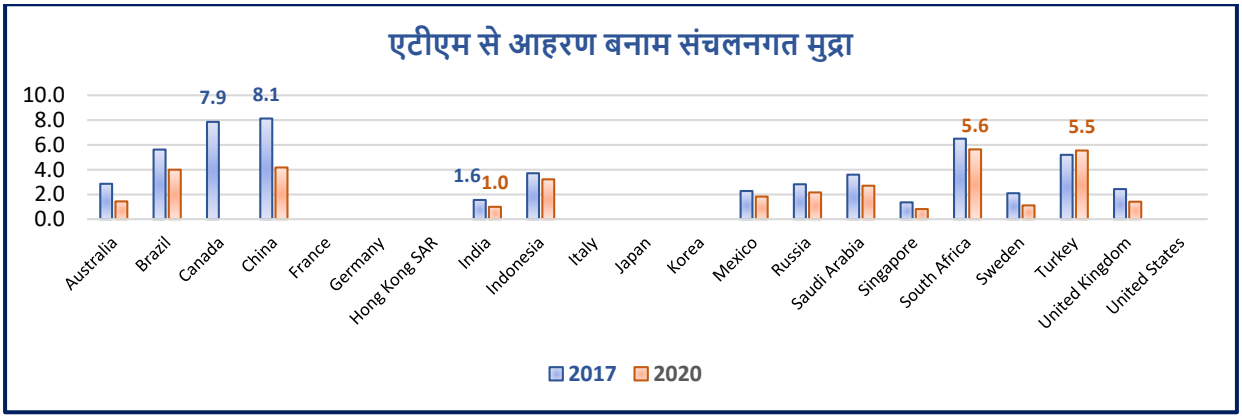

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)
नोट: जहां देश के भीतर नकदी आहरण उपलब्ध नहीं है, कुल नकदी आहरण (देश के भीतर और बाहर) को गणना में लिया गया।

[19] पिछले अभ्यास में संचलनगत मुद्रा से नकदी आहरण का अनुपात कम था और एटीएम की कम उपलब्धता को देखते हुए भारत को इस संकेतक में कमजोर का स्थान दिया गया था। हालांकि, एक समीक्षा में, डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ने पर ध्यान देने हेतु , संचलन गत मुद्रा (सीआईसी) के लिए नकदी आहरण का कम अनुपात वांछनीय बताया गया है। रेटिंग के औचित्य को तदनुसार संशोधित किया गया है ।

19.3 विश्लेषण : वर्ष 2020 में अधिकांश देशों (तुर्की को छोड़कर) में संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) के लिए नकदी आहरण के मूल्य के अनुपात में गिरावट आई है। यह संभव है कोविड जनित महामारी के प्रतिबंधों की वजह से एटीएम तक दौरों की संख्या सीमित होने के कारण आहरण का समग्र मूल्य प्रभावित हुआ हो।

भारत के लिए वर्ष 2020 में एटीएम से आहरण का मूल्य संचलनगत मुद्रा की राशि के समान था। यह वर्ष 2017 में संचलनगत मुद्रा के 1.6 गुना से कम हुआ है।

भारत में, एटीएम घनत्व कम होने, जिसने एटीएम में लेन-देन की संख्या सीमित कर दी है, के अतिरिक्त एटीएम से निकाली जा सकने वाली राशि पर सीमा लागू हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप एटीएम से नकदी आहरण का संचलनगत मुद्रा से अनुपात कम हो गया है।

झ. घरेलू कार्ड नेटवर्क

20. घरेलू कार्ड नेटवर्क की उपस्थिति और इसका हिस्सा

20.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत में, घरेलू कार्ड नेटवर्क, रु पे को वर्ष 2012 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा लॉन्च किया गया था। मार्च 2022 के अंत तक, 652 मिलियन से अधिक रु पे डेबिट कार्ड थे जो कुल निर्गत किए गए डेबिट कार्ड के 65% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ बाजार पर प्रभावी थे। हालाँकि, रु पे कार्ड्स की भारत में क्रेडिट कार्ड संवर्ग (सेगमेंट) में 3% से कम हिस्सेदारी है।

20.2 बेंचमार्क रेटिंग: सामान्य

भारत की स्थिति: 11/21

तालिका 22: घरेलू कार्ड का उपयोग - ई-कॉमर्स और बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर

क्रम संख्या	देश	घरेलू कार्ड नेटवर्क*	कार्ड नेटवर्क में हिस्सा (%) 2020					
			वीसा	मास्टर कार्ड	घरेलू*	एमेक्स	डाइनर्स	अन्य
1	आस्ट्रेलिया	एफ्टपोस	45	26	24	5		
2	ब्राज़ील	एलो	31	49	18	1		1
3	कनाडा	इंटरएक	39	26	33	3		
4	चीन	युनियन पे	0.5	0.3	99			
5	फ्रांस	कार्टेस बैंकेयर्स	1	3	84	1		10
6	जर्मनी	जिरोकार्ड	29	28	37	6		
7	हांगकांग	ईपीएस, चाइना यूनियन पे	22	15	17, 34	9		4
8	भारत	रु पे	49	36	13	2		
9	इण्डोनेशिया	जीपीएन	41	41	11			6
10	इटली	बैंकोमैट	35	39	25	1		
11	जापान	जेबीसी जे- डेबिट	38	20	32, 5	4		1
12	मेक्सिको	कारनेट	61	34		4		1
13	रूस	एमआईआर गोल्डन	45	36	12, 3			3
14	सउदी अरब,	एमएडीए	30	24	45			
15	सिंगापुर	नेट्स	34	26	33	5	1	1
16	दक्षिणी अफ्रीका		52	46		1		
17	दक्षिणी कोरिया	चाइना यूनियन पे, जेसीबी	22	16	6, 3	2		51
18	स्वीडन		28	70		2		
19	तुर्की,	ट्रॉय	54	42	3	1		
20	यूनाइटेड किंगडम		84	14		1		
21	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका	स्टार,पल्स, डिस्क वर	60	25	1, 1, 1	7		4

स्रोत: वर्ल्डपे ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022

20.3 विश्लेषण: नकदी के प्राथमिक विकल्पों में से एक कार्ड भुगतान है और कार्ड लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए अधिकांश अधिकारिताओं के पास अपने घरेलू कार्ड नेटवर्क हैं । कार्ड उपयोग में घरेलू कार्ड नेटवर्क का हिस्सा प्रबल देखा गया है जैसे चीन (99%), फ्रांस (84%), जर्मनी (37%) और सऊदी अरब (45%)। भारत में हाल के दिनों में रु पे कार्ड के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यह देखा गया है कि घरेलू कार्ड नेटवर्क वाली अधिकारिताएं सामान्यतया लेन-देन के लिए घरेलू कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देती हैं और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं के साथ ताल-मेल स्थापित करती हैं । भारत में घरेलू कार्ड नेटवर्क को बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाताधारकों को रु पे डेबिट कार्ड जारी कर वित्तीय समावेशन में सहायता हेतु के केंद्र सरकार के प्रयासों से बढ़ावा मिला । इसके अलावा, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रु पे डेबिट कार्ड के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) का अधित्याग कर दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) रु पे कार्डों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भागेदारी बनाने पर काम कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भागीदारों (चाइना यूनियन पे (सीयूपी), डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज (डीएफएस) और जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) के साथ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के गठबंधन ने रु पे की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया है। डीएफएस और जेसीबीआई बैंक पहचान संख्या (बिन्स) का उपयोग करके रु पे सह-ब्रेंड अंतरराष्ट्रीय कार्ड 195 से अधिक देशों में स्वीकार किए जाते हैं। इसके अलावा, एनपीसीआई ने अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं के साथ सह-ब्रांडिंग के बिना रु पे कार्ड स्वीकार करने हेतु भूटान और सिंगापुर के साथ प्रबंध किया है। इससे निवासियों द्वारा रु पे कार्ड की अधिक मांग को बढ़ावा देने, इसकी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

ट. क्रेडिट अंतरण

21. क्रेडिट अंतरण की मात्रा और संवृद्धि

21.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत जमा अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर) के मामले में, वर्ष 2020 में लेन-देन की संख्या और वर्ष 2017 और 2020 के बीच 3 साल की अवधि में कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दोनों में, प्रबल रहा है । इसका श्रेय चौबीसों घंटे उपलब्ध जमा अंतरण प्रणाली को दिया जा सकता है, जिससे तत्काल निधि अंतरण की सुविधा मिलती है।

21.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति: मात्रा - 1 /20 ; कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर - 1 /20

तालिका 23 : जमा अंतरण मात्रा और संवृद्धि

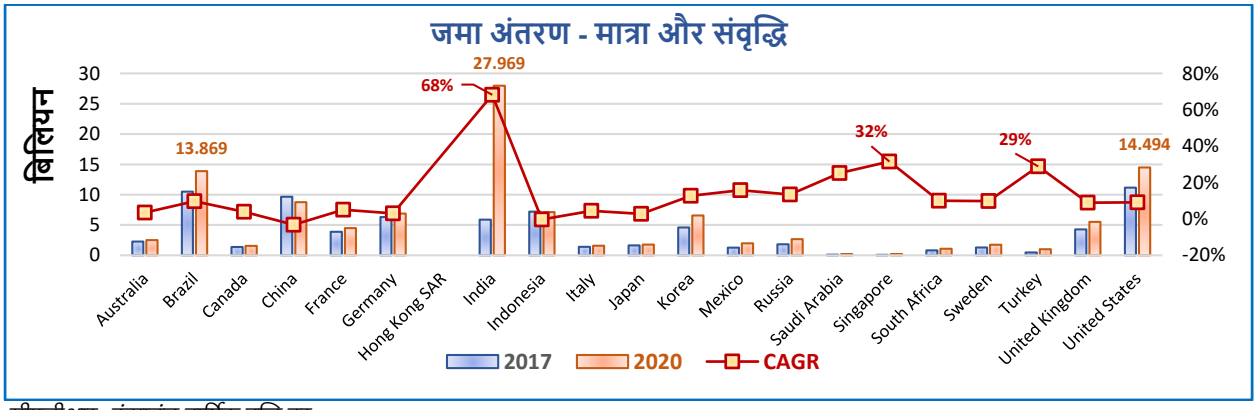

सीएजीआर=कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

21.3 विश्लेषण: भारत ने अन्य बेंचमार्क देशों की तुलना में वर्ष 2017 और 2020 के बीच जमा अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर) की मात्रा में सुदृढ़ संवृद्धि की है। वर्ष 2020 के दौरान जमा अंतरण की बहुत बड़ी मात्रा 27.97 बिलियन थी, जो वर्ष 2017 और 2020 के बीच 68% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। भारत में, खुदरा जमा अंतरण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) क्रेडिट, त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से किया जाता है।

भारत में जमा अंतरण भुगतान में वृद्धि का श्रेय अंतर-परिचालनीय भुगतान प्रणाली ('इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम') को दिया जा सकता है, जिसने भुगतान परिदृश्य में क्रांति ला दी है। अंतर-परिचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) ने बैंक और अन्य पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाताओं द्वारा भुगतान की बुनियादी अवसंरचना के उपयोग को सुकर बनाया जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिली । जमा अंतरण प्रणाली (क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम) का उपयोग भुगतान करने हेतु नकदी और कार्ड के विकल्प के रूप में लाभार्थियों को निधि अंतरण करने और क्यूआर कोड को स्कैन करने और व्यापारी भुगतान करने के लिए भी किया जाता है ।

22. भुगतान प्रणाली में जमा अंतरण का हिस्सा (मात्रा)

22.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : समग्र भुगतान प्रणाली लेनदेन में जमा अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर) की हिस्सेदारी वर्ष 2017 में 37.5% से बढ़कर वर्ष 2020 में 68.8% हो गई और अब बेंचमार्क देशों में यह सबसे अधिक है।

22.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति : 1/20

तालिका 24 : भुगतान प्रणाली में जमा अंतरण का हिस्सा (मात्रा)

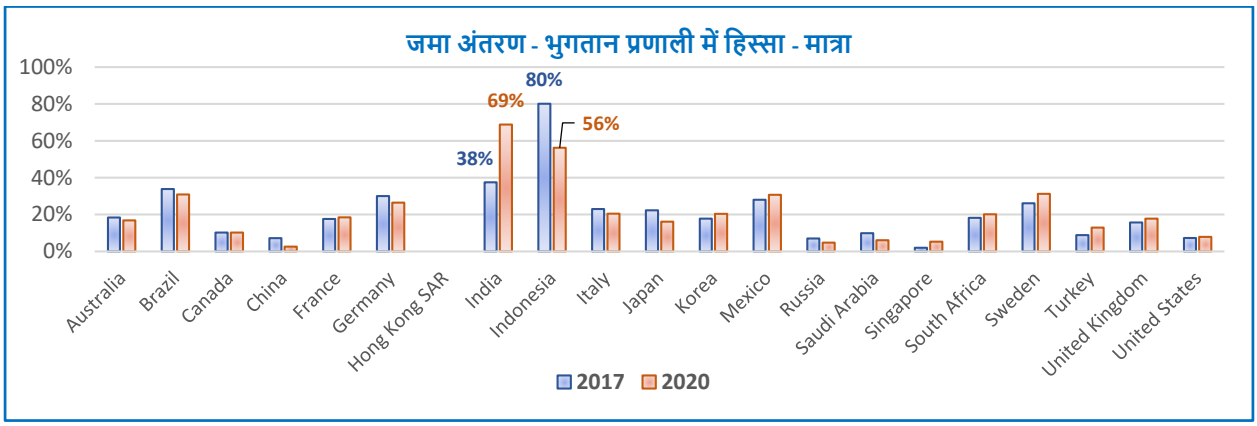

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

22.3 विश्लेषण: कुल भुगतान लेनदेन में जमा (क्रेडिट) हस्तांतरण का बड़ा हिस्सा भुगतान करने हेतु भुगतान प्रणाली के अन्य रूपों (सीधे नामे, कागजी समाशोधन) और लिखतों (कार्ड, ई-मुद्रा) पर जमा हस्तान्तरण प्रणाली हेतु उपभोक्ता के अधिमान को इंगित करता है।

भारत में खुदरा जमा अंतरण प्रणाली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस), राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) का एक समूह (गुलदस्ता) है, जिसमें कई प्रणालियाँ जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं और तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। इसने भारत को वर्ष 2020 में जमा अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर) के हिस्से के मामले में लीडर के रूप में उभरने में योगदान दिया है। इंडोनेशिया में भी वर्ष 2020 में 56% हिस्सेदारी के साथ, जमा अंतरण अन्य भुगतानों पर प्रबल रहा है।

ठ. बड़ी राशि के भुगतान

23. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस)

23.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में, भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में और उसके द्वारा परिचालित आरटीजीएस प्रणाली को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई बदलाव हुए हैं। दिनांक 14 दिसंबर, 2020 आरटीजीएस प्रणाली से चौबीसों घंटे चल रही है इसने भारत को दुनिया के कुछ उन देशों में से एक बना दिया है, जहां उनकी बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली रात-दिन सातो दिन चल रही है।

23.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

तालिका 25: बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली (एलवीपीएस)

क्रम सं	देश	बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली (एलवी पीएस)	निपटान	स्वामित्व	प्रबंधक	सदस्यता	खुलने का समय	बंद होने का समय
1	आस्ट्रेलिया	आरआईटीएस	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	07:30	18:30 (पूर्वी स्टैण्डर्ड समय) 20:30 डे लाइट सेविंग टाइम (दिवालोक बचत समय)
2	ब्राज़ील	एसटीआर	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित) [कोई भी वित्तीय संस्था जिसका रिजर्व खाता या निपटान खाता सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील के पास हो]	06:30	18:30
3	कनाडा,	एलवीटीएस	बहुपक्षीय नेटिंग	पेमेंट एसोसिएशन	पेमेंट एसोसिएशन	खुली (निर्बंधित) [कनाडियन पेमेंट्स एसोसिएशन के सदस्य (पेमेंट्स कनाडा) तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने पर एलवीटी एस में सीधी सहभागिता के पात्र हैं]	00:30	18:00
4	चीन	एचवीपीएस	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित)	08:30	20:30
5	फ्रांस	टारगेट 2 बीडीएफ	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	07:00	18:00
6	जर्मनी	टारगेट 2 बीबीके	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित)	07:00	18:00
7	हांगकांग	एचकेडी चेट्स (अमेरिकी डॉलर और रॅन्मिन्बी में निपटान हेतु अलग-अलग प्रणाली उपलब्ध है)	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	अन्य (हांगकांग अंतर-बैंक समाशोधन लि एचकेडी चेट्स का प्रणाली प्रचालक है)	प्रतिबंधित	08:30	18:30
8	भारत	आरटीजीएस	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	00:30	24:00
9	इंडोनेशिया	बीआई-आरटीजीएस	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	05:30	21:00
10	इटली	टारगेट 2-बीडीआई	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित)	07:00	18:00
11	जापान	टारगेट 2-बीडीआई	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	08:30	21:00 बीओ जे–नेट फंड ट्रांसफर सेवा का "मुख्य समय " 9:00 से 17:00
	जापान	एफएक्सवाईसीएस	आरटीजीएस	वाणिज्यिक बैंक	वाणिज्यिक बैंक	प्रतिबंधित	08:30	21:00 एफएक्सवाईसीएस फंड ट्रांसफर का "मुख्य समय " 9:00 से 15:00
12	मेक्सिको	एसपीईआई	बहुपक्षीय नेटिंग	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित)	18:00	17:59

क्रम सं	देश	बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली (एलवी पीएस)	निपटान	स्वामित्व	प्रबंधक	सदस्यता	खुलने का समय	बंद होने का समय
13	रूस	बैंक ऑफ़ रशिया पेमेंट सिस्टम (बीआरपीएस)	आरटीजीएस, बहुपक्षीय नेटिंग, बैच निपटान	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	01:00	21:00 तेज भुगतान सेवा 24x7 उपलब्ध है
14	सउदी अरब	एसएआरआईई	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	09:00	16:30
15	सिंगापुर	एमईपीएस +(आईएफटी)	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित)	09:00	19:00
16	दक्षिणी अफ्रीका	एसएएमओएस	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	00:00	23:59
17	दक्षिणी कोरिया	बीओके-वायर+	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	09:00	17:30
18	स्वीडन	आरआईएक्स	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	07:00	17:00
19	तुर्की	ईएफटी	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	08:30	17:30
20	यूनाइटेड किंगडम	सीएचएपीएस स्टर्लिंग	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	प्रतिबंधित	06:00	18:00
21	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका	फेड वायर फंड्स सर्विस	आरटीजीएस	केंद्रीय बैंक	केंद्रीय बैंक	खुली (निर्बंधित) [विदेशी बैंक की अमरीकी शाखा या एजेंसी सहित कोई भी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) संस्था, फेडरल रिज़र्व बैंक में अपना खाता रख सकती है]	21:00	18:30

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा संकलित रेड बुक 'चुनिंदा भुगतान प्रणालियों की विशेषताएं'

23.3 विश्लेषण: बड़ी राशि की भुगतान प्रणालियाँ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार अवसंरचनाएं (एफएमआई) हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) सकल निपटान के आधार पर तत्काल बड़ी राशि के निधि अंतरण की सुविधा देता है, जो क्रेडिट जोखिम को कम करने में मदद करता है। तथापि, सकल निपटान तरलता गहन है और भुगतान अपेक्षित होता है, भले ही इसकी प्रकृति कुछ भी हो, निपटान सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-निधिक (वित्त पोषित) होना चाहिए। आरटीजीएस के महत्व को देखते हुए, विभिन्न देशों ने इस प्रणाली तक अभिगम (पहुंच) हेतु अलग-अलग मानदंड अपनाए हैं।

अधिकांश अधिकारिताओं में आरटीजीएस का स्वामित्व और प्रचालन केंद्रीय बैंक के पास होता है और इसका उपयोग ग्राहक और अंतर-बैंक भुगतान के लिए किया जाता है। केंद्रीय बैंक की मुद्रा में निपटान सुनिश्चित करने के लिए, सहायक भुगतान प्रणालियों की निपटान फाइलें अंतिम निपटान के लिए आरटीजीएस में पोस्ट की जाती हैं।

आरटीजीएस परिचालन के घंटों का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह प्रणाली बड़ी राशि के कॉर्पोरेट लेन-देन को प्रसंस्कृत करती है। आरटीजीएस परिचालन की अवधि का विस्तार बाजार के समय में वृद्धि को सुकर बनाता है। इसके अलावा, आरटीजीएस की अवधि-वर्धित उपलब्धता सहायक भुगतान प्रणालियों के लिए अतिरिक्त निपटान चक्रों की पोस्टिंग सुनिश्चित करती है और निपटान, क्रेडिट और व्यतिक्रम (डिफ़ॉल्ट) जोखिमों के निर्माण को कम करती है, इस प्रकार भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता को बढ़ाती है। सभी अधिकारिताओं में

आरटीजीएस प्रणाली के प्रचालन में विस्तृत अधिव्यापन (ओवरलैप) का लाभ भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने और सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

भारत में, आरटीजीएस को 14 दिसंबर, 2020 से दिन-रात उपलब्ध कराया गया है । इस उपाय ने कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों को भुगतान करने हेतु अधिक लचीलापन प्रदान किया और सहायक भुगतान प्रणालियों के लिए अतिरिक्त निपटान चक्रों की पोस्टिंग सुनिश्चित की।

भारत में पहले आरटीजीएस तक अभिगम (पहुंच) घरेलू स्तर पर स्थित बैंकों, समाशोधन गृहों और दलाल व्यापारियों (ब्रोकर डीलरों) को थी। आरटीजीएस हेतु सदस्यता मानदंड की जुलाई 2021 में समीक्षा की गई थी और भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ), अर्थात पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ताओं, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम प्रचालकों को सीधे सदस्य के रूप में आरटीजीएस में भाग लेने की अनुमति दी गई । बैंकेतर संस्थाओं को अभिगम प्रदान करने से सदस्यों के लिए लागत कम करने, बैंकों पर उनकी निर्भरता को कम करने, भुगतान करने में लगने वाले समय को कम करने और भुगतान पूर्ण होने की अनिश्चितता को समाप्त करने में सहायता मिलती है।

ड. तेज भुगतान

24. तेज भुगतान की उपलब्धता वाले चैनल

24.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत कुछ उन देशों में से एक है, जिनके पास दो तेज भुगतान प्रणालियाँ हैं, यथा त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)। भारत में तत्काल भुगतान को अपनाना उल्लेखनीय रहा है, भारत में तेज भुगतान प्रणाली का उपयोग कर किए गए लेन-देन की संख्या अन्य देशों की तुलना में, जिसके लिए डेटा उपलब्ध है, प्रबल है,

इसके अलावा, भारत में आरबीआई द्वारा परिचालित एक अन्य खुदरा भुगतान प्रणाली भी है, यथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), जो यद्यपि एक तेज़ भुगतान प्रणाली नहीं है (क्योंकि यह आधे घंटे के बैचों में निपटान के लिए व्यवस्थित है), परंतु बिना निपटान जोखिम के रात दिन सात दिन(24/7) चलती है, क्योंकि लाभार्थी को भुगतान निपटान के बाद ही किया जाता है।

24.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

तालिका 26: तेज भुगतान प्रणालियाँ

क्रम सं	देश	तेज भुगतान प्रणाली	सक्रिय	समर्थित सेवाएं	समर्थित अभिगम चेंनल	बैंकेतर भुगतान सेवा प्रदाताओं को अभिगम	प्रणाली सहभागियों के बीच निपटान का मॉडल	मात्रा (मिलियन) [2020]
1	आस्ट्रेलिया	न्यू पेमेंट्स प्लेटफार्म आस्ट्रेलिया (एनपीपीए)	2018	व्यापारी भुगतान; बिल भुगतान	इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग ; क्यूआर कोड	परोक्ष	तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस)	570
2	ब्राज़ील	एसपीआई	2020				तत्काल सकल निपटान	

क्रम सं	देश	तेज भुगतान प्रणाली	सक्रिय	समर्थित सेवाएं	समर्थित अभिगम चेंनल	बैंकेतर भुगतान सेवा प्रदाताओं को अभिगम	प्रणाली सहभागियों के बीच निपटान का मॉडल	मात्रा (मिलियन) [2020]
3	चीन	आईबीपीएस	2010	बिल भुगतान; आवर्ती भुगतान	शाखा; मोबाइल /इंटरनेट बैंकिंग; क्यूआर कोड	नहीं	आस्थगित निवल निपटान	15624
4	फ्रांस	एससीटी इन्स्ट	2017	व्यापारी भुगतान; थोक/बैच भुगतान; बिल भुगतान; उत्तर दिनांकित भुगतान	इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; शाखा ; एटीएम; क्यूआर कोड	परोक्ष	तत्काल सकल निपटान	
5	हांग कांग	एफपीएस	2018	व्यापारी भुगतान; थोक/बैच भुगतान; बिल भुगतान; भुगतान करने का अनुरोध	इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; क्यूआर कोड	परोक्ष	तत्काल सकल निपटान	138
6	भारत	त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस)	2010	समकक्षीय (पी2पी) भुगतान; विदेशी आवक विप्रेषण	इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; एसएमएस; असंरचित पूरक सेवा डेटा (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफार्म), एटीएम	परोक्ष	आस्थगित निवल निपटान	2974
7	भारत	एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)	2016	व्यापारी भुगतान; थोक/बैच भुगतान; बिल भुगतान; भुगतान करने का अनुरोध; विदेशी आवक विप्रेषण	इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; क्यूआर कोड निकट क्षेत्र संचार; असंरचित पूरक सेवा डेटा	परोक्ष	आस्थगित निवल निपटान	18881
8	मेक्सिको	एसपीईआई	2015	व्यापारी भुगतान; थोक/बैच भुगतान; बिल भुगतान; भुगतान करने का अनुरोध	शाखा; एटीएम; इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; क्यूआर कोड; निकट क्षेत्र संचार (एनएफसी)	प्रत्यक्ष	संकर (हाइब्रिड)	
9	सिंगापुर	तेज	2014	व्यापारी भुगतान; बिल भुगतान	इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; शाखा; एटीएम;	हाँ	आस्थगित निवल निपटान	147
10	यूनाइटेड किंगडम	यू के तेज भुगतान	2008	थोक/बैच भुगतान; बिल भुगतान; स्थायी आदेश; उत्तर(भावी) दिनांकित भुगतान; एकल तत्काल भुगतान	इंटरनेट /मोबाइल बैंकिंग; शाखा	प्रत्यक्ष	आस्थगित निवल निपटान	2850

स्रोत: विश्व बैंक तेजी से भुगतान; सीपीएमआई रेड बुक

24.3 विश्लेषण : तेज भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जिनमें भुगतान संदेश का प्रसारण और आदाता (प्राप्तकर्ता) को "अंतिम" निधियों की उपलब्धता वास्तविक समय या निकट-वास्तविक समय पर होती है और प्रणाली (सिस्टम) यथासंभव '24-घंटे और सात-दिन (24x7)' के आधार पर परिचालित रहती है।

तेज भुगतान प्रणाली के आरंभ ने विभिन्न नवोन्मेषों को जन्म दिया है और भुगतान करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं । तेज़ भुगतान प्रणालियाँ सभी आधिकारिताओं में, बिल भुगतान, क्यूआर आधारित भुगतान, निकट क्षेत्र संचार (एनएफसी) आधारित भुगतान, भुगतान के अनुरोध आदि जैसी कई कार्यात्मकताओं का समर्थन करती हैं।

तेज भुगतान प्रणालियों का लाभ गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी उठाया जाता है जैसे कि खाता उपनाम सेवाएं, जमा राशि पूछताछ, भुगतान अनुसूची निर्धारण, आदि। विभिन्न अधिकारिताएं अपनी तेज़ भुगतान प्रणालियों की सहबद्धता अन्य अधिकारिताओं की भुगतान प्रणालियों के बीच स्थापित करने में लगी हुईं हैं ताकि सीमा-पार तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके।

विभिन्न अधिकारिताओं ने बैंकेतर संस्थाओं को उनकी त्वरित भुगतान प्रणाली तक अभिगम (पहुंच) प्रदान करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया है, जिसमें से कुछ ने प्रत्यक्ष अभिगम (मेक्सिको, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम) और अन्य ने परोक्ष अभिगम (ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, भारत, हांगकांग) की अनुमति दी है। बेंचमार्क वाले देशों में, चीन में केवल आईबीपीएस ने बैंकेतर संस्थाओं को अभिगम की अनुमति नहीं दी और मेक्सिको में केवल एसपीईआई प्रणाली ने संकर (हाइब्रिड) निपटान मॉडल का पालन किया। सभी प्रणालियों ने निपटान की पद्धतियाँ भी अलग-अलग अपनाईं हैं, कुछ ने तत्काल सकल निपटान और अन्य ने आस्थगित निवल निपटान को अपनाया है।

भारत में तेज भुगतान प्रणाली, मात्रा के मामले में तो समग्र खुदरा भुगतान चला रही है । मार्च 2022 में भारत में कुल खुदरा भुगतान लेन-देन का 73% से अधिक तेज भुगतान हुआ। अकेले एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने मार्च 2022 में 5.4 बिलियन लेन-देन को प्रसंस्कृत किया है, जो खुदरा भुगतान लेन-देन का 64% था। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली कई बैंक खातों को सहभागी बैंक/बैंकेतर अन्य पक्षीय एप्लिकेशन प्रदाता (थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर) की किसी एकल मोबाइल एप्लिकेशन में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, वर्तमान में, 20 टीपीएपी (गूगल, व्हाट्सएप, अमेज़ॅन आदि) यूपीआई लेन-देन की सुविधा के लिए बैंकों के साथ भागीदारी कर रहे हैं।

ढ . प्रत्यक्ष नामे (डायरेक्ट डेबिट)

25. प्रत्यक्ष नामे की मात्रा और संवृद्धि

25.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत में प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) ने वर्ष 2017 और 2020 के बीच 38.6% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बेंचमार्क देशों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। तथापि, मात्रा के मामले में, भारत में प्रत्यक्ष नामे (डायरेक्ट डेबिट्स) संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों की तुलना में कम है।

25.2 बेंचमार्क रेटिंग: मात्रा – मजबूत; सीएजीआर – लीडर

भारत की स्थिति: मात्रा 8 /17, सीएजीआर -1/17

तालिका 27: सीधे नामे की मात्रा और संवृद्धि

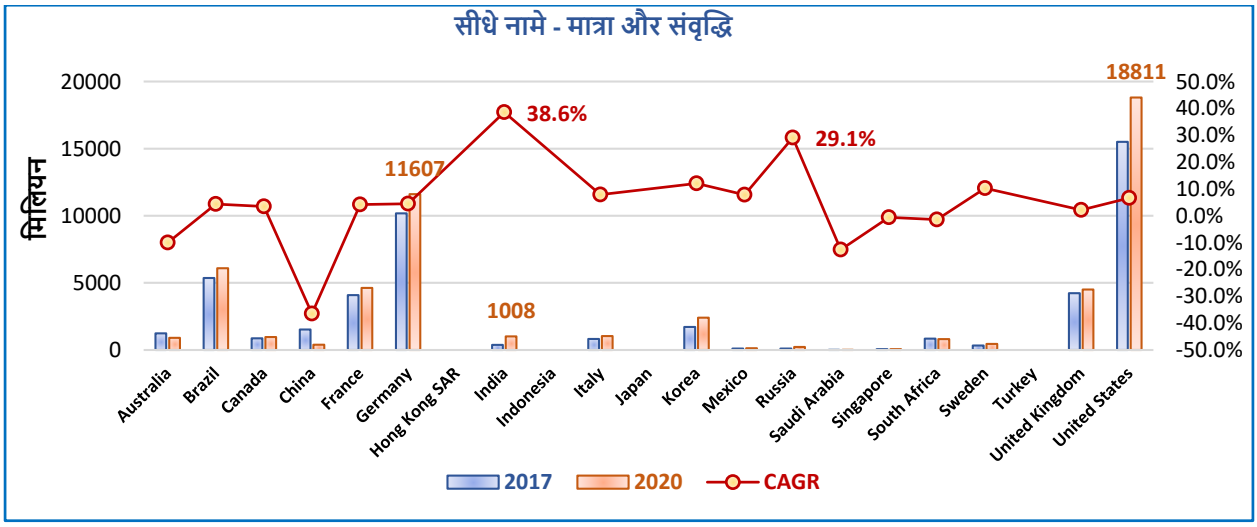

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'

सीएजीआर = कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

25.3 विश्लेषण: प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) एक पूर्व अधिदेश आधारित भुगतान होते हैं, जो सामान्यतः क्रेडिट कार्ड और उपयोगिता (यूटिलिटी) बिल जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

भारत में, प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) भुगतान में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के नामे भुगतान शामिल हैं। बेंचमार्क देशों बीच 38.6% की उच्चतम सीएजीआर के बावजूद, भारत में प्रत्यक्ष नामे लेन-देन की मात्रा (वॉल्यूम) कम है। कोविड जनित महामारी के दौरान प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) में वृद्धि हुई क्योंकि उनका उपयोग देश भर में गरीब और सीमांत व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संबंधी भुगतान सुकर करने हेतु किया गया था।

वर्ष 2017 और 2020 के दौरान अधिकांश बेंचमार्क देशों में, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सऊदी अरब, सिंगापुर और दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर, प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) लेन-देन में वृद्धि देखी गई है।

26. भुगतान प्रणाली में प्रत्यक्ष नामे का हिस्सा (मात्रा)

26.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भुगतान प्रणालियों में प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में 2.5% थी। भुगतान प्रणालियों में प्रत्यक्ष नामे भुगतान के हिस्से में परिवर्तन अधिकांश बेंचमार्क देशों में नगण्य है।

26.2 बेंचमार्क रेटिंग : सामान्य

भारत की स्थिति : 12 /17

तालिका 28: भुगतान प्रणालियों में प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) का हिस्सा (मात्रा)

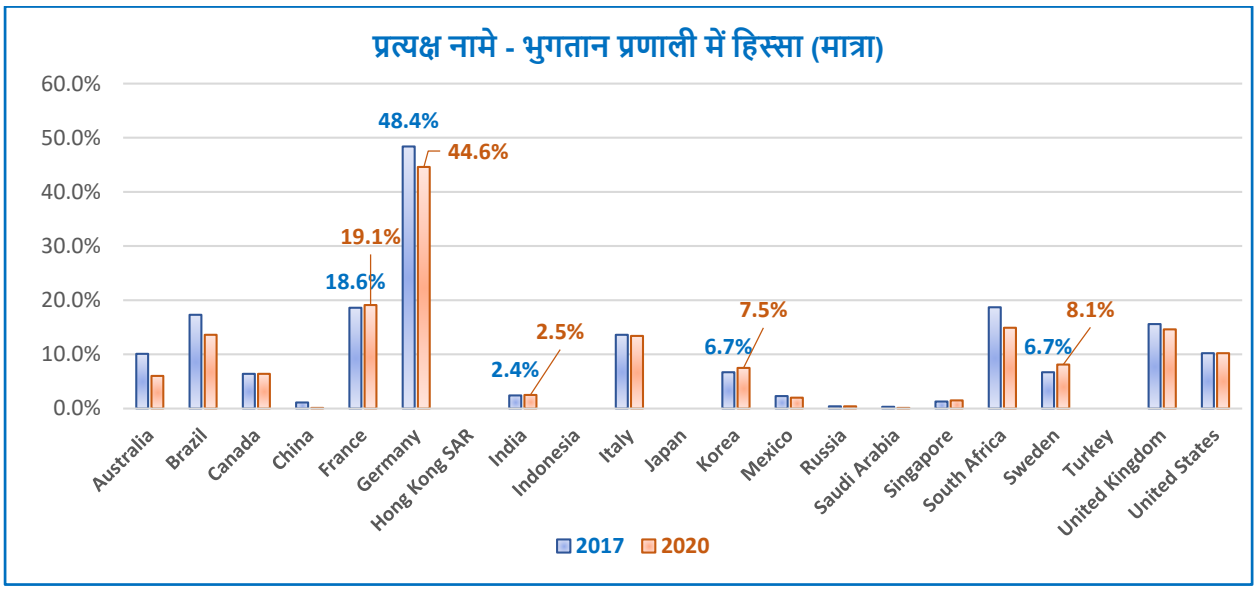

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

26.3 विश्लेषण: वर्ष 2017 से 2020 तक की अवधि में प्रत्यक्ष नामे का हिस्सा केवल फ्रांस, कोरिया और स्वीडन में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

भारत में, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष नामे लेन-देनों की संख्या बढ़ रही है, परंतु भुगतान परिदृश्य में जमा(क्रेडिट) अंतरण लेन-देनों का ही प्रभुत्व है। यह प्रत्यक्ष नामे लेन-देनों का हिस्सा काफी कम होने की व्याख्या करता है।

जर्मनी में प्रत्यक्ष नामे लेन-देन भुगतान परिदृश्य पर प्रबल हैं जहां एकल यूरो भुगतान क्षेत्र (सिंगल यूरो पेमेंट्स एरिया) डायरेक्ट डेबिट्स (प्रत्यक्ष नामे) लोकप्रिय हैं ।सिंगल यूरो पेमेंट्स एरिया (एसईपीए) प्रत्यक्ष नामे खिंचाव (कर्षण)-आधारित है, जिसमें व्यापारी अपने ग्राहक से अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त होने पर कई भुगतान शुरू कर सकते हैं। भुगतान सीधे बैंकों के बीच होता है और कोई कार्ड नेटवर्क शामिल नहीं होता है। कार्ड-आधारित विकल्पों की तुलना में एसईपीए प्रत्यक्ष नामे भुगतान, व्यवसायों के लिए तेज़ और सस्ते है। हालांकि, जर्मनी में प्रत्यक्ष डेबिट (नामे) की हिस्सेदारी जो वर्ष 2017 में 48.4% थी वह वर्ष 2020 में घटकर 44.6% हो गई।

त. इलेक्ट्रॉनिक मनी (ई-मुद्रा)

27. वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की उपलब्धता

27.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : वर्ल्डपे ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में 45% ऑनलाइन लेन-देन डिजिटल / मोबाइल वॉलेट (ई-मनी) का उपयोग करके किए जाते हैं। भारत में, भुगतान के वैकल्पिक रूप, जो यूपीआई अन्य पक्षीय एप्लिकेशन के माध्यम से सुगम हैं, मुख्य रूप से ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

27.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

तालिका 29 : भुगतान के वैकल्पिक तरीके (2021)

क्रम सं	देश	भुगतान के लोकप्रिय वैकल्पिक तरीके		भुगतान के तरीके का हिस्सा – ई-मुद्रा	
				ऑन लाइन लेनदेन	खुदरा दूकान
1	ऑस्ट्रेलिया	पे पाल	एप्पल पे	26	11
2	ब्राज़ील	बोलेटो बैंकारिओ	पिक्स x	16	8
3	कनाडा	पे पाल	एप्पल पे	22	8
4	चीन	अली पे	वी चैट पे	83	54
5	फ्रांस	पे पाल	अमेज़न पे	25	4
6	जर्मनी	पे पाल		29	4
7	हांग कांग	अली पे	वी चैट पे	33	24
8	भारत	गूगल पे	फोन पे	45	25
9	इंडोनेशिया	ओ वो	गो पे	39	19
10	इटली	पे पाल	अमेज़न पे	34	10
11	जापान	कोनबिनी	पे पे	12	9
12	मेक्सिको	पे पाल	बीबीवीपे	27	7
13	रूस	एप्पल पे	जी पे	25	9
14	सउदी अरब	एप्पल पे	पे पाल	18	14
15	सिंगापुर	पे पाल	एप्पल पे	29	14
16	दक्षिणी अफ्रीका	पे पाल		19	5
17	दक्षिणी कोरिया	एन पे	सैमसंग पे	22	10
18	स्वीडन	क्लार्ना	स्विश	20	13
19	तुर्की	ल्यज़िको	बीकेएम एक्सप्रेस	6	8
20	यूनाइटेड किंगडम	पे पाल	एप्पल पे	32	9
21	संयुक्त राज्य अमेरिका	अमेज़न पे	एप्पल पे	30	11

स्रोत: वर्ल्डपे ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022, एनपीसीआई

27.3 विश्लेषण: वर्ल्डपे ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2022 ने परिभाषित किया है कि वैकल्पिक भुगतान विधियां, नकदी के अलावा अन्य भुगतान विधियाँ हैं अथवा वैश्विक कार्ड ब्रांड नेटवर्क से जुड़े भौतिक कार्ड हैं । वैकल्पिक भुगतान विधियों में बैंक अंतरण, डिजिटल और मोबाइल वॉलेट, प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) और बाय नाउ, पे लेटर (बीएनपीएल) अर्थात अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें, शामिल हैं।

भारत में, बैंकेतर संस्थाओं ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में, पूर्वदत्त भुगतान लिखत (ई-मुद्रा) जारीकर्ताओं, भारत बिल भुगतान प्रचालक इकाइयों (बिल भुगतान) और यूपीआई प्लेटफार्म पर अन्य पक्षीय एप्लीकेशन प्रदाताओं के रूप में भाग लेने वाली फिनटेक फर्मों के साथ, वैकल्पिक भुगतान में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। बिगटेक फर्म भी यूपीआई में अन्य पक्षीय एप्लिकेशन प्रदाताओं के रूप में भाग लेती हैं और अपने प्लेटफॉर्म – गूगल पे, अमेज़ॅन पे, व्हाट्सएप

आदि के माध्यम से लेन-देन की सुविधा प्रदान करती हैं। बैंकेतर पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता भी अपने पीपीआई वॉलेट धारकों को अंतर-परिचालनीय (इंटरऑपरेबल) तरीके से यूपीआई सुविधा प्रदान करते हैं। चीन में, वैकल्पिक भुगतान विधियां ऑनलाइन लेन-देन में 83% से अधिक और खुदरा स्टोर लेन-देन में 54% की हिस्सेदारी के साथ भुगतान लेन-देन पर प्रबल हैं। चीन में वैकल्पिक भुगतानों का प्रभुत्व अलीबाबा के अली पे और टेंसेंट के वीचैट पे द्वारा संचालित है।

28. ई-मुद्रा की मात्रा और संवृद्धि

28.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: वर्ष 2020 में 4950 मिलियन से अधिक लेन-देन के साथ भारत ने ई-मनी लेन-देन की मात्रा के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये लेन-देन अनुमोदित बैंकों के साथ-साथ अधिकृत बैंकेतर जारीकर्ताओं द्वारा कार्ड या वॉलेट के रूप में निर्गत पूर्व दत्त भुगतान लिखतों का उपयोग करके किए जाते हैं।

28.2 बेंचमार्क रेटिंग: मात्रा – मजबूत; संवृद्धि – सामान्य

भारत की स्थिति: मात्रा - 4/14, संवृद्धि - 7/13

तालिका 30: मात्रा और संवृद्धि – ई- मुद्रा

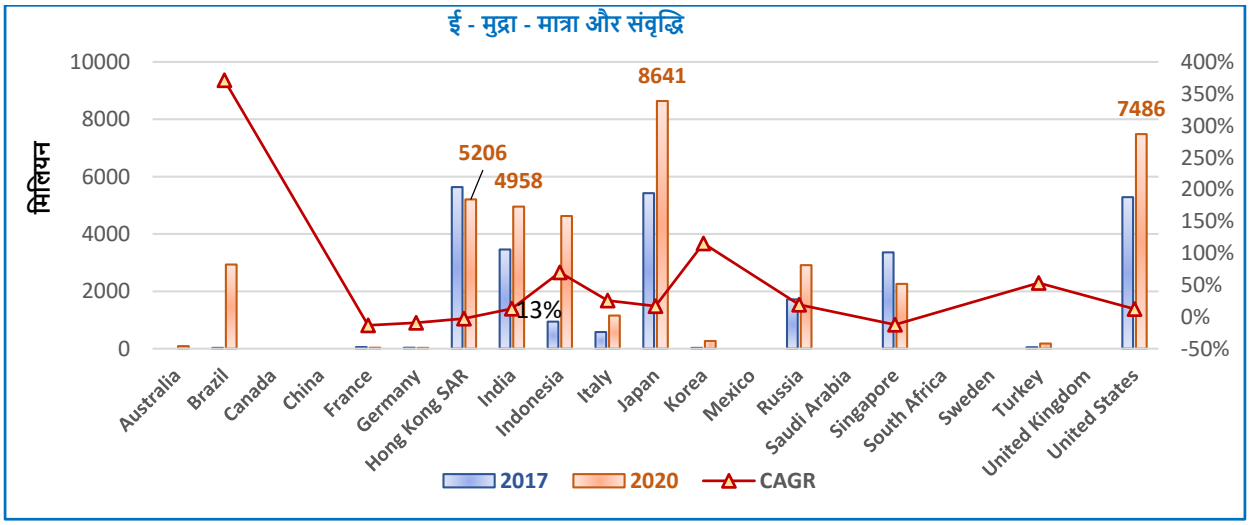

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)
सीएजीआर = कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर

28.3 विश्लेषण: ई-मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचयित पूर्वदत्त मूल्य है, जो ई-मुद्रा जारीकर्ता (एक बैंक, एक ई-मुद्रा संस्था या स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ई-मुद्रा जारी करने के लिए प्राधिकृत या अनुमत कोई अन्य संस्था) की देयता का प्रतिनिधित्व करती है और जो एक प्राधिकरण द्वारा समर्थित मुद्रा में मूल्यवर्गित है। भारत में, ई-मुद्रा में वॉलेट और कार्ड के रूप में जारी किए गए पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) शामिल हैं। व्यक्तियों और व्यापारियों दोनों के द्वारा डिजिटल वॉलेट के बढ़ते प्रयोग में सहयोगी प्रमुख कारक सुरक्षा और लेन-देन में आसानी हैं।

भारत में, छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए, दिसंबर 2019 में एक "लघु" पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) आरंभ किया गया, जिसमें न्यूनतम केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) की आवश्यकता थी और एक महीने में भरी गई राशि की सीमा ₹10,000 थी। इसके अलावा, मई 2021 में, पूर्ण केवाईसी अनुपालन वाले पीपीआई में बकाया राशि की सीमा को बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दिया गया। पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के बीच अंतर-परिचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) आरंभ होने से सभी पीपीआई जारीकर्ताओं और हित अधिग्रहणकर्ताओं के लिए ग्राहकों को अलग-अलग जोड़ना (ऑन-बोर्डिंग) आवश्यक नहीं रहा साथ ही उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ी तथा लागत किफायती हुई है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 और 2020 के बीच ई-मुद्रा लेन-देन की मात्रा में अविरत वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में, 4958 मिलियन ई-मुद्रा लेन-देन के साथ, भारत बेंचमार्क देशों, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है, में से केवल जापान (8641 मिलियन), संयुक्त राज्य अमेरिका (7486 मिलियन) और हांगकांग (5206 मिलियन) से पीछे था । भारत में ई-मुद्रा लेन-देन वर्ष 2017 और 2020 के बीच 13% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है।
, वर्ष 2017 और 2020 के बीच लेन-देन की मात्रा में 372% कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ संवृद्धि के मामले में ब्राजील लीडर (अग्रणी) माना जाता है, जिसका मुख्य कारण वर्ष 2017 में लेन-देन की कम मात्रा (28 मिलियन) थी । इस अवधि के दौरान ई-मुद्रा लेन-देन की घातांकी संवृद्धि मुख्य रूप से ई-कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता और स्मार्टफोन के साथ जनसँख्या का घनिष्ठ सुपरिचय होने के कारण हुई।

29. भुगतान प्रणाली में ई-मुद्रा का हिस्सा (मात्रा)

29.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत में ई-मुद्रा भुगतान लेनदेन की हिस्सेदारी वर्ष 2017 में 22.1% से घटकर वर्ष 2020 में 12.2% हो गई और यह अन्य देशों, जैसे जापान (78.8%), सिंगापुर (60.1%) और इंडोनेशिया (36.5%) की तुलना में काफी कम है । हिस्सेदारी में गिरावट को अन्य तरीकों जैसे यूपीआई में वृद्धि के साथ समझा जा सकता है।

29.2 बेंचमार्क रेटिंग: मजबूत

भारत की स्थिति: 5/13

तालिका 31: भुगतान प्रणालियों में ई-मुद्रा लेनदेन का हिस्सा (मात्रा)

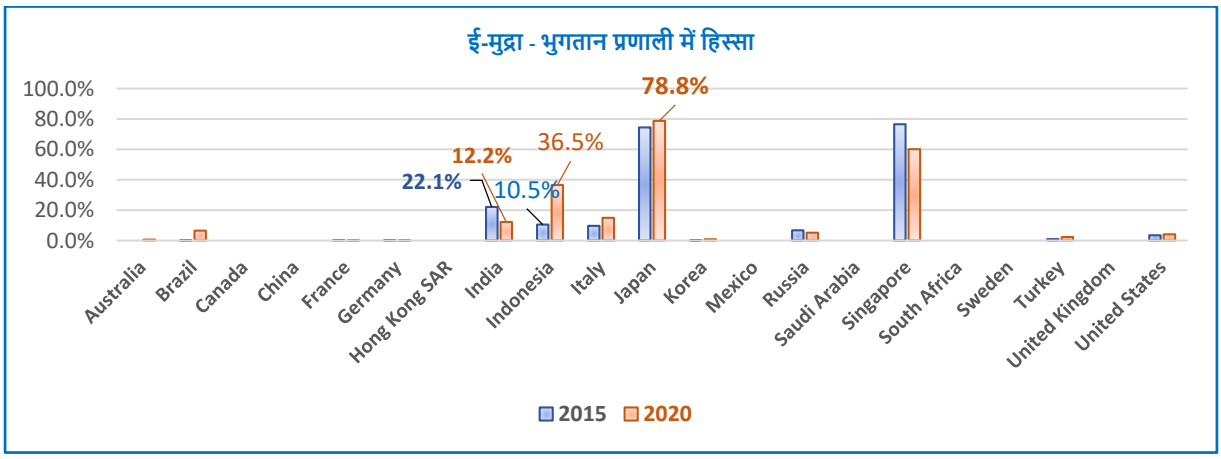

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) द्वारा संकलित रेड बुक 'कंट्री टेबल्स'
(आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स)

29.3 विश्लेषण: भारत में वर्ष 2020 में भुगतान प्रणाली लेनदेन में ई-मुद्रा की हिस्सेदारी 12.2% थी। मोबाइल अवसंरचना की बढ़ती उपलब्धता और ई-मुद्रा इंस्ट्रूमेंट्स की अंतर-परिचालनीयता से ई-मुद्रा लेनदेन में संवृद्धि हुई है परन्तु वैकल्पिक भुगतान के अन्य रूपों के प्रभुत्व के कारण ई-मुद्रा लेनदेन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

इंडोनेशिया में वर्ष 2017 से 2020 की अवधि के दौरान भुगतान लेनदेन में ई-मुद्रा के हिस्से (26%) में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई। इंडोनेशिया में, विशाल बैंक-रहित जनसंख्या और स्मार्टफोन की उच्च उपलब्धता के साथ एक नकदी संचालित अर्थव्यवस्था के कारण ई-वॉलेट लेन-देन उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं और उपभोक्ता गैर-नकदी विकल्पों की सरलता की ओर उन्मुख हो रहे हैं।

सिंगापुर की तकनीक-प्रेमी संस्कृति और स्मार्ट फोन अपनाने की उच्च दर ने कम मूल्य वाले दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिए ई-मुद्रा विधियों के प्रयोग में सहायता की है।

थ . डिजिटल उपयोगिता भुगतान

30. उपयोगिता (यूटिलिटी) बिलों का डिजिटल भुगतान

30.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) अक्टूबर 2017 में आरंभ की गई थी ताकि ग्राहकों को भुगतान की बहु विधियों का उपयोग करने और भुगतान की तत्काल पुष्टि के लिए अंतर-परिचालनीय और सुलभ बिल भुगतान सेवाएं प्रदान की जा सकें। बिल बनाने वाले (बिलर्स) और संसाधित लेन-देन के मामले में इस प्रणाली ने उल्लेखनीय संवृद्धि की है।

30.2 बेंचमार्क रेटिंग : सामान्य

30.3 विश्लेषण: विश्व बैंक के लिए किए गए ग्लोबल फाइंडेक्स सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, भारत में केवल 3% जनसंख्या ने वर्ष 2017 में उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) आरंभ होने से चूंकि उपयोगिता बिल भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरण हो रहा है, यह अनुपात बढ़ने की आशा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी आवर्ती बिल बनाने वाले बिलर्स को सम्मिलित करने हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के दायरे और कार्य क्षेत्र में विस्तार करने के लिए पहल की है। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2022 के अंत तक 20,000 से अधिक बिलर्स बीबीपीएस से जुड़ गए हैं। नकदी-आधारित बिल भुगतानों के डिजिटलीकरण के अलावा, बीबीपीएस से जुड़े बिलर्स को ग्राहकों के लिए मानकीकृत बिल भुगतान का अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क आदि का भी लाभ मिलता है।

31. सार्वजनिक जन परिवहन

31.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत के अधिकांश महानगरीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग किया जाता है। देश भर में चलने वाली मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड का उपयोग करती है जो संपर्क रहित नकदी मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।

31.2 बेंचमार्क रेटिंग: सामान्य

31.3 विश्लेषण: टिकट बुकिंग, जिसमें भुगतान प्रसंस्करण शामिल है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रमुख तत्व है। टिकट प्रणाली के दो मुख्य प्रकार हैं लिखत-आधारित टिकटिंग (कागज/कार्ड) और खाता-आधारित टिकटिंग। एक लिखत-आधारित टिकट प्रणाली में, निधि, यात्रा की पात्रता का प्रमाण और यात्रा संबंधी किसी भी प्राथमिक रिकॉर्ड सीधे कार्ड/कागज पर होता है। एक खाता-आधारित प्रणाली में, यात्रा करने हेतु पात्रता का प्रमाण और यात्रा संबंधी किसी भी रिकॉर्ड को बैक-ऑफ़िस में रखा जाता है और यात्रा के पूरा होने के बाद किराए की गणना और बिल बनाया जाता है।

कोविड जनित महामारी के कारण कई सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा टिकट बुकिंग के लिए क्यूआर कोड अभिनियोजित करने के साथ संपर्क रहित भुगतान विकल्पों ने लोकप्रियता हासिल की । नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) डिवाइस अन्य विकल्प हैं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन के लिए संपर्क रहित भुगतान करने के लिए किया गया है।

तालिका 32: सार्वजनिक जन परिवहन टिकट प्रणाली

देश	सार्वजनिक जन परिवहन टिकट प्रणाली
आस्ट्रेलिया	सिडनी, टीएफएनएसडब्ल्यू: संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड (ओपल), संचयित मूल्य, ग्रेटर सिडनी और आसपास के शहरी क्षेत्रों को कवर करने वाला वाइड एरिया मल्टी-मोडल सिस्टम। चेक-इन, चेक-

देश	सार्वजनिक जन परिवहन टिकट प्रणाली
	आउट पद्धति और रियायतों की एक व्यापक श्रृंखला । प्रणाली की कार्यात्मकता बढ़ाने के लिए हाल ही में ईएमवी और मोबाइल टिकटिंग को जोड़ा गया है।
ब्राज़ील	साओ पाउलो, एसपी ट्रांस: प्रणाली की विशेषता एक स्वत्वधारी सैम और कार्ड योजना है, जो परिवहन प्राधिकरण (साओ पाउलो, ट्रांसपोर्ट) के स्वामित्व में है, तथा कई डिवाइस प्रदाताओं और क्रेडिट विक्रेताओं को अनुमति देता है। सिस्टम समय और मोडल एकीकरण के साथ कई टैरिफ मॉडल की अनुमति देता है साथ ही कई परिचालकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता
कनाडा	मॉन्ट्रियल और क्यूबेक: कैलिप्सो मानक का उपयोग करके संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड (ओपस) में संचयित मूल्य। सभी पड़ोसी मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम का निर्बाध एकीकरण। वैंकूवर, ट्रांसलिंक: मल्टीमॉडल संचयित मूल्य स्मार्ट कार्ड (कम्पास) सभी क्षेत्रीय ट्रांजिट नेटवर्क पर निर्बाध रूप से संचालित होता है। हाल ही में, ईएमवी क्षमता आरम्भ की गई और मोबाइल पे ऐप में चेक-इन, चेक-आउट से लेकर अंतरण और किराया क्षेत्र की गणना की विशेषताओं को बढ़ाया गया था।
चीन	अली पे, टेंसेंट: चीन के 120 से अधिक शहरों में स्थानीय बस सेवाएं और मेट्रो ट्रेन सिस्टम अली पे ऐप आधारित फोन पर भुगतान स्वीकार करते हैं। इंटरनेट की दिग्गज कंपनी अलीबाबा के मोबाइल भुगतान ऐप अली पे का उपयोग कर ग्राहक सीधे भुगतान कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गेट्स को अपने फोन पर एक क्यूआर कोड स्कैन करने की अनुमति देकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। एप्पल पे, जेडी पे, यूनियन पे और चाइना टेलीकॉम बेस्ट पे, चाइना टेलीकॉम कॉर्प की एक समनुषंगी कंपनी भी ऐसी सेवाएं प्रदान करती है।
जर्मनी	जर्मन परिवहन कंपनियों के संघ [वीडीवी]) और उद्योग के भागीदारों और परिवहन परिचालकों ने वीडीवी कोर एप्लिकेशन लॉन्च किया। वीडीवी कोर एप्लिकेशन में टिकट-खरीद अंतर्निहित है ताकि मोबाइल फोन टिकटिंग के त्वरित और आसान लॉन्च को सुकर बनाया जा सके ।
हांग कांग एसएआर	हांगकांग, एमटीए: (ऑक्टोपस) वर्ष 1997 में दुनिया भर में अभिनियोजित पहले स्मार्टकार्ड सिस्टम में से एक, संचयित मूल्य, मल्टी-मोडल सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर किराया वसूल करने और पूरे हांगकांग में खुदरा बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है। योजना सीमित संख्या में टैक्सियों द्वारा स्वीकार की गई है; ड्राइवरों के लिए नया मोबाइल ऐप इसके उपयोग को बढ़ाएगा । मकाओ और शेनझेन में कार्ड का सीमित उपयोग।
भारत	रु पे राष्ट्रीय आम गतिशीलता (नेशनल कॉमन मोबिलिटी) कार्ड एक संपर्क रहित कार्ड है जिसमें ऑफलाइन वॉलेट की सुविधा भी है। इसलिए इसे नामे और पूर्वदत्त कार्ड कहा जाता है। एनसीएमसी का उपयोग परिवहन, पार्किंग, किराना, टोल और ट्रांजिट पर सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। देश भर के मेट्रो शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए क्यूआर कोड-आधारित टिकटिंग का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
इंडोनेशिया	जकार्ता, इंडोनेशिया - एकीकृत मल्टीमॉडल ट्रांजिट टिकटिंग और किराया भुगतान प्रणाली:

देश	सार्वजनिक जन परिवहन टिकट प्रणाली
	वर्ष 2017 में वन कारसिस वन ट्रिप (वन टिकट वन ट्रिप) के रूप में आरंभ की गई। उपभोक्ता बस स्टॉप और एमआरटी जकार्ता, एलआरटी जकार्ता, ट्रांस जकार्ता और कम्यूटर लाइन द्वारा संचालित नेटवर्क के रेलवे स्टेशन पर "एकीकरण द्वार" पर इन और आउट टैप करके या एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किराए का भुगतान करते हैं दूसरे चरण में मोबिलिटी-एएस-ए-सर्विस (मास) प्लेटफॉर्म को शामिल करने और एक एकीकृत टैरिफ सिस्टम की शुरुआत होने की आशा है।.
जापान	जापान, राष्ट्रव्यापी: जापान के कई क्षेत्रों में यात्रा और खरीदारी के लिए पूर्वदत्त ई-मुद्रा संपर्क रहित स्मार्टकार्ड (सुइका), पास्मो के साथ परस्पर परिवर्तनीय है जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क और कुछ टैक्सियों तक पहुंच प्रदान करता है। सुइका कार्ड लोकप्रिय खुदरा दुकानों पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध है और वर्ष 2016 से एप्पल डिवाइस पर वर्चुअलाइज्ड (आभासी) कार्ड।
मैक्सिको	किराया वसूल करने हेतु विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है: (ए) बीआरटी पूर्वदत्त संपर्क रहित इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टकार्ड का उपयोग करता है जिसे मेट्रोबस कहा जाता है; (बी) लाइट-रेल ट्रांजिट (एलआरटी) किराया वसूल करने के लिए पेपर टिकट और एक्सेस कंट्रोल के लिए टर्नस्टाइल का उपयोग करता है; (सी) मेट्रो, मैग्नेटिक-स्ट्रिप सिंगल-यूज टिकट और पूर्वदत्त संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, दोनों का उपयोग करती है; और (डी) उपनगरीय रेल किराया वसूली के लिए एक रिचार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग करती है। यूएस-आधारित एसीएस द्वारा आरंभ किया गया एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट फेयर स्मार्ट कार्ड, तारजेता डीएफ या फेडरल डिस्ट्रिक्ट कार्ड, यात्रियों को मेट्रो से बीआरटी में निर्बाध रूप से स्थानांतरित होने हेतु समर्थ करता है।
रूस	मॉस्को, एमटीए: सभी मोड के लिए क्षेत्र व्यापी संपर्क रहित संचयित मूल्य वाले स्मार्टकार्ड (ट्रोइका), मात्रा में उपयोग के लिए विभिन्न छूट योजनाएं। हाल ही में जोड़े गए मोबाइल टिकटिंग और हैंगर कार्ड के साथ-साथ पार्किंग और साइकिल किराए पर लेने के लिए कार्ड का उपयोग। क्रेडिट कार्ड, पे पास/पे वेव, ऐप्पल पे/सैमसंग पे/एंड्रॉइड पे, और यांडेक्स मनी इत्यादि सहित कई वैकल्पिक भुगतान विधियों को जोड़ा गया है।
सउदी अरब	जेद्दा, रियाद: रिचार्ज करने योग्य स्मार्ट कार्ड (एसएपीटीसीओ) बसों में भुगतान हेतु प्रयुक्त होता है। संपर्क रहित भुगतान की सुविधा हेतु वर्ष 2022 में रियाद मेट्रो का उद्घाटन होने की उम्मीद है।
सिंगापुर	सिंगापुर, एलटीए: संपर्क रहित स्मार्टकार्ड (ईज़ीलिंक) तकनीक को पहले अपनाने वाला, विभिन्न मोड के संचयित मूल्य वाले कार्ड सिस्टम, कार्ड को सीमित बिक्री केंद्र पर भुगतान कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टैप-इन, टैप-आउट किराए की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 2006 से एनईटीएस से अतिरिक्त कार्ड जोड़ा गया और दोनों कार्डों के लिए अंतर-परिचालनीयता हासिल की गई। मोबाइल एप्लिकेशन और ईएमवी तकनीक अभिनियोजित की जा रही है।
दक्षिणी अफ्रीका	केप टाउन, माय सिटी: पे वेव ईएमवी कार्ड (माईकनेक्ट) का उपयोग करके किराया गणना के लिए चेक-इन, चेक-आउट के माध्यम से संपर्क रहित टॉप-अप। नए बस रैपिड नेटवर्क में प्रयुक्त, रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत करने की योजना है (अन्य दक्षिण अफ्रीकी शहरों में कार्ड का उपयोग करने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति)।

देश	सार्वजनिक जन परिवहन टिकट प्रणाली
दक्षिणी कोरिया	सियोल, टी-मनी: देश भर के कई अलग-अलग महानगरों और स्थानों में सार्वजनिक बसों, सब वे, टोल बूथ और कुछ प्रमुख खुदरा बिक्री केंद्रों पर उपयोग के लिए रिचार्जेबल स्मार्ट कार्ड। मोबाइल टी-मनी एप्लीकेशन गूगल प्ले पर भी उपलब्ध है। कोविड महामारी के बाद, एक चेहरा पहचान कर भुगतान करने वाली प्रणाली का परीक्षण टी-मनी द्वारा किया जा रहा है जो यात्रियों को स्मार्टफोन या कार्ड को टैप किए बिना या अपना फेस मास्क हटाने की आवश्यकता के बिना अपने किराए का भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
तुर्की	इस्तांबुल, आईएमएम: मल्टी-मोडल संचयित मूल्य वाले संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड (इस्तांबुलकार्ट)। परिवहन प्रणाली में नकद भुगतान संभव नहीं है। नगरपालिका के स्वामित्व वाले पार्किंग स्थल और थिएटरों और निजी टैक्सियों में भुगतान के लिए उपयोग बढ़ाने की योजना है।
यूनाइटेड किंगडम	लंदन, टीएफएल: मल्टी-मोडल संपर्क रहित संचयित मूल्य वाले स्मार्टकार्ड (ऑयस्टर) और ईएमवी (50% से अधिक प्रयोक्ता) योजनाएं जो ग्रेटर लंदन क्षेत्र को शामिल करती हैं। पूरे नेटवर्क में किराए की गणना के लिए चेक-इन और आउट तकनीक। कैपिंग, रियायतें, ऑनलाइन और मोबाइल टॉप-अप की विशेषताएं और मोबाइल भुगतान ऐप द्वारा भुगतान की सुविधाएँ।
संयुक्त राज्य अमेरिका	शिकागो, सीटीए प्रणाली : विशेषताएं नकदी और संपर्क रहित संचयित मूल्य वाले स्मार्टकार्ड (वेंट्रा); मोबाइल भुगतान ऐप की अनुमति भी है, मोबाइल ऐप को सहारा देता है और ईएमवी (अर्थात यूरो पे, मास्टर कार्ड और वीसा) पूरे मल्टीमॉडल नेटवर्क पर समर्थित है। प्रणाली में रियायतें और कई तरह के मीयादी पास होते हैं।

स्रोत: एडवांसिंग सार्वजनिक परिवहन रिपोर्ट – 'डेमिस्टीफायिंग टिकटिंग एंड पेमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट'- नवंबर 2020

द. डिजिटल बुनियादी अवसंरचना

32. मोबाइल और ब्रॉडबैंड अभिदान (सब्सक्रिप्शन)

32.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में प्रति 100 व्यक्तियों पर मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अभिदान (सब्सक्रिप्शन) की संख्या वर्ष 2020 में क्रमशः 83.6 और 1.6 पर सबसे कम थी। इसके अलावा, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन में वर्ष 2017 से 2020 की अवधि में 6.3% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ोत्तरी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 1.4% की वार्षिकीकृत दर से कमी आई।

32.2 बेंचमार्क रेटिंग : कमजोर

भारत की स्थिति : ब्रॉड बैंड – 21/21, मोबाइल – 20/20

तालिका 33: मोबाइल और ब्रॉड बैंड अभिदान

देश का नाम	फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अभिदान (सब्सक्रिप्शन) (प्रति 100 व्यक्ति)			मोबाइल सेलुलर अभिदान (सब्सक्रिप्शन) (प्रति 100 व्यक्ति)		
	2017	2020	सीएजीआर	2017	2020	सीएजीआर
ऑस्ट्रेलिया	32.2	35	2.8%	108.4	107.7	-0.2%
ब्राज़ील	13.9	17.1	7.1%	106.5	96.8	-3.1%
कनाडा	37.9	41.8	3.3%	86.3	95.6	3.5%
चीन	27.7	33.6	6.6%	103.4	117.9	4.5%
जर्मनी	40.2	43	2.3%	132.7	128.3	-1.1%
फ्रांस	43.9	46.9	2.2%	106.4	111.5	1.6%
यूनाइटेड किंगडम	39.0	40.5	1.2%	118.5	116.4	-0.6%
हांग कांग एसएआर, चीन	36.4	38.3	1.7%	251.8	291.7	5.0%
इंडोनेशिया	2.3	3.9	18.4%	164.4	130.1	-7.5%
भारत	1.3	1.6	6.3%	87.3	83.6	-1.4%
इटली	27.3	29.5	2.6%	138.2	128.7	-2.4%
जापान	31.8	34.5	2.8%	135.5	152	3.9%
कोरिया, रिप.	41.5	43.6	1.7%	124.6	137.5	3.3%
मेक्सिको	13.6	16.4	6.4%	91.6	93.4	0.6%
रूसी फेडेरेशन	21.4	23.2	2.8%	156.2	163.6	1.6%
सउदी अरब	20.1	22.7	4.1%	121.5	124.1	0.7%
सिंगापुर	25.9	25.9	0.1%	146.8	144.1	-0.6%
स्वीडन	38.9	40.6	1.4%	126.4	128.3	0.5%
तुर्की	14.7	19.8	10.4%	95.9	97.4	0.5%
संयुक्त राज्य अमेरिका	33.3	36.4	3.0%	123.0		
दक्षिणी अफ्रीका	2.0	2.2	3.7%	155.2	161.8	1.4%

स्रोत: एचटीटीपीएस://डेटा.वर्ल्डबैंक.ओआरजी/इंडिकेटर

32.3 विश्लेषण : मोबाइल और इंटरनेट अभिगम (पहुँच) डिजिटल भुगतान सुकर करने वाले प्रमुख सहायक हैं। बैंकों और बैंकेतर संस्थाओं दोनों ने इन चैनलों का उपयोग करके भुगतान सेवाएं देने हेतु इनका लाभ उठाया है। बैंक उपभोक्ताओं को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं, जबकि बैंकेतर भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ और प्रदाताओं ने मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान लेनदेन को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, मोबाइल और इंटरनेट संबद्धता का उपयोग नवोन्मेष भुगतान समाधान जैसे संपर्क रहित भुगतान, टोकनाईजेशन, क्यूआर आधारित भुगतान, आदि प्रदान करने के लिए किया गया है ।

भारत में मोबाइल कनेक्शन समग्र रूप से अन्य देशों की तुलना में कम दिखाई देते हैं, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल के व्यापन का कम स्तर है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 57.85% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 130.17% की टेली-सघनता है । इसके अलावा, कई मोबाइल कनेक्शन वाले कुछ व्यक्तियों को एकल नेटवर्क पर स्विच करते देखा गया जिसने कनेक्शन की संख्या को प्रभावित हुई है। मोबाइल कनेक्शन में गिरावट के लिए आपूर्ति पक्ष पर देश में मोबाइल सेलुलर परिचालकों की कामबंदी/उनके विलय और मांग पक्ष पर छोटे व्यवसायों/प्रवासियों पर कोविड महामारी के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में मोबाइल कनेक्शन में इसी तरह की गिरावट अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, इटली और सिंगापुर) में भी देखी गई है।

भारत में वर्ष 2020 में प्रति 100 व्यक्तियों 1.6 फिक्स्ड और 52.4 वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे। वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को शामिल करने पर, संबंधित संकेतक में भारत के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। ट्राई द्वारा मार्च 2022 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन (27.25 मिलियन) का कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शन (788.3 मिलियन) में 4% से कम हिस्सा है। इसके अलावा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्रामीण भारत को उच्च गति डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं और इसे ग्राम पंचायतों में वाईफाई टर्मिनलों की स्थापना करके और फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन देकर सुकर बनाया जा रहा है।

ध . सरकारी ई-भुगतान - इस खंड का प्रारूप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2018 के लिए प्रकाशित सरकारी ई-भुगतान अपनाने संबंधी (एडॉप्शन) रैंकिंग के आधार पर तैयार किया गया था। इसके बाद कोई अनुवर्ती प्रकाशन नहीं हुआ है और इसलिए इस बेंचमार्किंग अभ्यास में सरकारी ई-भुगतान का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।

न. एग्रीगेटर्स (समूहक)

33. अन्य पक्ष भुगतान सेवा प्रदाता/भुगतान गेट वे/भुगतान समूहक (एग्रीगेटर्स)

33.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत ने हाल ही में भुगतान एग्रीगेटर्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी वर्तमान भुगतान एग्रीगेटर्स को 30 सितंबर, 2021 तक प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन करना अनिवार्य कर दिया । भारत में, भुगतान गेट वे की गतिविधियों को विनियमित नहीं किया जाता है क्योंकि वे निधियों का प्रबंधन नहीं करते हैं और विनियामक उनकी गतिविधियों के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी पर केवल अनुशंसात्मक दिशानिर्देश जारी करता है। इसके अलावा, गतिविधियों की बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) में जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया।

33.2 बेंचमार्क रेटिंग : मजबूत

33.3 विश्लेषण: अन्य पक्ष भुगतान सेवा प्रदाता / भुगतान गेट वे / भुगतान एग्रीगेटर वे सेवा प्रदाता हैं जो ई-कॉमर्स के व्यापारियों के भुगतान लेन-देन को संसाधित करते हैं। अन्य पक्ष भुगतान सेवा प्रदाताओं / भुगतान गेटवे / भुगतान एग्रीगेटर्स से संबंधित विनियम विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं जैसे (i) लाइसेंसीकरण/ प्राधिकार देने (ii) परिचालन संबंधी अपेक्षाएं (iii) ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा, (iv) निधियों का निपटान और (v) ग्राहक संरक्षण।

अन्य पक्ष के भुगतान सेवा प्रदाताओं का प्रत्यक्ष विनियमन चीन, ब्राजील, जापान और दक्षिण कोरिया में प्रचलित है। यद्यपि, सिंगापुर जैसे देशों में भुगतान मध्यस्थों का कोई प्रत्यक्ष विनियमन नहीं है। भारत में, केवल भुगतान एग्रीगेटरों की गतिविधियों को विनियमित किया जाता है क्योंकि उनमें निधियों का प्रबंधन शामिल होता है।

तालिका 34: अन्य पक्ष भुगतान सेवा प्रदाता/भुगतान गेट वे/भुगतान समूहक (एग्रीगेटर्स)

देश	लाइसेंसधारी/ प्राधिकृत	परिचालन संबंधी अपेक्षाएं	ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा	निधियों का निपटान	ग्राहक संरक्षण / शिकायत निवारण
ब्राज़ील	लाइसेंसधारी	न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड और प्रभावी जोखिम प्रबंधन नीतियां	निजता, उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता डेटा सुरक्षा और विवरणियों संबंधी क़ानून लागू	निपटान पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोई आरक्षित निधि अपेक्षाएं नहीं। मौजूदा दिवालियापन कानून लागू हैं।	उपभोक्ता संरक्षण क़ानून के अंतर्गत आते है जिसमें पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा ओर विवरणियां शामिल हैं ।
कनाडा	नहीं			समय की एक निर्धारित अवधि के भीतर निधियों का निपटान आवश्यक है।	
चीन	लाइसेंसधारी	आईटी सुविधाओं, संगठनात्मक संरचना और आरक्षित निधि के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं लागू हैं। अन्य पक्षीय भुगतान सेवा खातों के लिए दैनिक लेन-देन की सीमा	एग्रीगेटर्स को ग्राहकों के धन का उपयोग करने से रोकने के लिए ग्राहकों की आरक्षित जमा राशि का लगभग 20% एक निर्दिष्ट बैंक खाते में आवंटित करना अपेक्षित है। डेटा स्थानीयकरण, डेटा संरक्षण और डेटा स्थानांतरण की अपेक्षाओं का अनुपालन आवश्यक है।	अपने स्वयं के बैंक खाते से निधियों का निपटान नहीं कर सकते। दिवालियेपन के मामले में आरक्षित निधि अपेक्षाएं लागू होंगी।	

देश	लाइसेंसधारी/ प्राधिकृत	परिचालन संबंधी अपेक्षाएं	ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा	निधियों का निपटान	ग्राहक संरक्षण / शिकायत निवारण
यूरोप	प्राधिकृत	निम्नलिखित नहीं कर सकते (ए) निधियां नहीं रख सकते, (बी) भुगतान डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, और (सी) किसी भी तरह से लेन-देन को संशोधित नहीं कर सकते हैं। भेदभाव रहित नीति का पालन करना होगा।	यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि सरंक्षित और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कुछ न्यूनतम सुरक्षा उपाय हैं।	निपटान की कोई सीमा नहीं। कोई आरक्षित निधि अपेक्षाएं नहीं। दिवालियेपन की स्थिति में, वर्तमान दिवालिया कानून लागू होंगे।	
भारत	भुगतान एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।	पूंजी, निवल मालियत, अभिशासन के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाएं	भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) को व्यापारियों की अवसंरचना का सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है। पीए भुगतान डेटा या ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल स्टोर नहीं कर सकते हैं।	भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के लिए निलंब खोलना अपेक्षित है। व्यापारियों को देय राशि की गणना निपटान और एस्क्रो खाते में क्रेडिट के बाद ही की जाती है।	
इंडोनेशिया	लाइसेंसधारी (यदि 300,000 सक्रिय प्रयोक्ता हों या इतने प्रयोक्ता जोड़ने की योजना हो।)	प्रभावी और सुसंगत जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रणाली सुरक्षा मानक, उपभोक्ता संरक्षण उपाय। सेवा प्रदाताओं को बैंक ऑफ इंडोनेशिया को आवधिक और प्रासंगिक दोनों रिपोर्टें प्रस्तुत अवश्य प्रस्तुत करनी हैं।			
जापान	पंजीकृत	निदेशकों के लिए योग्यताएं; व्यापारी और उपभोक्ता की जाँच पड़ताल प्रक्रिया और आवधिक निरीक्षण।	ग्राहक डेटा के अनुचित उपयोग और प्रकटीकरण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए जाँच-पड़ताल प्रक्रिया और आवधिक निरीक्षण करना।	व्यापारी /उपभोक्ता से प्राप्त निधियां को (ए) एक नामित बैंक के ट्रस्ट/निलंब (एस्क्रो) खाते में में रखना चाहिए, (बी) इन निधियों की राशि के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था करनी चाहिए, या (सी) इन निधियों की राशि को	व्यापारियों या उपभोक्ताओं की शिकायतों, दावों और विवादों के निपटान हेतु उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और संगठनात्मक

देश	लाइसेंसधारी/ प्राधिकृत	परिचालन संबंधी अपेक्षाएं	ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा	निधियों का निपटान	ग्राहक संरक्षण / शिकायत निवारण
				नामित सरकारी निक्षेपागार में जमा करना चाहिए	अवसंरचना स्थापित करना चाहिए।
सिंगापुर	केवल तभी विनियमित होते हैं जब वे निपटान निधि को संभालते हैं		ग्राहक जानकारी की गोपनीयता से संबंधित कानून लागू होते हैं	निधियों के निपटान संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं। दिवालियापन के मामलों से निपटान के दौरान प्रचलित दिवालियापन कानून लागू होते हैं।	उपभोक्ता संरक्षण (निष्पक्ष व्यापार) अधिनियम (सीपीटीएफए) लागू है
दक्षिणी कोरिया	पंजीकृत	प्रयोक्ताओं की पहचान की पुष्टि करना, त्रुटि सुधार, पारदर्शिता, आहरण नियम, आईटी लेखा परीक्षा (ऑडिट) और व्यावसायिक दायरे की सीमाएं।	ऑनलाइन उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून लागू।	निपटान की कोई सीमा नहीं। कोई आरक्षित निधि अपेक्षाएं नहीं। प्रयोज्य दिवालियापन कानून लागू होते हैं।	वाणिज्यिक अधिनियम में बुनियादी उपभोक्ता संरक्षण प्रदान किया गया
संयुक्त राज्य अमेरिका	लाइसेंसधारी	पारदर्शिता और ज़मानत बांड, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) का पालन	डेटा संरक्षण कानून एग्रीगेटर्स पर लागू होते हैं।	निपटान संबंधी कोई अपेक्षाएं नहीं। दिवालिया होने के मामले में स्टेट ज़मानत बांड लागू होंगे।	डोड फ्रैंक और फ़ेडरल ट्रेड कमीशन अधिनियम के अधीन, जो अनुचित व्यापार और भ्रामक पद्धतियाँ को प्रतिबंधित करता है।

प . ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण

34. ग्राहक संरक्षा और अधिप्रमाणन मानक

34.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। इसके अलावा, विनियामक ने ग्राहक लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पिछले अभ्यास के बाद से, विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे (क) कार्ड लेन-देन को आरंभ /बंद करने की सुविधा, (ख) कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (ग) केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) को अनिवार्य करना, (घ) उच्च मूल्य के चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली।

34.2 बेंचमार्क रेटिंग : मजबूत

34.3 विश्लेषण: ई-वाणिज्य (कॉमर्स) वातावरण में, जहां लेन-देन ऑनलाइन किए जाते हैं, लेन-देन करते समय भुगतानकर्ता की पहचान का वैधीकरण करना आवश्यक है। कार्ड भुगतान नेटवर्क ने इस आवश्यकता को पहचानते हुए कार्ड-न-मौजूद (कार्ड-नॉट-प्रेजेंट) ई-वाणिज्य (कॉमर्स) लेन-देन के दौरान कार्डधारक को विधिमान्य करने के लिए अधिप्रमाणन के मानकों को स्थापित किया है।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं संरक्षण के लिए और धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं प्रदान की जा सकती हैं। भारत में, कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जाती हैं। वर्ष 2020 में, भारत ने कार्ड निर्गमकर्ता बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे ग्राहकों को बिक्री केंद्र (पीओएस) / एटीएम / ऑनलाइन लेन-देन / संपर्क रहित लेन-देन आदि पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के लेन-देन के लिए स्विच ऑन/ऑफ और लेन-देन की सीमा सेट/संशोधित करने की सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा, कार्ड नेटवर्क को अनुमति दी गई कि वे कार्ड धारकों को टोकनयुक्त कार्ड से लेन-देन की सुरक्षा का लाभ उठाने हेतु सक्षम करने के लिए कार्ड टोकनाईजेशन की सेवाएं प्रदान करें।

इसके अलावा, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बीएएटी) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, प्रिंट और ऑडियो-विजुअल मीडिया में सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें बैंक का अग्रणी कार्यक्रम "आरबीआई कहता है"[20] भी शामिल है।

तालिका 35: ग्राहक संरक्षा और अधिप्रमाणन मानक

देश	अधिप्रमाणन मानक	विशेषताएं
विश्वव्यापी	3डी सिक्योर (सुरक्षित)	3डी सिक्योर इंटरनेट सुरक्षा प्रोटोकॉल, एसएसएल/टीएलएस का उपयोग करते हुए एक सुरक्षित चैनल पर एक्सएमएल संदेशों के संप्रेषण पर आधारित है। एक 3डी सुरक्षित सेवा का उपयोग करने के लिए, कार्डधारक को अपने भुगतान कार्ड के साथ एक अधिप्रमाणन मूल्य, जैसे पासवर्ड, को जोड़कर सेवा के लिए नामांकन करना होगा। व्यापारी को अपनी साइट के भीतर मर्चेंट प्लग-इन (एमपीआई) स्थापित करके, 3डी सिक्योर का प्रयोग आरंभ करना होगा। 3डी सिक्योर 1.0.2 के मुख्य विक्रय बिंदुओं में से एक यह है कि यह धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन के खिलाफ व्यापारी को पूर्ण देयता अंतरण (शिफ्ट) की सुविधा प्रदान करता है। यदि किसी प्रयोक्ता को लेन-देन अधिकृत करने के लिए प्रमाणीकरण के द्वितीय स्तर से गुजरना पड़ता है, तो इस बात की संभावना कम होती है कि कार्ड का उपयोग धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से किया जाएगा।

[20]एचटीटीपीएस://आरबीआईकहताहै.आरबीआई.ओआरजी/

देश	अधिप्रमाणन मानक	विशेषताएं
विश्वव्यापी	3 डी सिक्योर 2.0	3 डी सिक्योर 2.0 की विशिष्टता इस प्रकार बनाई गई है कि वह मोबाइल भुगतान, ब्राउज़र और मोबाइल ऐप के साथ एकीकरण, जोखिम-आधारित सुरक्षा, बहु-कारक अधिप्रमाणन और ई-मुद्रा को सहायता प्रदान करती हैं। 3डीएस 2.0 की अधिप्रमाणन प्रक्रिया में टोकन के प्रयोग से पूरित होती है, जो एक बार प्रयोग किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड नंबर हैं। निर्गमकर्ता द्वारा जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण सुकर बनाने के लिए, 3डीएस 2.0 भुगतानकर्ता और डिवाइस के बारे में परिवर्ती जानकारी (जैसे डिवाइस आईडी, एमएसी पता, सिम कार्ड विवरण, आदि), जिसे 'समृद्ध डेटा' के रूप में जाना जाता है, प्रग्रहण करता है, ताकि इन्हें बाजार या क्षेत्रीय अधिदेश के आधार पर भेजने से प्रतिबंधित किया जा सके। कार्डधारक और लेन-देन विवरण सहित संग्रहित सूचना को कूटबद्ध (एन्क्रिप्ट) किया जाता है और कार्ड योजना के निर्देशिका (डायरेक्टरी) सर्वर पर भेजा जाता है जहां डेटा को विकूट (डिक्रिप्ट) किया जाता है, वैधीकरण किया जाता है और फिर कार्ड जारीकर्ता (एसीएस) को भेज दिया जाता है। इस समृद्ध डेटा के आधार पर, जारीकर्ता एक जोखिम मूल्यांकन करता है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि ऑनलाइन लेनदेन करने वाला व्यक्ति भुगतान कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिकृत है या नहीं। 3डी सिक्योर 2.0 का कार्यान्वयन को ईएमवी सीओ कम्युनिटी की सहायता और पीसीआई सुरक्षा मानक परिषद (पीसीआई एसएससी) के सहयोग से किया जा रहा है, जो नई विशिष्टता (स्पेसिफिकेशन) को अपने सूचना सुरक्षा अपेक्षाओं सम्बंधी के फ्रेमवर्क के भाग के रूप में इसका उपयोग करेंगे।
विश्वव्यापी	ईएमवी सीओ	यह अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, जेसीबी, मास्टरकार्ड, यूनियनपे और वीजा से मिल कर बना एक संघ है। ईएमवी सीओ भुगतान उद्योग में विश्वव्यापी अंतर-परिचालनीयता और सुरक्षित भुगतान लेनदेन की स्वीकृति को सुकर बनाता है। यह भौतिक कार्ड धोखाधड़ी को कम करने के लक्ष्य के साथ यूरो पे, मास्टरकार्ड और वीज़ा द्वारा वर्ष 1994 में शुरू किए गए स्मार्ट भुगतान कार्ड के लिए एक तकनीकी मानक ईएमवी का प्रबंधन भी करता है।
भारत	पे सिक्योर	पे सिक्योर अधिप्रमाणन उपाय सेवा हेतु कार्ड के पंजीकरण के दौरान ही स्थापित किए जाते हैं और "नियम" आधारित होते हैं। नियम अपेक्षित अधिप्रमाणन के स्तर को निर्धारित करते हैं। एक निश्चित मूल्य के भीतर ऑनलाइन लेन-देन के लिए, भुगतानकर्ता को दो-कारक अधिप्रमाणन पद्धति, एक छवि और एक पासफ्रेज़ के रूप में, जिसके बाद में कार्ड के पिन का उपयोग कर अधिप्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। एक निश्चित सीमा से अधिक के लेन-देन के लिए, कार्ड का पिन दर्ज करने से पहले, कार्डधारकों को एक

		वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज करना होगा जो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पते या डिवाइस पर भेजा जाता है। एक एंटी-फ़िशिंग तंत्र भी उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ता को लेन-देन के दौरान अपनी पिछली तीन ऑनलाइन खरीदारी की जांच करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), ईएमवीसीओ के एक व्यावसायिक और तकनीकी सहयोगी के रूप में, 3डी सिक्योर 2.0 प्रोटोकॉल के डिजाइन और विकास के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के निर्माण, विकास, संवर्धन और कार्यान्वयन के लिए ईएमवी सीओ कार्य दल में भाग ले सकता है।
चीन	यूनियनपे ऑनलाइन पेमेंट्स (यूपीओपी)	यूनियनपे घरेलू बाजार के लिए दो कार्डधारक अधिप्रमाणन प्रणालियां, सिक्योरपे और एक्सप्रेसपे प्रदान करता है। जब भुगतानकर्ता सिक्योरपे के लिए पंजीकृत होते हैं, तो उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग कर खुद को अधिप्रमाणित करने के लिए निर्गमकर्ता बैंक की साइट पर भेज दिया जाता है। एक्सप्रेस पे अधिप्रमाणन व्यापारी (मर्चेंट) की साइट पर किया जाता है और इसमें भुगतानकर्ता के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग भी शामिल होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, यूनियन पे कार्ड उसी तरह काम करते हैं जैसे उनके सह-ब्रांडों की भुगतान प्रणाली में मानक कार्ड होते हैं
रूस	एमआईआर	एमआईआर कार्ड, जो कार्डधारक प्रमाणीकरण के लिए वीज़ा के मानक के साथ संयोज्य (कम्पेटिबल) 3डीएस 1.0.2 की विशेषताएँ रखता है, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का मुकाबला करने और कार्ड भुगतान के देश में प्रसंस्करण को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य बाहरी आर्थिक या राजनीतिक कारकों को रोकने के लिए रूसी सेंट्रल बैंक की समनुषंगी नेशनल पेमेंट कार्ड सिस्टम (एनएसपीके) द्वारा जारी किया गया था।
यूरोप	पी एस डी 2 डायरेक्टिव	पीएसडी2 भुगतान अधिप्रमाणन के लिए अधिक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की अनुमति देता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मजबूत अधिप्रमाणन वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाए । अंतिम लक्ष्य धोखाधड़ी को कम करना है, जबकि प्रयोज्यता के बेहतर स्तर प्रदान करना भी है।

35. लोकपाल

35.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नवंबर 2021 में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए अधिक अनुक्रियाशील बनाने के लिए एकीकृत लोकपाल योजना प्रारंभ की। एकीकृत लोकपाल योजना ने निम्नलिखित 3 योजनाओं को संयुक्त किया है (i) बैंकिंग लोकपाल

योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019

इसके अलावा, एक तेज, प्रभावी और कुशल शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2019 में बड़े गैर-बैंक (बैंकेतर) पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एक आंतरिक लोकपाल योजना शुरू की गई थी।

35.2 बेंचमार्क रेटिंग : मजबूत

35.3 विश्लेषण: अधिकारिताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं की पहुंच एक ऐसे शिकायत निवारण तंत्र तक हो जो सुलभ, सस्ता, स्वतंत्र, निष्पक्ष, उत्तरदायी, समयोचित और प्रभावशाली है। एक लोकपाल न केवल अत्यधिक कानूनी लागतों के बिना उपभोक्ताओं द्वारा सामना की गई व्यक्तिगत गलतियों के निवारण में सहायता करता है, बल्कि एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में भी कार्य करता है, जो विनियामक उपायों को सूचित करने में मदद करता है।

भारत में डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना ने भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों यथा बैंकेतर कोई व्यक्ति जो भुगतान सेवाओं दे रहा है / भुगतान प्रणाली परिचालन कर रहा है, के ग्राहकों के डिजिटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान की है। यह डिजिटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक शीघ्र और लागत मुक्त शीर्ष स्तरीय तंत्र है। इन गतिविधियों को अब एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

तालिका 36 : लोकपाल योजनाएं

क्रम सं	देश	संगठन	स्थापित	शक्तियां
1.	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय शिकायत प्राधिकरण (ऑस्ट्रलियन फाइनेंसियल कम्प्लेंट्सअथॉरिटी)	2018	एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में कार्य करता है। ट्रेजरी कानून संशोधन (उपभोक्ताओं को पहले रखना - ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय शिकायत प्राधिकरण की स्थापना) अधिनियम 2018 (एएफसीए एक्ट) एएफसीए को प्राधिकृत करता है और इसके अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है। एएफसीए एक विनियामक नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र लोकपाल के रूप में कार्य करता है। यह बैंकिंग, बीमा, निवेश और वित्तीय सलाह से संबंधित शिकायतों पर विचार करता है।
2.	यूनाइटेड किंगडम	वित्तीय लोकपाल सेवा	2001	वित्तीय लोकपाल सेवा को वित्तीय सेवा और बाजार अधिनियम, 2000 के माध्यम से सांविधिक समर्थन प्राप्त है। यह अधिकांशतः वित्तीय सेवाओं - बैंकिंग, बीमा, पेंशन, बचत और निवेश, कार्ड, मुद्रा अंतरण,आदि से संबंधित शिकायतों पर विचार करता है।
3.	कनाडा	बैंकिंग सेवाओं और निवेश के लिए लोकपाल	1996	प्रारंभ में एक बैंकिंग लोकपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 2002 में म्यूचुअल फंड और निवेश को भी इसके परिचालन के दायरे में जोड़ा गया। लोकपाल की सिफारिशें फर्मों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

क्रम सं	देश	संगठन	स्थापित	शक्तियां
4.	फ्रांस	-		एसीपीआर (प्रूडेंशियल कंट्रोल एंड रिजॉल्यूशन अथॉरिटी) अर्थात विवेकपूर्ण नियंत्रण और समाधान प्राधिकरण के पास विवाद के समाधान का कोई अधिकार-क्षेत्र नहीं है। विवाद संबंध में बैंकर/बीमाकर्ता या किसी अन्य मध्यस्थ की असंतोषजनक अनुक्रिया होने पर, एसीपीआर विवाद समाधान के लिए मध्यस्थों/अदालतों का सुझाव देता है।
5.	जर्मनी	बा फिन (फ़ेडरल फाइनेंसियल सुपरवाइजरी ऑथरिटी) अर्थात संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण	2002	बैंकिंग, बीमा और प्रतिभूति उद्योगों के लिए पर्यवेक्षक / विनियामक
6,	दक्षिणी अफ्रीका	बैंकिंग सेवाओं के लिए लोकपाल	1997	स्वतंत्र लोकपाल जो बाध्यकारी फैसला जारी कर सकता है
7.	संयुक्त राज्य अमेरिका	ग्राहक सहायता समूह (कॉम्प्ट्रोलर ऑफ़ करेंसी)		निष्पक्ष अभिगम (पहुँच) और समान व्यवहार सुनिश्चित करने में सहायता करता है। ग्राहकों के प्रश्नों और शिकायतों में मदद करता है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, बैंकिंग नियमों और जोखिमों को समझने में सहायता करने हेतु सलाह देता है । कॉम्पट्रोलर ऑफ़ करेंसी अर्थात मुद्रा नियंत्रक, ट्रेजरी विभाग का एक स्वतंत्र ब्यूरो है।
8.	रूस	वित्तीय लोकपाल सेवा	2018	वर्ष 2018 में बैंक ऑफ रूस द्वारा स्थापित गया और सांविधिक समर्थन (4 जून, 2018 का फ़ेडरल लॉ (संघीय कानून) है। लोकपाल बीमा, क्रेडिट संस्थाओं, गिरवी की दुकानों, पेंशन निधियों आदि सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को कवर करता है।

सभी देशों में सदृश की योजनाओं की तुलना करने से पता चलता है कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां डिजिटल भुगतान लेन-देन का पूरा दायरा लोकपाल योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। ऐसा लगता है कि अन्य देशों में लोकपाल योजनाएं डिजिटल भुगतान लेन-देन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। कई अधिकारिताओं में लोकपाल को उद्योग के सहभागियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो उपभोक्ताओं के बीच विश्वास पैदा नहीं करता है। इसके अलावा, कुछ अधिकारिताओं जैसे कनाडा में लोकपाल के पास बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है।

इसके अलावा, भुगतान प्रणालियों में ग्राहकों का विश्वास बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े गैर-बैंक (बैंकेतर) पूर्वदत्त लिखतों (पीपीआई) के जारीकर्ताओं को एक आंतरिक लोकपाल योजना को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ग्राहकों की अधिकांश शिकायतों का निवारण भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के स्तर पर ही पीएसओ के शिकायत निवारण तंत्र के उच्चतम स्तर पर रखे प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।

फ. प्रतिभूति निपटान और समाशोधन प्रणाली

36. केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी)

यद्यपि भारत में कई केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) काम कर रहे हैं, परंतु इस अध्ययन के उद्देश्य से हम भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा विनियमित केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) अर्थात भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के परिचालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

36.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है और मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) बाजारों में लेन-देन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान प्रदान करता है। एक बहुराष्ट्रीय (क्रॉस-कंट्री) तुलना में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), ने संगठन के प्रबंधन के लिए मौजूदा शासन व्यवस्था और सदस्य की चूक और अन्य गैर-चूक (डिफ़ॉल्ट) हानियों के प्रबंधन हेतु कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में अच्छा कम किया है।

36.2 बेंचमार्क रेटिंग: लीडर

36.3 विश्लेषण : केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार अवसंरचनाएं (एफएमआई) हैं जो उनके द्वारा सर्विस किए जा रहे बाजारों में गारंटीकृत निपटान सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रतिभागियों के लिए प्रतिपक्ष जोखिम को कम करते हैं, जिससे प्रणालीगत जोखिम कम होता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपयुक्त शासन व्यवस्था के साथ केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) एक कुशल और प्रभावी तरीके से कार्य करें। इसके अलावा, सीसीपी के पास संभाव्य सामान्य व्यावसायिक घाटे को पूरा (कवर) करने और उनके द्वारा लगातार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सक्षम बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवल मालियत (नेटवर्थ) होनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए निम्निलिखित दिशा-निदेश निर्धारित किए हैं: (i) घरेलू सीसीपी की शासन व्यवस्था पर निदेश ; (ii) निवल मालियत की अपेक्षाओं और सीसीपी के स्वामित्व पर निदेश; और (iii) विदेशी केंद्रीय प्रतिपक्षकारों को मान्यता देने संबंधी दिशा निदेश।

सीसीपी उच्च मूल्य के लेन-देन को संभालते हैं और किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप व्यापक प्रणालीगत प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए सीसीपी के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास उपयुक्त जोखिम प्रबंधन पद्धतियां हों। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के मामले में सहभागी क्रेडिट एक्सपोज़र, बहुपक्षीय नेटिंग (निवल राशि निर्धारण), सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी)/भुगतान बनाम भुगतान (पीवीपी) निपटान और मार्जिन वसूली के माध्यम से कवर किए जाते हैं। सभी उत्पादों के लिए मार्जिनिंग मॉडल का उपयोग करके बाजार जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। प्रारंभिक मार्जिन भविष्य के संभाव्य एक्सपोजर को कवर करने के लिए एकत्र किया जाता है जबकि दिन के दौरान (इंट्रा-डे) और दिन के अंत में एमटीएम मार्जिन वर्तमान एक्सपोजर को कवर करने के लिए एकत्र किया जाता है। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) संसाधनों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए प्रतिदिन मार्जिनिंग

मॉडल की बैक-टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग करता है तथा स्ट्रेस टेस्ट के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त व्यतिक्रम निधि (एडिशनल डिफॉल्ट फंड) में अंशदान मांगने के लिए क्रियाविधि मौजूद हैं।

वित्तीय बाजार की अवसंरचना हेतु सिद्धांत (प्रिंसिपल्स ऑफ़ फाइनेंसियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर) अर्थात पीएफएमआई के अनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) सभी बाजार खंडों के लिए कवर-1 की अपेक्षाओं के अधीन है क्योंकि वह कई अधिकारिताओं में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के रूप में काम नहीं करता है और जिन उत्पादों को मंजूरी दी गई है जो जटिल जोखिम प्रोफ़ाइल के नहीं हैं। हालांकि, सीसीआईएल ने अपने व्युत्पन्नी खंड (डेरिवेटिव सेगमेंट) - फॉरेक्स फॉरवर्ड और रुपया व्युत्पन्नी खंड (डेरिवेटिव सेगमेंट) के लिए कवर-2 की अपेक्षाओं को लागू किया है।

सहभागी व्यतिक्रमों (चूकों) के कारण होने वाली हानियों को पूर्व-वित्त पोषित संसाधनों द्वारा संभाला जाता है जिसमें सदस्य के अंशदान वाली व्यतिक्रम निधि (डिफॉल्ट फंड)और सीसीआईएल द्वारा अपने सेटलमेंट रिजर्व फंड (एसआर एफ) से डिफॉल्ट फंड में किया गया अंशदान शामिल हैं । कारोबार के प्रत्येक खंड (सेगमेंट) में सीसीआईएल का जोखिम डिफ़ॉल्ट फंड में अंशदान के 25% तक सीमित है, लेकिन खंड के लिए उच्चतम व्यक्तिगत सदस्य के अंशदान से कम नहीं हो, जो कि अधिकांश अन्य सीसीपी से अधिक है। सभी खंडों में कारोबार में सीसीआईएल की कुल जोखिम एसआरएफ में शेष तक सीमित है । इसके अलावा, गैर-व्यतिक्रम (डिफ़ॉल्ट) घटनाओं से होने वाले नुकसान की देखभाल के लिए सीसीआईएल द्वारा एक आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआरएफ) की स्थापना की गई है।

तालिका 37: चुनिंदा केंद्रीय प्रतिपक्षकार में डिफॉल्ट फंड परिदृश्य

क्रम सं	अधिकारिता	केंद्रीय प्रतिपक्षकार का नाम	एसआईटीजी/डीएफ अनुपात* (%)
1.	फ्रांस	एलसीएच एसए	0.65
2.	यूनाइटेड किंगडम	एलसीएच	1.01
3.	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका	ओसीसी	1.36
4.	जर्मनी	यूरेक्स क्लीयरिंग	2.61
5.	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका	सीएमई	3.33
6.	स्वीडन	नैस्डाक	10.87
7.	भारत	सीसीआईएल	25.00
8.	चीन	शंघाई क्लीयरिंग हाउस	28.59
9.	सिंगापुर	एसजीएक्स डीसी	41.75

**ऐसे मामलों में जहां सीसीपी द्वारा संसाधनों को समाशोधन सेवा स्तर पर या करेंसी द्वारा अलग किया जाता है, अनुपात निर्धारित करने के लिए संसाधनों को संकलित किया गया है।*

स्रोत: सीसीआईएल, सीसीपी का सार्वजनिक मात्रात्मक प्रकटन

ब. अन्वेक्षा (ओवरसाइट)

37. भुगतान प्रणाली की अन्वेक्षा

37.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 ने भारतीय रिज़र्व बैंक को देश के भीतर भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने का अधिकार निर्दिष्ट और प्रदान किया है। वर्ष 2020 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए अद्यतन अन्वेक्षा फ्रेमवर्क प्रकाशित किया जो भारतीय रिज़र्व बैंक की अन्वेक्षा के उद्देश्यों और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के साथ-साथ वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे हेतु सिद्धांतों (पीएफएमआई) के तहत वित्तीय बाजार अवसंरचना और प्रणाली व्याप्ति के रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसडब्ल्यूआईपीएस) के मूल्यांकन की पद्धति का ब्यौरा भी देता है।

37.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

37.3 विश्लेषण : भुगतान और निपटान प्रणाली की अन्वेक्षा (निगरानी) केंद्रीय बैंक का कार्य है जिसके द्वारा सुरक्षा और कार्यकुशलता के उद्देश्यों को, वर्तमान और योजनाबद्ध प्रणालियों की निगरानी, इन उद्देश्यों के समक्ष उनका मूल्यांकन और जहां आवश्यक हो परिवर्तन को उत्प्रेरित करके, बढ़ावा दिया जाता है।

भारत में, तीन प्रमुख तरीके से अन्वेक्षा (निगरानी) गतिविधि की जाती है, वे हैं (i) वर्तमान और योजनाबद्ध प्रणालियों की निगरानी; (ii) निरीक्षण उद्देश्यों के समक्ष वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) का मूल्यांकन; और (iii) जहां आवश्यक हो, सुधार के लिए परिवर्तन को उत्प्रेरित करना।

भारत में, वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और अधिकृत खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) की परोक्ष (ऑफ-साइट) निगरानी विभिन्न साधनों के माध्यम से की जाती है, जैसे (ए) विनियमित संस्थाओं द्वारा निर्धारित डेटा / सूचना प्रस्तुत करना, (बी) धोखाधड़ी की निगरानी / प्रणाली अलर्ट (सी) अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएस ओ) के साथ नियमित बैठकें, (डी) बाजार आसूचना (इंटेलिजेंस), और (ई) अन्वेक्षण रिपोर्ट और सर्वेक्षण। इसके अलावा, ऑनसाइट निरीक्षण/लेखापरीक्षा, एफएमआई/आरपीएस के लिए स्थापित ऑफसाइट निगरानी और चौकसी, के पूरक हैं । ऑनसाइट निरीक्षण गतिविधि, इकाई द्वारा किए गए वार्षिक स्व-मूल्यांकन से प्राप्त इकाई के जोखिम प्रोफाइल और इकाई और बाजार आसूचना, द्वारा प्रस्तुत जानकारी, यदि कोई हो, पर आधारित है। वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और अधिकृत खुदरा भुगतान प्रणालियां (आरपीएस) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऑनसाइट निरीक्षण के अधीन होते हैं।

तालिका 38 : अन्वेक्षा (निगरानी) के साधन

देश			उपलब्ध साधन					
	सुनिश्चित (व्यक्त)	अन्तर्निहित (अव्यक्त)*	निगरानी	संवाद और नैतिक प्रत्यायन /दबाव	आंकड़े और/ या भुगतान प्रणाली रिपोर्ट निर्मित करना और प्रकाशित करना	विनियम जारी करना	प्रतिबंध लगाना	ऑन साइट निरीक्षण
ऑस्ट्रेलिया	Y		Y	Y	Y	Y		
ब्राज़ील	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
कनाडा	Y	Y	Y	Y	Y			Y
चीन		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ईसीबी	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
फ्रांस	Y	Y	Y	Y	Y			Y
जर्मनी		Y	Y	Y	Y			
हांगकांग एसएआर	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
भारत	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
इटली	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
जापान		Y	Y	Y	Y			Y
मेक्सिको	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
रूस	Y	Y	Y	Y	Y			Y
सउदी अरब		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
सिंगापुर	Y	Y	Y	Y	Y	Y#	Y#	Y#
दक्षिणी अफ्रीका	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
दक्षिणी कोरिया		Y	Y	Y	Y			
स्वीडन		Y	Y	Y	Y			Y
तुर्की		Y	Y	Y	Y	Y		
संयुक्त राज्य अमेरिका	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y

स्रोत: खुदरा भुगतान में नवोन्मेष पर कार्य दल द्वारा आयोजित सर्वेक्षण, 2012 (सीपीएसएस, बीआईएस)

नोट :
**अंतर्निहित - "देश में भुगतान की पर्याप्त और सुरक्षित कार्यपद्धति सुनिश्चित करने" के संदर्भ में इसका अर्थ समझा गया*
 # ऑपरेटरों, निपटान संस्थाओं और नामित भुगतान प्रणाली के सहभागी एमएएस नियमों के अधीन होंगे
$ प्राधिकरण सुस्पष्ट है जहां यह बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन में फेडरल रिजर्व की भूमिका से लिया गया है; उपलब्ध साधन परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे ।

भ. सीमा-पार वैयक्तिक धन-प्रेषण

38. उपलब्धता

38.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत में, सीमा-पार धन-प्रेषण का बड़ा हिस्सा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। गैर-बैंक (बैंकेतर) सहभागियों को केवल आवक धन-प्रेषण की सुविधा देने की अनुमति है।

38.2 बेंचमार्क रेटिंग : सामान्य

38.3 विश्लेषण : प्राधिकृत व्यापारी बैंक भुगतान अंतरण की विभिन्न पद्धतियों जैसे चेक और ड्राफ्ट, वायर ट्रांसफर, विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) के माध्यम से अंतरण और रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के माध्यम से धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंकेतर (गैर-बैंक) सहभागियों के बीच, मुद्रा अंतरण प्रचालक अपने ग्राहकों की ओर से या तो अपने आंतरिक सिस्टम का उपयोग करके या सीमा पार बैंकिंग नेटवर्क तक अभिगम (पहुंच) के माध्यम से सीमा-पार अंतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एकल मुद्रा या बहुविध मुद्राओं में सीमा-पार लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाली विभिन्न भुगतान प्रणालियाँ हैं। डायरेक्टो ई मेक्सिको सिस्टम फेडरल रिजर्व के ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को मेक्सिकन आरटीजीएस सिस्टम के साथ सहबद्ध करके संयुक्त राज्य अमेरिका से मेक्सिको में विप्रेषण की सुविधा प्रदान करता है जबकि बैंक ऑफ मैक्सिको इसमें विदेशी मुद्रा रूपांतरण का कार्य करता है। गल्फ को-ऑपरेटिव काउंसिल आरटीजीएस प्रणाली खाड़ी क्षेत्र (गल्फ रीजन) के 6 देशों के भीतर स्थानीय मुद्रा में भुगतान के साथ लेनदेन की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की गई थी।

इसके अलावा, सीमा-पार से भुगतान और विप्रेषण की सुविधा के लिए सभी अधिकारिताओं में परिचालित तेज भुगतान प्रणालियों को आपस में सहबद्ध करने के की पहल की गई है। सिंगापुर की पे नाउ और थाईलैंड की प्रोम्प्ट पे नामक वास्तविक समय (रीयल-टाइम) खुदरा भुगतान प्रणाली को आपस में सहबद्ध करना एक ऐसा ही उदाहरण है। इसी के सदृश, सिंगापुर की पे नाउ को भारत की यूपीआई के बीच अंतर-सहबद्धता पर काम चल रहा है और आशा है कि वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में यह सक्रिय हो जाएगी ।

भारत में, सीमा-पार से भुगतान, विशेष रूप से वैयक्तिक धन-प्रेषण की सुविधा के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। नेपाली प्रवासी श्रमिकों को घर वापस धन-प्रेषण भेजने में सहायता देने हेतु, भारत-नेपाल विप्रेषण योजना शुरू की गई थी, जो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ साझेदारी में भारत से नेपाल धन के एकतरफा विप्रेषण की सुविधा के लिए एनईएफटी का उपयोग करती थी। मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) अर्थात मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम विदेशों में प्रतिष्ठित मनी ट्रांसफर कंपनियों के बीच एक तालमेल व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध है, जिन्हें समुद्रपारीय प्रमुख (ओवरसीज प्रिंसिपल) के रूप में जाना जाता है और भारत में एजेंट के माध्यम से यह सेवा डिजिटल और/या मोबाइल प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, जिससे ग्राहक सीमा-पार से धन-प्रेषण कर सकते हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक, सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सहयोग से, धन - प्रेषण सहित सीमा पार लेन-देन की सुविधा के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) प्रणाली की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अन्य अधिकारिताओं तक पहुंच बना रहा है। सभी अधिकारिताओं में तेज़ भुगतान प्रणालियों के बीच सहबद्धता सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं और तेज धन-प्रेषण सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक (रेगुलेटरी) सैंडबॉक्स (आरएस) पहल के तहत दूसरी इकाई (कोहोर्ट) के रूप में सीमा-पार भुगतान का चयन किया ताकि कम लागत, सुरक्षित, सुविधाजनक और पारदर्शी प्रणाली की जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिए नई प्रोद्योगिकियों का लाभ उठाकर सीमा पार भुगतान परिदृश्य को बदलने में सक्षम नवोन्मेषों को बढ़ावा दिया जा सके।

अंत में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां (सीपीएस) अर्थात आरटीजीएस और एनईएफटी, जो चौबीसों घंटे काम करते हैं, के होने से आवश्यक बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध है, जिसका लाभ धन-प्रेषण सहित सीमा-पार से भुगतान की सुविधा के लिए अन्य अधिकारिताओं में समान प्रणालियों के साथ अन्तर्विष्ठ (इंटरफेस) करने के लिए उठाया जा सकता है।

39. प्रवाह

39.1 मुख्य अंतर्दृष्टि: भारत वैयक्तिक धन-प्रेषण अंतर्वाह के मामले में (लीडर) अग्रणी है, वैश्विक धन-प्रेषण का 11.85% हिस्सा इसके द्वारा प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में, भारत को 83 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि का धन-प्रेषण प्राप्त हुआ।

39.2 बेंचमार्क रेटिंग : लीडर

भारत की स्थिति (विप्रेषण में हिस्सा): 1 /21

तालिका 39 : प्रवासी विप्रेषण (धन-प्रेषण) अंतर्वाह

देश	(मिलियन अमरीकी डालर में)				सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में विप्रेषण (2020)	विप्रेषण हिस्सा 2020 (%)
	2017	2018	2019	2020		
ऑस्ट्रेलिया	2,002	1,861	1,752	1,191	0.1	0.17
ब्राज़ील	2,699	2,933	3,214	3,566	0.2	0.51
कनाडा	1,268	1,296	1,312	852	0.05	0.12
चीन	63,876	67,414	68,398	59,507	0.3	8.43
फ्रांस	24,885	26,879	26,174	25,142	0.9	3.56
जर्मनी	15,688	16,888	18,271	17,899	0.5	2.54
हांग कांग एसएआर	437	425	451	458	0.1	0.06
भारत	68,967	78,790	83,332	83,149	3.0	11.79
इंडोनेशिया	8,990	11,215	11,666	9,651	0.8	1.37
इटली	9,742	9,900	10,459	9,711	0.4	1.38
जापान	4,443	4,369	4,389	4,875	0.1	0.69
कोरिया डेमोक्रटिक रिपब्लिक .						0.00
मेक्सिको	32,271	35,768	39,022	42,878	4.1	6.08
रूसी फेडरेशन	8,235	9,287	10,432	9,915	0.6	1.41
सउदी अरब	291	335	334	302	0.0	0.04
सिंगापुर	0	0				0.00
दक्षिणी अफ्रीका	874	929	890	811	0.2	0.11
स्वीडन	3,109	3,074	3,185	3,091	0.4	0.44
तुर्की	1,048	1,122	810	795	0.1	0.11
यूनाइटेड किंगडम	4,306	4,390	4,215	3,247	0.1	0.46
यूनाइटेड स्टेट्स	6,347	6,941	7,163	6,498	0.0	0.92
विश्व	**640,378**	**695,091**	**722,245**	**705,517**		

स्रोत: एचटीटीपीएस://डब्लूडब्लूडब्लू.केएनओएमएडी.ओआरजी/डेटा/रेमिटेंसेस

39.3 विश्लेषण: विप्रेषण सामान्यतया कम मूल्य के व उच्च मात्रा के निधि अंतरण हैं जो मुख्य रूप से उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ताओं को किए जाते हैं। वैयक्तिक विप्रेषण आमतौर पर वह राशि होती है जो प्रवासी अपने मूल देशों में अपने परिवार और दोस्तों को वापस भेजते हैं और आमतौर पर इसे प्रवसन और विकास को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रम की बढ़ती गतिशीलता के साथ, उभरते बाजारों

और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं को विप्रेषण प्रवाह महत्वपूर्ण हैं और देखा गया है कि ये विप्रेषण इन देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आधिकारिक विकास सहायता दोनों से अधिक होते है ।

विप्रेषण अंतर्प्रवाह के मामले में, भारत 83.1 बिलियन अमरीकी डालर (वैश्विक विप्रेषण प्रवाह का 11.79% हिस्सा) के साथ लीडर (अग्रणी) है, इसके बाद चीन 59.5 बिलियन अमरीकी डालर (हिस्सा 8.43%) और मैक्सिको 42.8 बिलियन अमरीकी डालर (हिस्सा 6.08%) आते हैं ।

कोविड जनित महामारी के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में अधिकांशतः सभी देशों में (ब्राजील, हांगकांग, जापान, कोरिया, मैक्सिको को छोड़कर) विप्रेषण अंतर्प्रवाह में गिरावट आई है। भारत में विप्रेषण अंतर्प्रवाह, हालांकि, लचीला रहा और वर्ष 2020 में केवल 0.2% की गिरावट आई।

40. लागत

40.1 मुख्य अंतर्दृष्टि : भारत को विप्रेषण भेजने की लागत अन्य बेंचमार्क देशों की तुलना में कम थी। हालांकि, भारत से विप्रेषण भेजने की लागत रूस और सिंगापुर की तुलना में अधिक थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि, बेंचमार्किंग अभ्यास में चुने गए सभी देशों में विप्रेषण की तुलना करना उचित नहीं हो सकता क्योंकि विप्रेषण मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उद्भव होकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लाभार्थियों को निदेशित होते हैं।

40.2 बेंचमार्क रेटिंग : मजबूत

40.3 विश्लेषण: सीमा-पार से भुगतान बढ़ाने पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की चरण -1 की रिपोर्ट ने उच्च लागत की पहचान वर्तमान सीमा-पार भुगतान व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में की है । रिपोर्ट ने व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों पर उच्च लेन-देन शुल्क के मांग पक्ष पर प्रभाव को उजागर किया है, जो सीमा-पार से भुगतान को हतोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा, आपूर्ति पक्ष के दृष्टिकोण से विभिन्न लागतें शामिल हैं जैसे परिचालन लागत, विनियामक अनुपालन लागत, नेटवर्क लागत, प्रतिनिधि (कोरेस्पोंडेंट) लागत, विदेशी विनिमय (एफएक्स) लागत, चलनिधि (तरलता) लागत, धन-शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) संबंधित लागत, आदि।

विप्रेषण लागत विभिन्न मापदंडों जैसे गंतव्य स्थान, अंतरण की विधि, भुगतान की बुनियादी अवसंरचना, विप्रेषण मूल्य, प्रतिस्पर्धा और विप्रेषक और प्राप्तकर्ता देश में प्रचलित विनियमों से प्रभावित होती है। इसके अलावा, विप्रेषण लागत विनिमय दर मार्जिन, सेवा प्रदाता शुल्क, उद्भव (ऑनलाइन या शाखा), लिखत और शामिल मध्यस्थों के आधार पर, सभी गलियारों (कॉरिडोर) में भिन्न हो जाती है।

सीमा-पार भुगतान की चार चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की परामर्शदात्री रिपोर्ट ने विप्रेषण की लागत के संबंध में टारगेट प्रस्तावित किया है । रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की पुष्टि की है कि वर्ष 2030 तक 200अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की वैश्विक औसत लागत 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें किसी भी कॉरिडोर यह लागत 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

200 अमेरिकी डॉलर विप्रेषण की वैश्विक औसत लागत वर्ष 2021 की पहली तिमाही के 6.38% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया 4.64% की औसत लागत के साथ सबसे कम लागत वाला (प्राप्तकर्ता) क्षेत्र बना हुआ है। यद्यपि भारत के लिए विप्रेषण लागत (प्राप्तकर्ता देश) तुलनात्मक रूप से कम है, तथापि भारत की भुगतान प्रणालियों का लाभ उठाकर, अन्य अधिकारिताओं के साथ सहबद्धता स्थापित कर और विप्रेषण के लिए उपलब्ध चैनलों के लिए एक सस्ता और तेज विकल्प प्रदान कर, लागत को और कम करने के प्रयास जारी हैं ।

तालिका 40: सीमा-पार विप्रेषण की लागत

देश	2020 – तिमाही (क्यू) 3	
	किसी विशिष्ट देश से प्रेषण भेजने की औसत लेन-देन लागत (%) – विप्रेषक (भेजने वाला) देश	किसी विशिष्ट देश को प्रेषण भेजने की औसत लेनदेन लागत (%) – प्राप्तकर्ता देश
ऑस्ट्रेलिया	7.21	
ब्राज़ील	9.77	6.90
कनाडा	6.27	
चीन		8.43
फ्रांस	6.30	
जर्मनी	7.47	
हांग कांग		
भारत	3.96	5.41
इंडोनेशिया		6.57
इटली	6.15	
जापान	10.58	
कोरिया रिपब्लिक	4.74	
रूसी फेडरेशन	1.94	
सउदी अरब	4.80	
सिंगापुर	3.31	
दक्षिणी अफ्रीका	15.05	8.14
स्वीडन	7.93	
तुर्की	11.11	7.26
यूनाइटेड अरब इमिरत	4.10	
यूनाइटेड किंगडम	6.57	
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका	5.14	

स्रोत विश्व बैंक डेटाबैंक – एचटीटीपीएस://डेटाबैंक.वर्ल्डबैंक.ओआरजी/होम.एएसपीएक्स